वर्ष 19
अंक 222
14 पृष्ठ
मूल्य 6 रुपये

सोमवार, 2 नवंबर 2026

कोलकाता, चंडीगढ़, जयपुर, **नई दिल्ली**, भोपाल, मुंबई और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार www.bshindi.com

बिज़नेस स्टैंडर्ड



पृष्ठ 1

रिटेल बिलों की डिजिटल निगरानी

मोहन यादव ▸▸ पृष्ठ 6

मध्य प्रदेश में एमएसएमई के लिए बनेगी अलग कंपनी



अधिक जानकारी के लिए स्कैन करें

SBI MUTUAL FUND
A PARTNER FOR LIFE

निवेश को म्यूज़िक प्लेलिस्ट की तरह क्यों बदलें?

ETFs चुनिए

सरल. विविधता. कम लागत



Exchange-Traded Funds

हर मूड के साथ प्लेलिस्ट बदल जाती है, लेकिन आपको अपना इंवेस्टमेंट बदलने की कोई ज़रूरत नहीं. डीमैट अकाउंट के ज़रिए, आप **एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETFs)** में इंवेस्ट करके व्यापक मार्केट, ग्लोबल मौके, सेक्टर, थीम, सोना या चांदी जैसी कमोडिटी और वैल्यू, लो वोलैटिलिटी या मोमेंटम जैसे इंवेस्टमेंट स्टाइल को कवर करते हैं.

इनका पारदर्शी और कम लागत वाला स्ट्रक्चर आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, जबकि आपका चुना हुआ **ETF** उस इंडेक्स को फ़ॉलो करता है जिसे वह ट्रैक करता है.

SBI म्युच्युअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षण और जागरूकता के लिए एक पहल.

निवेशक केवल पंजीकृत म्युच्युअल फंड्स के साथ ही व्यवहार करें, जिनके विवरण सेबी की वेबसाइट (https://www.sebi.gov.in) पर 'Intermediaries/Market Infrastructure Institutions' के अंतर्गत सत्यापित किए जा सकते हैं. कृपया वन-टाइम केवायसी (नो योर कस्टमर) प्रक्रिया, जिसमें पता, फ़ोन नंबर, बैंक विवरण आदि में परिवर्तन की प्रक्रिया शामिल है, के लिए म्युच्युअल फंड्स की वेबसाइट का संदर्भ लीजिए. यदि निवेशक पंजीकृत मध्यस्थों के जवाबों से असंतुष्ट हैं, तो वे अपनी शिकायतें https://scores.sebi.gov.in पर दर्ज करा सकते हैं. स्कोअर्स (SCORES) आपको सेबी के पास अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करने और उसके बाद उसकी स्थिति देखने की सुविधा देती है.

अपने MFD/RIA से संपर्क करें | विज़िट करें: www.sbimf.com | हमें फ़ॉलो करें:

म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन हैं, योजना से जुड़े सभी दस्तावेज़ों को ध्यान से पढ़ें.

HDFC BANK
We understand your world

प्रधान कार्यालयः एचडीएफसी बैंक हाऊस, सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल (वेस्ट), मुंबई–400013, **क्षेत्रीय कार्यालयः** एचडीएफसी बैंक लि., विशेष प्रचालन विभाग, गुलाब भवन, भूतल, 6, बहादुर शाह जफर मार्ग, दिल्ली–110002

शुद्धिपत्र

यह शुद्धिपत्र को ''बिज़नेस स्टैंडर्ड'' समाचार पत्र के (अंग्रेजी और हिंदी) संस्करण में दिनांक 15.10.2026 को प्रकाशित **अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी हेतु सार्वजनिक नोटिस** के संदर्भ में है। अधोल्लिखित संपत्तियों के संबंध में ईएमडी प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय और ई–नीलामी की तिथि/समय को अब बढ़ा दिया गया है और अब इसे निम्नानुसार पढ़ा जाए:

मद नं. 1 आवासीय संपत्ति अर्थात **संपत्ति खसरा नं. 195 (खाता खतौनी नंबर 187, मिन) मौजा नदेही, तहसील जसपुर, जिला उधम सिंह नगर, विक्रय विलेख दिनांक 10.08.2018 बही नं. 1 जिल्द 641 पृष्ठ 215 से 226 क्रमांक 2300 उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर और सीमाएँ निम्नवत् हैं:– पूर्वः सड़क 24 मीटर, पश्चिमः शेष क्षेत्र (शेष आराजी मुकीर), उत्तरः शेष क्षेत्र (शेष आराजी मुकीर), दक्षिणः सड़क 18 मीटर चौड़ी**

ईएमडी (रु. 12,80,000/–) प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31.10.2026 से बढ़ाकर 17.11.2026 समय अप. 4.00 तक कर दी गई है और जबकि ई–नीलामी की तिथि **03.11.2026 से बढ़ाकर 19.11.2026 (समय पूर्वा. 10:30 से पूर्वा. 11.30) तक** कर दी गई है।

ई–नीलामी के नियमों और शर्तों में कोई अन्य परिवर्तन नहीं है, जो प्रकाशन के अंत में वेबसाइट www.hdfcbank.com और www.bankeauctions.com पर दिए गए हैं।

दिनांकः 31.10.2026 **प्राधिकृत अधिकारी,**
स्थानः दिल्ली **एचडीएफसी बैंक लि.**

नैनीताल बैंक
दि नैनीताल बैंक लि.

[पंजीकृत कार्यालय : जी०बी० पंत रोड़, मल्लीताल, नैनीताल, उत्तराखण्ड-263001]
CIN No. U65923U R1922PLC000234, website: www.nainitalbank.bank.in
e-mail ID: secretarial@nainitalbank.co.in, Phone: 05942-233739

कंपनी के शेयरधारकों को सूचना

शेयरों को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (IEPF) खाते में स्थानांतरित करने के लिए
(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के अनुसार)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) की आवश्यकताओं के अनुसार, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, हस्तांतरण और वापसी) नियम, 2016 (षनियमष), जैसा कि संशोधित है, कंपनी को उन शेयरों को स्थानांतरित करना आवश्यक है, जिनके संबंध में लाभांश लगातार सात वर्षों की अवधि के लिए अवैतनिक या दावा रहित रहता है, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित आईईपीएफ खाते में।

वे सभी शेयरधारक जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए लगातार सात वर्षों तक अपने लाभांश का नकदीकरण नहीं किया है और जिनके शेयर **IEPF** खाते में स्थानांतरित किए जाने योग्य हैं, उनकी जानकारी कंपनी की वेबसाइट ***https://www.nainitalbank.bank.in/english/Dividend.aspx*** पर उपलब्ध है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त सूचना के अनुसार, दावा न किए गए लाभांश राशि और शेयरों का दावा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज कंपनी के सचिवालय विभाग को भेजें। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि शेयरधारकों द्वारा वैध दावा प्राप्त न होने की स्थिति में, कंपनी उक्त नियमों की आवश्यकता के अनुसार बिना किसी और सूचना के उक्त शेयरों को **IEPF** खाते में स्थानांतरित कर देगी। कृपया ध्यान दें कि उक्त नियमों के अनुसार, आईईपीएफ को हस्तांतरित अघोषित लाभांश राशि और शेयरों के संबंध में कंपनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। कृपया ध्यान दें कि ऐसे हस्तांतरण के बाद, शेयरधारक/दावेदार आईईपीएफ प्राधिकरण से लाभांश सहित हस्तांतरित शेयरों का दावा कर सकते हैं, जिसके लिए विवरण ***www.iepf.gov.in*** पर उपलब्ध हैं। इस मामले पर किसी भी जानकारी/स्पष्टीकरण के लिए, संबंधित शेयरधारक/दावेदार कंपनी को ***secretarial@nainitalbank.co.in*** पर या आरटीए, मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31–32, गाचीबोवली फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद – 500 032, टोल फ्री नंबर – 1800 309 4001, ई–मेल आईडी – ***einward.ris@kfintech.com*** पर लिख सकते हैं।

स्थान : नैनीताल **द नैनीताल बैंक लिमिटेड**
दिनांक : 02 नवम्बर, 2026 **(विवेक साह),** कम्पनी सचिव

बजाज फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : मारफत बजाज ऑटो लिमिटेड कॉम्प्लेक्स, मुंबई–पुणे रोड, अकुर्दी, पुणे – 411035
शाखा कार्यालय : बजाज फाइनेंस लिमिटेड, बांदा/ शाहजहांपुर

(परिशिष्ट–IV के सहपठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमों ,2002 के नियम 8(1)के तहत)

जबकी, अधोहस्ताक्षरी **बजाज फाइनेंस लिमिटेड (बीएफएल)** के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजीकृत डाक (''सूचना'') द्वारा एक मांग सूचना निर्गमित की जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि को चुकाने के लिए उधारकर्ताओं/सह–उधारकर्ता(ओं)को उक्त सूचना की प्राप्ती की दिनांक से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने का आहवान किया गया।

निम्न नामित उधारकर्ताओं/बंधककर्ताओं/गारंटरों राशि चुकाने में विफल रहे है, एतद् द्वारा उधारकर्ताओं/सह–उधारकर्ताओं/गारंटरों और सामान्य रूप से जनता को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर **भौतिक कब्जा** प्राप्त कर लिया ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि उक्त संपत्ति से व्यवहार न किया जाए और संपत्ति के साथ कोई भी व्यवहार निम्न उल्लेखित राशि के साथ उस पर संविदात्मक दर पर भविष्य के ब्याज साथ **बजाज फाइनेंस लिमिटेड** के प्रभार के अधीन होगा।

उपलब्ध समय के संबंध में, प्रत्याभूत परिसंपत्ति को छुड़ाने के लिए, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों पर आकर्षित किया जाता है।

ऋण खाता सं./ उधारकर्ता(ओं)/बंधककर्ता(ओं)/ गारंटर(ओं) के नाम और पता	प्रत्याभूत अचल संपत्ति का विवरण	धारा 13(2) की मांग सूचना की दिनांक और धारा 13(2) की राशि कब्जे की दिनांक
LAN : P79PFB5551078 और P4C0PFB9813174 **1. ओम पेस्टीसाइड अपने मालिक रोहित गंगवार के माध्यम से** निवासी मोहद्दीनपुर चौराहा के पास, मोहिद्दीनपुर बांदा, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश 242042, संपर्क: 79855246404, ईमेल आईडी: gangwarr197@gmail.com **इसके अतिरिक्त :** निवासी मोहद्दीनपुर चौराहा के पास, मोहिद्दीनपुर के पास, तहसील पुवायान मोहिद्दीनपुर बांदा,बांदा, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश 242042, संपर्क: 79855246404, ईमेल आईडी: gangwarr197@gmail.com, **इसके अतिरिक्त :** अराजी सं. 152एमआई, ग्राम ताजपुर, परगना तहसील पुवायान, जिला शाहजहांपुर उ.प्र. 242042 **2.श्रीदेवी उर्फ जमुना देवी पत्नी सत्यवीर गंगवार** निवासी गायत्री नगर बांदा शाहजहांपुर उ.प्र. 242042, संपर्क: 79855246404, ईमेल आईडी: gangwarr197@gmail.com, **3. रोहित गंगवार पुत्र सत्यवीर गंगवार,** निवासी गायत्री नगर बांदा शाहजहांपुर उ.प्र. 242042, संपर्क: 79855246404, ईमेल आईडी: gangwarr197@gmail.com	अराजी सं. 1520एमआई, ग्राम ताजपुर, परगना तहसील पुवायान, जिला शाहजहांपुर उ.प्र. 242042 , संग साझा क्षेत्र में समानुपातिक हिस्सा (मापक क्षेत्र 60.40 वर्ग मीटर) का संपूर्ण व सर्वांगीण भाग। **सीमांकन : लीगल दस्तावेजों के अनुसार :** पूर्व : टीका राम का मकान, पश्चिम : मिन्द्री देवी का प्लॉट, उत्तर : अनिर्मित सड़क, दक्षिण : पॉवर हाऊस की सीमा, **साइट विजिट अनुसार :** पूर्व : टीका राम का मकान, पश्चिम : ग्रहाक का प्लॉट (मिन्द्री देवी द्वारा विक्रय), उत्तर : 12 फुट चौड़ी मिट्टी सड़क, दक्षिण : पॉवर हाऊस की सीमा	20.08.2025 रु.20,97,447/– (रुपये बीस लाख सत्तानबे हजार चार सौ सैंतालीस मात्र) कब्जा दिनांक: 31.10.2026

दिनांक : 31.10.2026, स्थान :उत्तर प्रदेश **हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी, बजाज फाइनेंस लिमिटेड**

सीएफएम एसेट रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

कॉरपोरेट कार्यालयः पहली मंजिल, वेकफील्ड हाउस, स्प्रोट रोड, बल्लार्ड एस्टेट, मुंबई-400038

कब्जा सूचना
(अचल सम्पत्ति के लिए)

परिशिष्ट IV **नियम 8(1) के साथ पठित**

चूंकि, सीएफएम एसेट रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (सीएफएमएआरसी ट्रस्ट-219 के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत) के अधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूत हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (54 ऑफ 2002) के अधीन तथा धारा 13(12), 13(2) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 3 के तहत मांग सूचना जारी की गई थी, जिसमें कथित सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित रकम चुकता करने को कहा गया था। आगे, सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 5 के प्रावधानों के अधीन ऑक्सीजो फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड एवं सीएफएम एसेट रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के बीच दिनांक 23-03-2026 के पंजीकृत हस्तांतरण अनुबंध के मार्फत ऑक्सीजो फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड ने ऊपर उल्लेखित ऋण खाते की सम्पूर्ण बकाया रकम के सभी अधिकारों, स्वामित्व तथा हित के साथ अंतर्निहित प्रतिभूतियों को सीएफएम एसेट रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में हस्तांतरित कर दिया है। संबंधित पक्षों के ब्यौरा के साथ गिरवी रखी गई सम्पत्ति पर सीएफएमएआरसी द्वारा कब्जा का विवरण नीचे उल्लेखित है:-

ग्राहक (कर्जदार(ों)/सह-कर्जदार(ों) तथा गारंटर(ों)/ साझेदारों/गिरवीदाता(ओं) का नाम	मांग सूचना की तारीख एवं रकम रु. में	कब्जा की तारीख
आजाद सिंह (कर्जदार), **भंवर सिंह** (सह-कर्जदार), **नम्रता भटनागर** (सह-कर्जदार), **ऋण खाता सं.: OXYTL01PCX7**	मांग सूचना की तारीखः **13-06-2026, रु. 5,43,464/-** (रुपये पांच लाख तैंतालीस हजार चार सौ चौसठ मात्र) दिनांक 26-05-2026 तक	28-10-2026
गिरवी रखी गई सम्पत्तिः गाटा संख्या 418, ग्राम जड़वड़ भुम्भा, संभलहेड़ा, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, 251315। सीमाएँः उत्तरः ज्ञानेन्द्र का टिन शेड, दक्षिणः 12 फुट चौड़ी सड़क, पूर्वः मनवीर का मकान, पश्चिमः मंगू सिंह की भूमि		
कोमल शर्मा (कर्जदार), **शारदा** (सह-कर्जदार), **विपिन कुमार शर्मा** (सह-कर्जदार), **ऋण खाता सं.: OXYTL01JH9M**	मांग सूचना की तारीखः **13-06-2026, रु. 4,85,579/-** (रुपये चार लाख पच्चासी हजार पांच सौ उनासी मात्र) दिनांक 26-05-2026 तक	28-10-2026
गिरवी रखी गई सम्पत्तिः ग्राम नायडू, परगना हस्तिनापुर, तहसील मवाना, मेरठ, मेरठ, उत्तर प्रदेश, 250401। सीमाएँः उत्तरः श्रीमती शारदा पत्नी श्री रामेंद्र (उर्फ राजेंद्र) का मकान, दक्षिणः श्री श्रीपाल पुत्र श्री दलीप का मकान, पूर्वः 9 फुट चौड़ा रास्ता, पश्चिमः 16.1/2 फुट चौड़ा रास्ता		
मेरुन्नीशा (कर्जदार), **इरशाद** (सह-कर्जदार), **ऋण खाता सं.: OXYTL01URH7**	मांग सूचना की तारीखः **13-06-2026, रु. 4,28,667/-** (रुपये चार लाख अट्ठाईस हजार छह सौ सड़सठ मात्र) दिनांक 26-05-2026 तक	28-10-2026
गिरवी रखी गई सम्पत्तिः खसरा संख्या 117, 118, ग्राम सरबराहपुर उर्फ तुरहेड़ी परगना भुम्मा संभलहेड़ा, मुजफ्फनगर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, 251314। सीमाएँः उत्तरः इंतजार का खेत, दक्षिणः 12 फीट चौड़ी सड़क, पूर्वः 12 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिमः सदाब का प्लॉट		
मो. आरिफ (कर्जदार), **रिहाना** (सह-कर्जदार), **ऋण खाता सं.: OXYTL01N65K**	मांग सूचना की तारीखः **13-06-2026, रु. 3,67,680/-** (रुपये तीन लाख सड़सठ हजार छह सौ अस्सी मात्र) दिनांक 26-05-2026 तक	29-10-2026
गिरवी रखी गई सम्पत्तिः खसरा सं.-595, मोहल्ला खेड़ापट्टी, ग्राम सुजडू, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, 251003। सीमाएँः उत्तरः हाजी गुफरान का मकान, दक्षिणः शब्बीर अहमद का प्लॉट, पूर्वः 15 फुट चौड़ा रास्ता, पश्चिमः कब्रिस्तान की संपत्ति।		
मुकुल तोमर (कर्जदार), **सुनीता** (सह-कर्जदार), **यशपाल** (सह-कर्जदार), **ऋण खाता सं.: OXYTL01TB7R**	मांग सूचना की तारीखः **13-06-2026, रु. 6,25,193/-** (रुपये छह लाख पच्चीस हजार एक सौ तिरानवे मात्र) दिनांक 26-05-2026 तक	29-10-2026
गिरवी रखी गई सम्पत्तिः खसरा सं. 243, ग्राम नगला खेप्पड़, परगना भुम्मा संभलहेड़ा, तहसील जनसत, जिला मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, 251314। सीमाएँः उत्तरः अनुराग का मकान, दक्षिणः बबलू का मकान, पूर्वः 10 फुट चौड़ा रास्ता, पश्चिमः नरेंद्र का मकान		
सुनीता (कर्जदार), **सोनू** (सह-कर्जदार), **ऋण खाता सं.: OXYTL01U1RGX**	मांग सूचना की तारीखः **13-06-2026, रु. 6,50,657/-** (रुपये छह लाख पचास हजार छह सौ सनतावन मात्र) दिनांक 26-05-2026 तक	29-10-2026
गिरवी रखी गई सम्पत्तिः खसरा सं.197के एवं 221, ग्राम आलमगीरपुर फरीदपुर, परगना एवं तहसील सरधाना, मेरठ, मेरठ, उत्तर प्रदेश, 250342। सीमाएँः उत्तरः सतपाल की जगह, दक्षिणः उपहारदाता सोनू की जगह, पूर्वः ओमपाल का मकान, पश्चिमः 15 फुट चौड़ा रास्ता		
विकास कुमार (कर्जदार), **कोमल** (सह-कर्जदार), **शकुंतला** (सह-कर्जदार), **ऋण खाता सं.: OXYTL01PKPK1**	मांग सूचना की तारीखः **13-06-2026, रु. 4,71,141/-** (रुपये चार लाख इकहत्तर हजार एक सौ इकतालीस मात्र) दिनांक 26-05-2026 तक	27-10-2026
गिरवी रखी गई सम्पत्तिः खसरा सं. 1195एमआई, ग्राम अमीरपुर, नगौला, परगना सरसावा, तहसील एवं जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश, 245101। सीमाएँः उत्तरः गोपाल का मकान (39'-5"), दक्षिणः रामकरण का मकान (39'-5"), पूर्वः 4 फुट चौड़ा रास्ता (18'-6"), पश्चिमः चंदू का मकान (20'-6")		
बेबी सिंह (कर्जदार), **जुगलेश** (सह-कर्जदार), **ऋण खाता सं.: OXYTL01YTTBF**	मांग सूचना की तारीखः **13-06-2026, रु. 4,79,911/-** (रुपये चार लाख उनासी हजार नौ सौ ग्यारह मात्र) दिनांक 26-05-2026 तक	31-10-2026
गिरवी रखी गई सम्पत्तिः खसरा सं. 360, ग्राम चुबका, तहसील अमरोहा, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश, 244221। सीमाएँः उत्तरः 2.43 मीटर चौड़ा रास्ता, दक्षिणः 3.04 मीटर चौड़ा रास्ता, पूर्वः 2.43 मीटर चौड़ा रास्ता, पश्चिमः दानकर्ता बेबी सिंह का मकान।		

कर्जदारों द्वारा कथित रकम का चुकता करने में असफल होने के कारण एतद्द्वारा कर्जदारों तथा जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित कथित नियमों के नियम 8 के अधीन "कब्जा की तारीख" कॉलम में नीचे उल्लेखित तारीख को यहां निम्नलिखित सम्पत्ति पर **प्रतीकात्मक कब्जा** कर लिया है।

विशेष तौर पर ऊपर उल्लेखित कर्जदारों तथा आम तौर पर जनसाधारण को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि इस संपत्ति से संबंधित कोई सौदा न करें तथा इस संपत्ति से संबंधित कोई भी सौदा इस सूचना में उल्लेखित रकम के साथ यहां ऊपर किए गए विवरण में दर्शाई गई बकाया रकम की तिथि की स्थिति की ठीक अगली तारीख से सम्पूर्ण भुगतान तथा/अथवा वसूली की तारीख तक अनुबंधकीय दर पर ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत एवं शुल्कों इत्यादि की रकम के लिए **सीएफएम एसेट रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड** के प्रभार का विषय होगा। आगे प्रत्याभूत सम्पत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

कृपया ध्यान दें सम्पत्ति का विवरण यहां ऊपर उल्लेखित है।

दिनांक : 02.11.2026 **अधिकृत अधिकारी, सीएफएम एसेट रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड**
स्थान : दिल्ली/एनसीआर **(सीएफएमएआरसी ट्रस्ट-219 के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत)**

Look beyond the market noise

Track companies, market movements, and market signals capturing investor attention daily with Stocks in the News in Business Standard.

Business Standard
Insight Out

To book your copy, SMS **reachbs** to **57575** or email **order@bsmail.in**

businessstandard bsindia business.standard business-standard.com

वर्ष 19
अंक 222
14 पृष्ठ
मूल्य 6 रुपये

सोमवार, 2 नवंबर 2026

कोलकाता, चंडीगढ़, जयपुर, **नई दिल्ली**, भोपाल, मुंबई और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार www.bshindi.com

बिज़नेस स्टैंडर्ड



अजय खंडेलवाल ▸▸ पृष्ठ 10

कुछ क्षेत्रों में सिमटी है आय वृद्धि, शेयर विशेष पर दांव की सलाह

एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ▸▸ पृष्ठ 12

तेजस, एएमसीए वायु सेना के लिए शीर्ष प्राथमिकता



एक नज़र

शुद्ध जीएसटी संग्रह 25.6 फीसदी बढ़ा

आयात से मिलने वाले कर राजस्व में तेज बढ़ोतरी की मदद से केंद्र और राज्य सरकारों का शुद्ध माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह अक्टूबर में सालाना आधार पर 25.6 फीसदी बढ़कर 2.03 लाख करोड़ रुपये रहा। यह चालू वित्त वर्ष में दर्ज की गई अब तक की सबसे तेज वृद्धि दर है। वित्त मंत्रालय द्वारा रविवार को जारी अंतरिम आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। चालू वित्त वर्ष में सकल जीएसटी संग्रह में भी सबसे तेज वृद्धि दर्ज की गई जो सालाना आधार पर 22.9 फीसदी बढ़कर 2.31 लाख करोड़ रुपये रहा। पृष्ठ 4

यात्री वाहनों की थोक बिक्री 12.4% बढ़ी

अक्टूबर महीने के दौरान यात्री वाहनों की घरेलू बाजार में थोक बिक्री सालाना आधार पर 12.4 फीसदी बढ़कर 5,28,384 वाहन रही। मारुति सुजूकी ने अक्टूबर में 2,12,384 कारें बेचीं। यह पिछले साल के इसी महीने की बिक्री के मुकाबले 20.5 फीसदी अधिक है। टाटा मोटर्स ने 73,894 वाहन बेचे। महिंद्रा ऐंड महिंद्रा की बिक्री भी बढ़कर 73,338 वाहनों की रही। ह्युंडै मोटर ने 62,799 वाहन बेचे। पृष्ठ 2

प्रिय पाठको

आपके प्रिय समाचार पत्र बिज़नेस स्टैंडर्ड में आज से प्रतिदिन दो नए पृष्ठ शामिल किए जा रहे हैं। पहला पृष्ठ म्यूचुअल फंड पर केंद्रित है। हमारा उद्देश्य आपको म्यूचुअल फंडों के हर बारीक पहलू से रूबरू कराना है। इस पृष्ठ पर आपको मिलेंगे विभिन्न फंडों का निष्पक्ष विश्लेषण, जोखिम प्रबंधन के तरीके और बाजार के विशेषज्ञों की राय। दूसरे पृष्ठ में प्रदेशों के प्रमुख आर्थिक एवं व्यापारिक समाचारों, खासकर लघु एवं मझोले उद्योगों (एसएमई) से जुड़ी खबरों को स्थान दिया गया है। इसमें कमोडिटी बाजार की प्रमुख खबरें भी प्रकाशित की जाएंगी।

रिटेल बिलों की डिजिटल निगरानी

अगले साल अप्रैल से होगा परीक्षण, जीएसटी चोरी रोकने में मिलेगी मदद

मोनिका यादव
नई दिल्ली, 1 नवंबर

कर नियमों का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए माल एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिकारी 1 अप्रैल, 2027 से एक पायलट परियोजना शुरू करने की योजना बना रहे हैं। इसके तहत दुकानों और व्यवसायों द्वारा आम खुदरा ग्राहकों को जारी किए गए बिलों (इनवॉइस) का विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज किया जाएगा। यह परियोजना चुनिंदा व्यावसायिक क्षेत्रों पर लागू होगी। घटनाक्रम से अवगत दो अधिकारियों ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि इस कदम से कर अधिकारी उन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में होने वाले खुदरा लेनदेन का ब्योरा हासिल कर सकेंगे, जहां कर चोरी की आशंका अधिक रहती है। इससे यह आकलन करने में मदद मिलेगी कि कारोबारी अपनी बिक्री की सही जानकारी दे रहे हैं और उचित मात्रा में जीएसटी का भुगतान कर रहे हैं या नहीं।

वर्तमान में जिन कारोबार की सालाना बिक्री 5 करोड़ रुपये से अधिक है, उन्हें अन्य व्यवसायों को जारी किए गए बिलों (इनवॉइस) को सरकार द्वारा निर्धारित पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज करना होता है। हालांकि इसमें कुछ छूट भी दी गई है।



अजय मोहंती

बढ़ेगी पारदर्शिता

- रिटेल ई-इनवॉइसिंग का चुनिंदा क्षेत्रों में पहले स्वैच्छिक परीक्षण होगा
- जीएसटी परिषद ने सितंबर 2024 में स्वैच्छिक ट्रायल का दिया था प्रस्ताव

- इसका उद्देश्य जीएसटी चोरी और बिक्री कम दिखाने पर रोक लगाना है
- इलेक्ट्रॉनिक बिल से विदेशी पर्यटकों को जीएसटी रिफंड में होगी सहूलियत
- बैंक, बीमा कंपनियों और एनबीएफसी के बी2बी को भी ई-इनवॉइसिंग के दायरे में लाने पर हो रहा विचार

इस व्यवस्था को 'ई-इनवॉइसिंग' कहा जाता है। अब इसका दायरा बढ़ाकर अंतिम उपभोक्ताओं को की जाने वाली बिक्री तक किया जाएगा। इसे कर अनुपालन बढ़ाने की दिशा में अगला महत्त्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

वर्तमान में कारोबारी जीएसटी रिटर्न में अपनी कुल बिक्री की जानकारी देते हैं और उन्हें प्रत्येक खुदरा लेनदेन का अलग-अलग ब्योरा देने की जरूरत नहीं होती है। अधिकारियों में से एक ने कहा कि खुदरा लेनदेन के लिए भी ई-इनवॉइसिंग व्यवस्था अनिवार्य होने से कर अधिकारी व्यक्तिगत बिलों का कारोबारियों द्वारा कर रिटर्न में घोषित बिक्री से मिलान कर सकेंगे।

सितंबर 2024 में अपनी 54वीं बैठक में जीएसटी परिषद ने चुनिंदा क्षेत्रों और राज्यों में ग्राहकों के बिलों की इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग का स्वैच्छिक परीक्षण करने की सिफारिश की थी।

परिषद की बैठक के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध ब्योरे से पता चलता है कि शुरुआत में इसे स्वैच्छिक आधार पर लागू करने और बाद में कर चोरी की आशंका वाले क्षेत्रों में अनिवार्य बनाने का विचार है। बैठक में रेस्तरां को उन क्षेत्रों में शामिल किया गया था जहां खुदरा ई-इनवॉइसिंग लागू की जा सकती है।

परिषद ने खुदरा क्षेत्र में इस व्यवस्था के संभावित लाभों को भी स्वीकार किया था। इनमें बेहतर कर अनुपालन, कागजी बिलों से बचने के कारण पर्यावरण को होने वाला फायदा और लागत में कमी शामिल हैं। ग्राहक को ई-इनवॉइस उसके मोबाइल फोन पर मिलेगा।

अधिकारियों ने कहा कि सरकार अब इस पायलट परियोजना को आगे बढ़ाने की इच्छुक है।

इस खबर पर टिप्पणी के लिए 23 अक्टूबर को ही वित्त मंत्रालय को हमने ईमेल भेजा था लेकिन खबर लिखे जाने तक कोई जवाब नहीं मिला।

उक्त अधिकारी ने कहा कि फिलहाल बैंक, बीमा कंपनियों और एनबीएफसी को अन्य कारोबारियों के साथ होने वाले लेनदेन की ई-इनवॉइसिंग से छूट प्राप्त है। हालांकि केंद्र और राज्य सरकारें इन संस्थाओं के कारोबारी लेनदेन के बिलों को भी इस अनिवार्यता के दायरे में लाने पर विचार कर रही है। (शेष पृष्ठ 9)

दूरसंचार कंपनियों ने की आईटीसी बढ़ाने की मांग

गुलवीन औलख
नई दिल्ली, 1 नवंबर

भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने नियामक से अंतरराष्ट्रीय टर्मिनेशन शुल्क (आईटीसी) बढ़ाने के लिए अलग से विचार-विमर्श करने की मांग की है। उन्होंने इसे मौजूदा अधिकतम 0.65 रुपये प्रति मिनट से बढ़ाकर कम से कम 5 रुपये प्रति मिनट करने को कहा है। आईटीसी वह शुल्क है जिसका भुगतान कोई विदेशी दूरसंचार कंपनी भारतीय नेटवर्क पर आने वाली कॉल के लिए करती है।

उद्योग संगठन सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) के जरिये कंपनियों ने कहा है कि पिछले एक साल के दौरान रुपये में गिरावट के कारण उनकी वास्तविक कमाई प्रभावित हुई है। वैश्विक ऑपरेटरों द्वारा आईटीसी का भुगतान अमेरिकी डॉलर में होता है। शुल्क बढ़ने से कंपनियां असमान टर्मिनेशन शुल्क के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई कर सकेंगी।

विदेशी दूरसंचार सेवा प्रदाता भारतीय ऑपरेटरों को 0.35 से 0.65 रुपये प्रति मिनट भुगतान करते हैं। मगर भारतीय दूरसंचार कंपनियों को विदेशी नेटवर्क पर कॉल के लिए 3 से 3.5 रुपये प्रति मिनट शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। उद्योग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, इन दोनों दरों में अंतर काफी बड़ा है। भारत में आने वाली कॉल की संख्या बाहर जाने वाली कॉल से काफी अधिक है। इसलिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्रधिकरण (ट्राई) का हस्तक्षेप जरूरी है।

दूरसंचार कंपनियों का कहना है कि आईटीसी व्यवस्था का उस व्यापक टर्मिनेशन शुल्क व्यवस्था से कोई संबंध नहीं है जिसकी समीक्षा ट्राई नवंबर 2025 से कर रहा है। इसलिए आईटीसी शुल्क में तत्काल बदलाव करना जरूरी है। (शेष पृष्ठ 12)

शुल्क का मामला

- रुपये में गिरावट के बीच वैश्विक बराबरी पर जोर
- आईटीसी शुल्क 5 रुपये करने की मांग
- बीएसएनएल भी शुल्क बढ़ाने के पक्ष में
- ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा अतिरिक्त बोझ



नया संवत, नई शुरुआत : निवेशकों के लिए पोर्टफोलियो रीसेट का मौका

बिज़नेस स्टैंडर्ड हिंदी लेकर आया है एक विशेष वेबिनार, जहाँ म्युचुअल फंड, शेयर बाज़ार और सोने से जुड़े अहम सवालों पर चर्चा करेंगे अपने क्षेत्र के अनुभवी विशेषज्ञ। समझिए बाज़ार का बदलता मिज़ाज, निवेश के विकल्प और आपके अगले निवेश फ़ैसले से जुड़े ज़रूरी पहलू।

मुख्य वक्ता: वेंकट एन चलसानी, मुख्य कार्याधिकारी, एम्फी

दिनांक: 4 नवंबर 2026

समय: 12 pm

In association with ADITYA BIRLA CAPITAL MUTUAL FUNDS

रजिस्टर करें।

सेशन 1 12:15 pm — *वैश्विक चुनौतियों के बीच निवेशकों के लिए कमाई और निवेश के नए विकल्प*

मॉडरेटर: **आशुतोष ओझा** और **खुशबू तिवारी**



वेंकट एन चलसानी,
मुख्य कार्याधिकारी, एम्फी



राहुल सिंह,
सीआईओ (इक्विटीज), टाटा म्युचुअल फंड



जितेंद्र श्रीराम,
सीनियर फंड मैनेजर (इक्विटीज), बड़ौदा बीएनपी पारिबा म्युचुअल फंड

सेशन 2 1 pm — *नया संवत, नई उम्मीदें: शेयर बाजार में निवेशकों का भरोसा और रिटर्न की संभावनाएं*

मॉडरेटर - **पुनीत वाधवा**



हरेंद्र कुमार,
प्रबंध निदेशक, इलारा सिक्योरिटीज



जिग्नेश देसाई,
सीईओ - इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, सेंट्रम ब्रोकिंग

सेशन 3 1:55 pm — *बाजार की हलचल में क्या सोना अब भी निवेशकों के लिए 'गोल्डन अपॉर्च्युनिटी' है?*

मॉडरेटर: **ऋषभ कृष्ण सक्सेना**



अपूर्व शेठ,
मार्केट पर्सपेक्टिव्स और रिसर्च हेड, सैमको सिक्योरिटीज



बिज़नेस स्टैंडर्ड

बेहतर बिज़नेस वो, जो आपकी भाषा में हो

@bshindinews @bshindinews bs.hindi hindi.business-standard.com

संक्षेप में

सोलेक्स एनर्जी अमेरिकी बाजार में उतरेगी

घरेलू कंपनी सोलेक्स एनर्जी ने वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के उद्देश्य से अमेरिका में सौर मॉड्यूल और सौर सेल विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की योजना बनाई है। यह 2030 तक कंपनी की 1.5 अरब डॉलर के निवेश की योजना का हिस्सा होगा। कंपनी के चेयरमैन चेतन शाह ने कहा कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार है। हालांकि, चीन से आयात पर भारी डंपिग रोधी शुल्क लगाए जाने के कारण भारत कम लागत वाले विकल्प का एकमात्र व्यवहार्य आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है। अमेरिका में विस्तार की योजना के बारे में पूछे जाने पर शाह ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि सोलेक्स एनर्जी मुख्य रूप से स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े उपकरणों की वैश्विक स्तर पर भारी मांग का लाभ उठाने और चीनी आपूर्तिकर्ताओं के मुकाबले खुद को एक भरोसेमंद एवं किफायती विकल्प के रूप में स्थापित करने के लिए अमेरिकी बाजार में विस्तार करना चाहती है। सोलेक्स एनर्जी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (एमडी) शाह ने कहा, 'अमेरिका में काफी संभावनाएं हैं। *भाषा*

लोढ़ा समूह गुरुग्राम में कार्यालय परिसर बनाएगी

रियल एस्टेट क्षेत्र की कंपनी लोढ़ा डेवलपर्स ने दिल्ली-एनसीआर के संपत्ति बाजार में कदम रखते हुए गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर करीब 1,200 करोड़ रुपये के निवेश से प्रीमियम कार्यालय परिसर विकसित करने की योजना बनाई है। मुंबई मुख्यालय वाली कंपनी की यह एनसीआर में पहली परियोजना होगी। पिछले साल लोढ़ा डेवलपर्स ने गुरुग्राम में दो परियोजनाओं के लिए एमआरजी समूह के साथ संयुक्त विकास करार किया था। इनमें से एक परियोजना वाणिज्यिक और एक आवासीय है। लोढ़ा डेवलपर्स के कार्यकारी निदेशक (वित्त) सुशील मोदी ने बताया कि कंपनी ने हाल में 1.2 एकड़ में फैली अपनी वाणिज्यिक परियोजना 'लोढ़ा पैंथियन' पेश की है। *भाषा*

वाहन बिक्री की रफ्तार तेज

त्योहारी मांग, जीएसटी कटौती, आयकर राहत और कम ब्याज दरों ने दिया सहारा

दीपक पटेल
नई दिल्ली, 1 नवंबर

भारत में अक्टूबर महीने के दौरान यात्री वाहनों (पीवी) की घरेलू थोक बिक्री सालाना आधार पर 12.4 प्रतिशत बढ़कर 5,28,384 वाहन हो गई। इसमें त्योहारी सीजन की मजबूत मांग, पिछले साल लागू की गई जीएसटी दर कटौती, आयकर में राहत और अपेक्षाकृत कम ब्याज दरों का योगदान रहा।

मारुति सुजूकी इंडिया के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी (मार्केटिंग ऐंड सेल्स) पार्थो बनर्जी ने रविवार को एक वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इन कारणों से वाहन खरीदना अधिक किफायती हो गया और ग्राहक भी दोपहिया वाहनों से कारें खरीदने के लिए प्रोत्साहित हुए। देश की सबसे बड़ी यात्री वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजूकी इंडिया लिमिटेड (एमएसआईएल) ने अक्टूबर में 2,12,384 घरेलू वाहनों की थोक बिक्री दर्ज की। यह पिछले साल के इसी महीने की 1,76,318 वाहनों की बिक्री के मुकाबले 20.5 प्रतिशत ज्यादा है। कंपनी ने छोटी कारों, स्पोर्ट यूटिलिटी वाहनों (एसयूवी), सिडैन और मल्टी-पर्पज वाहनों (एमपीवी) की मजबूत मांग की भी बात कही।

बनर्जी ने कहा कि मांग को तीन कारकों से समर्थन मिला है - जीएसटी 2.0, पहले घोषित आयकर राहत और भारतीय रिजर्व बैंक की अपेक्षाकृत कम रीपो दर। रीपो दर वह ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंकों को पैसा उधार देता है। हालांकि आरबीआई ने हाल में इसे 25 आधार अंक बढ़ा दिया है, लेकिन बनर्जी ने कहा कि यह अभी भी पहले के स्तर से 75 आधार अंक नीचे है। बनर्जी ने कहा कि मांग लगातार ऊंची रहने के कारण डीलरों पर कम स्टॉक चिंता का मसला है। अक्टूबर के अंत में मारुति के डीलर नेटवर्क में केवल 12 दिन का स्टॉक था, जबकि रिटेल बिक्री, होलसेल डिस्पैच से अधिक रही। नेटवर्क स्टॉक का मतलब उन वाहनों से है जो ग्राहकों को बेचने के लिए डीलरों के पास होते हैं। उन्होंने कहा, 'अगर आप मुझसे पूछें, तो यह चिंता की बात है।'

मारुति सजुकी के कॉरपोरेट मामलों के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राहुल भारती ने कहा कि कंपनी मांग को पूरा करने के लिए लगातार उत्पादन बढ़ा रही है। इसका औसत दैनिक उत्पादन वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में 9,100 वाहन से बढ़कर दूसरी तिमाही में 9,600 और अक्टूबर में 10,100 वाहन हो गया।

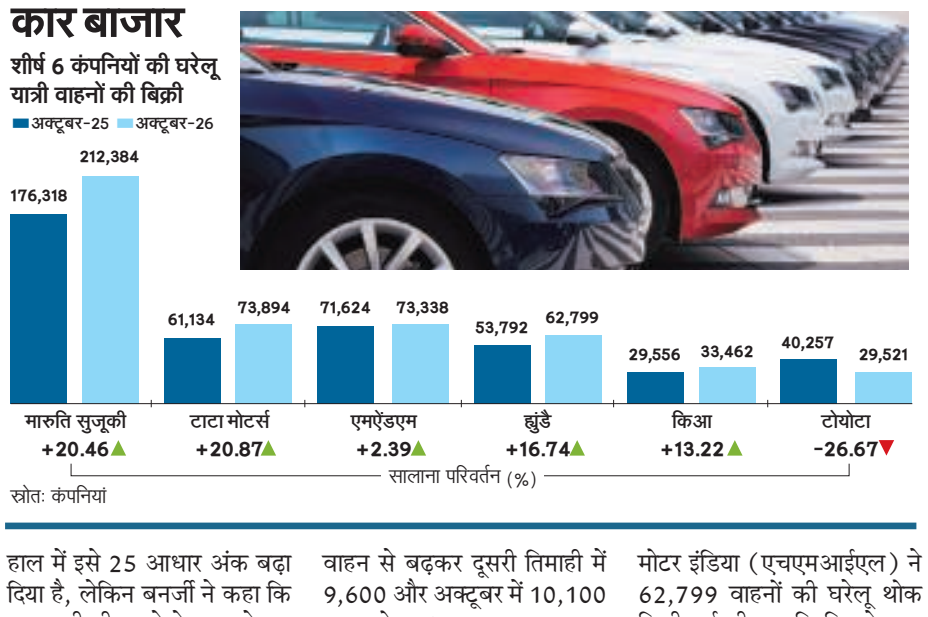
अक्टूबर में कंपनी का कुल उत्पादन लगभग 2,60,000 वाहनों तक पहुंच गया, जो पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 35 प्रतिशत अधिक है। भारती ने इस बढ़ोतरी का श्रेय उत्पादन क्षमता में वृद्धि, बेहतर कार्य क्षमता और काम के दिनों की अधिक संख्या को दिया। उन्होंने बताया कि मांग अभी भी आपूर्ति से अधिक है, बुकिंग ज्यादा है, जबकि डीलरों के पास स्टॉक कम है।

टाटा मोटर्स ने अक्टूबर में 73,894 वाहनों की घरेलू पीवी की थोक बिक्री दर्ज की, जो एक साल पहले के 61,134 से अधिक है। महिंद्रा ऐंड महिंद्रा (एमऐंडएम) ने 73,338 वाहनों की थोक बिक्री दर्ज की, जबकि अक्टूबर 2025 में यह आंकड़ा 71,624 वाहन था। ह्युंडै मोटर इंडिया (एचएमआईएल) ने 62,799 वाहनों की घरेलू थोक बिक्री दर्ज की, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह आंकड़ा 53,792 वाहन था। कंपनी ने अपने इस प्रदर्शन का श्रेय त्योहारों की मजबूत मांग और घरेलू तथा निर्यात बाजारों में तेज रफ्तार को दिया है।

एचएमआईएल के एमडी और सीईओ तरुण गर्ग ने कहा, 'त्योहारी सीजन की मजबूत मांग और साथ ही घरेलू तथा निर्यात बाजारों में अच्छी तेजी के कारण हम बिक्री का यह नया रिकॉर्ड बना पाए हैं। हाल में लॉन्च की गई ह्युंडै बेयॉन भारत के साथ-साथ 50 से अधिक निर्यात बाजारों में भी हमारी वृद्धि की रफ्तार को और मजबूत बनाएगी।' किया इंडिया ने अक्टूबर में 33,462 वाहनों की घरेलू थोक बिक्री दर्ज की, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह आंकड़ा 29,556 वाहन था।

कार बाजार

शीर्ष 6 कंपनियों की घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री



स्रोतः कंपनियां

टीवीएस विवाद पर इनगवर्न की रिपोर्ट में टिप्पणी

कानून से निपटाएं व्यवसाय में पारिवारिक मतभेद

सोहिनी दास
मुंबई, 1 नवंबर

समय के साथ व्यवसाय के कारोबारी मूल्यांकन में आए बदलाव के कारण पहले किए गए किसी पारिवारिक समझौते को दोबारा नहीं खोला जाना चाहिए। पारिवारिक व्यवस्था से संबंधित मतभेदों को कानूनी पक्रिया और पहले से लिखित समझौते के माध्यम से ही हल किया जाना चाहिए। टीवीएस समूह के वेणु श्रीनिवासन परिवार में चल रहे उत्तराधिकार विवाद का जाय़जा लेते हुए कॉर्पोरेट प्रशासन सलाहकार फर्म इनगवर्न रिसर्च सर्विसेज ने अपनी रिपोर्ट में यह बात कही।

'पारिवारिक उत्तराधिकार विवाद सूचीबद्ध कंपनी प्रशासन के लिए जोखिम- टीवीएस उत्तराधिकार मामले से सबक' शीर्षक सेनवंबर 2026 की अपनी रिपोर्ट में इनगवर्न ने कहा कि बाद में होने वाला बिजनेस प्रदर्शन और मूल्यांकन में बदलाव अपने आप में एक प्रलेखित पारिवारिक व्यवस्था को बदलने का आधार नहीं होना चाहिए।' इसमें यह भी कहा गया है कि कोई भी बदलाव या पुनर्व्याख्या समझौते की शर्तों और कानून के अनुसार ही की जानी चाहिए।

यह टिप्पणियां वेणु श्रीनिवासन और उनकी पत्नी मल्लिका श्रीनिवासन व बेटी लक्ष्मी वेणु के बीच पारिवारिक संपत्ति एवंकारोबारों के विभाजन पर मतभेदों के बीच आई हैं।वेणु श्रीनिवासन का तर्क है कि संबंधित संपत्तियां उनकी व्यक्तिगत संपत्ति है और उनके बच्चों, लक्ष्मी और सुदर्शन वेणु के बीच संपत्तियों का बंटवारा 10 दिसंबर, 2020 के संदर्भ में पूरी तरह उचित और न्यायसंगत है। 2020 में व्यापक टीवीएस समूह समझौता हुआ था। लेकिन, मल्लिका श्रीनिवासन और लक्ष्मी वेणु ने सार्वजनिक रूप से यह कहा है कि परिवार के भीतरकोई आर्थिक समझौता नहीं हुआ है और



वेणु श्रीनिवासन, टीवीएस समूह

ऐसेसमझौते के लिए कोई पारदर्शी मूल्यांकन या आपसी सहमति नहीं बनी थी। अपनी रिपोर्ट में इनगवर्न ने कहा कि 21 मार्च, 2024 को परिवार के सभी चार सदस्यों द्वारा एक सहमति पत्र (एमओयू) को लागू किया गया था और अगले दिन टीवीएस होल्डिंग्स ने स्टॉक एक्सचेंजों को इस बारे में सूचित किया था। लेकिन एक्सचेंजों को दी गई सूचना में समझौते की विस्तृत शर्तों का खुलासा नहीं किया गया था। इनगवर्न ने कहा कि अक्टूबर 2026 में सार्वजनिक हुए विवाद से यह जरूरत उठी है कि टीवीएस होल्डिंग्स और टीवीएस मोटर को पूर्व में हुए समझौते का नए सिरे से खुलासा करना चाहिए या नहीं। फर्म ने कहा कि उसे इस बारे में बिल्कुल पता नहीं चला है कि किसी भी कंपनी ने अक्टूबर के विवाद का स्टॉक-एक्सचेंज फाइलिंग में कोई जिक्र किया है।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सुदर्शन वेणु के प्रबंधन उत्तराधिकार स्थापित कॉर्पोरेट प्रक्रियाओं के माध्यम से आगे बढ़े थे। टीवीएस होल्डिंग्स के प्रबंध निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति को शेयरधारकों की मंजूरी मिली, जबकि टीवीएस मोटर के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति को इसके निदेशक मंडल ने अनुमोदित किया था और इसका खुलासा किया गया था।

चिप हब के लिए ओडिशा में निवेश होंगे 4 अरब डॉलर

हेमंत कुमार राउत
भुवनेश्वर, 1 नवंबर

ओडिशा वैश्विक चिप निर्माण और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला में अपनी मजबूत पहचान बनाने के लिए पांच सेमीकंडक्टर परियोजनाएं लाने की योजना बना रहा है। इन पर लगभग 4 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया जाएगा। पारंपरिक रूप से खनन, धातु और खनिज-आधारित उद्योगों के प्रभुत्व वाले ओडिशा के औद्योगिक परिदृश्य में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन और उन्नत 3डी चिप पैकेजिंग तक फैली ये परियोजनाएं महत्त्वपूर्ण बदलाव का संकेत हैं।

बीते शुक्रवार को टाईकॉन भुवनेश्वर 2026 के उद्घाटन अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) विशाल कुमार देव ने कहा कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत देशभर के लिए स्वीकृत 12 परियोजनाओं में से दो ओडिशा में स्थापित की जा रही हैं।

उन्होंने कहा, 'भारत की पहली कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट और पहली उन्नत 3डी चिप पैकेजिंग यूनिट पर यहां बहुत तेजी से काम चल रहा है, जिनका शिलान्यास मंजूरी मिलने के 6 से 8 महीने के भीतर हो गया था।'

देव ने कहा कि ओडिशा खदान-आधारित अर्थव्यवस्था से अब दिमाग-आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, जिसमें सेमीकंडक्टर, एआई डेटा सेंटर और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) जैसे बौद्धिक कार्यों के बुनियादी ढांचे के निर्माण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, 'इंटेल और 3डी ग्लास सॉल्यूशंस जैसी वैश्विक कंपनियों के साथ हमारे सहयोग का मकसद वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में अग्रणी बनने का है।'

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि आज डेटा नया तेल है लेकिन कल कंप्यूटिंग नया तेल बन जाएगा और ओडिशा ने इस उभरते क्षेत्र में पहले ही छलांग लगा दी है। देव ने यह भी कहा, 'ओडिशा अपनी एआई नीति तैयार करने और एआई मिशन की घोषणा करने वाला पहला राज्य है।' इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री मुकेश महालिंग ने कहा कि प्रमुख निवेश केंद्र बनने की ओडिशा में कई विशेषताएं हैं। यहां प्रचुर प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं। साथ ही पर्याप्त बिजली, भूमि और पानी की उपलब्धता एवं प्रगतिशील औद्योगिक नीतियां यहां निवेश लाने में मददगार हैं।

जेएसडब्ल्यू बीपीएसएल (भूषण पावर ऐंड स्टील लिमिटेड) के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने ओडिशा की निर्यात क्षमता का विस्तार करने में विनिर्माण मानकों, कुशल लॉजिस्टिक्स और वैश्विक प्रौद्योगिकी साझेदारी के महत्त्व पर जोर दिया।

टाई भुवनेश्वर के प्रेसिडेंट अयस्कान्त मोहंती ने कहा कि नीतिगत समर्थन को बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे, गुणवत्ता मानकों और लागत प्रतिस्पर्धा क्षमता के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।' इस अवसर पर एमएएस इंडिया के सीईओ मलिक अहमदीन, वॉक्सी टेक्नॉलजीज और ईएचएएम के चेयरमैन और सीईओ मुरली बुक्कापटनम तथा टाई भुवनेश्वर के वाइस प्रेसिडेंट सानू रथ ने भी बात की।



भुवनेश्वर में शुक्रवार को टाईकॉन भुवनेश्वर 2026 में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री मुकेश महालिंग, अतिरिक्त मुख्य सचिव हेमंत शर्मा और विशाल देव और अन्य

औद्योगिक बदलाव

- वैश्विक चिप निर्माण और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला में अग्रणी बनने के लिए राज्य सरकार की 5 परियोजनाएं लाने की योजना
- ओडिशा के औद्योगिक परिदृश्य में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन और उन्नत 3डी चिप पैकेजिंग तक फैली ये परियोजनाएं महत्त्वपूर्ण बदलाव का संकेत

टू पॉइंट ओ कैपिटल ने जुटाए 1 करोड़ डॉलर

पीरजादा अबरार
बेंगलूरु, 1 नवंबर

ट्रांजिशन वेंचर कैपिटल के नेतृत्व वाले फंडिंग राउंड में टू पॉइंट ओ कैपिटल (टीडब्ल्यू.ओ) ने 1 करोड़ डॉलर की रकम जुटाई है। इस राउंड में मौजूदा निवेशक ओमनीवोर और एंजेल निवेशक चिरंजीव सिंह सलूजा तथा सुधीर एम रेड्डी ने भी हिस्सा लिया। यह कंपनी वाणिज्यिक एवं औद्योगिक (सीऐंडआई) व्यवसायों के लिए एआई पर आधारित एक फुल-स्टैक स्वच्छ ऊर्जा प्लेटफॉर्म है।

इस पूंजी से कंपनी को बैटरी एनर्जी स्टोरेज (बीईएसएस) के क्षेत्र में विस्तार करने और सोलर, ऊर्जा किफायत तथा अप शिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी और मजबूत बनाने में मदद करेगी। कंपनी डेटा सेंटर, ऑटोमोटिव, फार्मा, निर्माण और हेल्थकेयर जैसे अधिक ऊर्जा और पानी की खपत वाले क्षेत्रों में भी अपने विस्तार की योजना बना रही है।

यह कंपनी पूरे भारत में प्रमुख मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) और इंजीनियरिंग, ईपीसी फर्मों के साथ काम करती है। इसके ग्राहकों में प्रीमियर एनर्जीज, गोदरेज, जेके टायर, मोरेपेन फार्मा, विप्रो और फीनिक्स मिल्स शामिल हैं।

सीऐंडआई ग्राहकों को अपनी स्वच्छ ऊर्जा और उपयोगिता संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए कस्टमाइज्ड कैपिटल और परिसंपत्ति आधारित समाधानों की आवश्यकता होती है। ये समाधान परिचालन लागत कम करने, यूरोपीय संघ जैसे नए बाजारों तक पहुंच प्रदान करने और परिचालन संबंधी लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। यह अवसर सालाना 100 अरब डॉलर से 150 अरब डॉलर का होने का अनुमान है, जिसे कंपनी अपने पूंजी समाधानों के माध्यम से पूरा करना चाहती है।

भूषण मामले में वसूली को हरी झंडी

भाविनी मिश्रा
नई दिल्ली, 1 नवंबर

नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने कहा है कि भूषण पावर ऐंड स्टील लिमिटेड (बीपीएसएल) से कथित तौर पर गबन किए गए लगभग 5,431 करोड़ रुपये की वसूली के लिए सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (एसएफआईओ) की ओर से दायर याचिका, इन्सॉल्वेंसी ऐंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) की धारा 32ए के आधार पर स्वीकार करने योग्य है। ट्रिब्यूनल ने पूर्व प्रमोटरों और अन्य संस्थाओं की आठ याचिकाओं को खारिज कर दिया। इन लोगों ने इस कार्यवाही को चुनौती दी थी।

न्यायमूर्ति अनूपिंदर सिंह ग्रेवाल की अध्यक्षता और न्यायमूर्ति रविंद्र चतुर्वेदी की सदस्यता (तकनीकी) वाले पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि उसे मामले की सुनवाई का अधिकार है और केंद्र ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत वैध रूप से कार्यवाही को अधिकृत किया है। अपने 30 अक्टूबर के आदेश में एनसीएलटी ने स्पष्ट किया कि आईबीसी के तहत बीपीएसएल की समाधान योजना की मंजूरी वित्तीय कदाचार के आरोपों का अंत नहीं करती है। इसमें कहा गया कि आईबीसी की धारा 32ए, पूर्व निदेशकों या तीसरे पक्ष को धोखाधड़ी से अलग की गई संपत्तियों की वापसी की मांग करने वाली कार्यवाही से नहीं बचाती है।

अप्रैल 2023 में कंपनी अधिनियम की धारा 241, 242, 246 और 339 के तहत दायर की गई एसएफआईओ की याचिका में पूर्व प्रमोटरों, संबद्ध फर्मों और व्यक्तियों सहित 76 प्रतिवादी बनाए गए हैं। याचिका में इन प्रतिवादियों को धोखाधड़ी में शामिल होने, अपने लेनदारों और अन्य हितधारकों को नुकसान पहुंचाने के कारण ब्याज के साथ कम से कम 5,431 करोड़ रुपये के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराने की मांग की गई है।

एसएफआईओ की जांच के अनुसार 2009-10 से संबद्ध फर्मों और व्यक्तियों के एक नेटवर्क के माध्यम से बीपीएसएल से कथित तौर पर धन का गबन किया गया।

एसएफआईओ ने आरोप लगाया कि पूर्व प्रमोटर और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक संजय सिंघल ने अपनी पत्नी और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर चल और अचल संपत्ति हासिल करने के लिए इन फर्मों का उपयोग करके धन के गबन का ताना-बाना बुना। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया कि फर्म की वित्तीय डीलिंग को पूंजी निवेश की सुविधा देने और बैंकों से क्रेडिट सुविधा प्राप्त करने के लिए बनाया गया था। ट्रिब्यूनल ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि याचिका आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि कथित लेनदेन अतीत में किए गए।



एनसीएलटी का रुख

- भूषण पावर ऐंड स्टील लिमिटेड से गबन किए गए 5.4 करोड़ रुपये की वसूली संबंधी एसएफआईओ की याचिका सुनवाई के योग्य
- ट्रिब्यूनल ने मामले में चुनौती देने वाले पूर्व प्रमोटरों और अन्य संस्थाओं की आठ याचिकाओं को खारिज कर दिया

नीचे आने को तैयार नहीं कच्चे माल की लागत

जून तिमाही में कच्चे माल की लागत 47 तिमाहियों के उच्चतम स्तर पर थी, सितंबर में भी रही यही स्थिति

सचिन मामपट्टा
मुंबई, 1 नवंबर

सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकॉनमी (सीएमआईई) के आंकड़ों से पता चलता है कि जून तिमाही में गैर-वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों की प्रत्येक 100 रुपये की बिक्री में से 44 रुपये कच्चे माल की लागत और उससे जुड़े खर्चों को पूरा करने में चले गए। यह 2014 के आखिर के बाद से किसी भी तिमाही में सबसे अधिक है। इन आंकड़ों का बिज़नेस स्टैंडर्ड ने विश्लेषण किया है।

सितंबर तिमाही में भी कच्चे माल की ऊंची लागत का यह रुझान बरकरार रहा। समीक्षा में शामिल गैर-वित्तीय क्षेत्र की 3,687 कंपनियों के लिए जून तिमाही की बिक्री में कच्चे माल, स्टोर और स्पेयर पार्ट्स का खर्च हिस्सा 44.49 प्रतिशत रहा। यह जून 2025 में दर्ज 38.77 प्रतिशत के आंकड़े से 5.72 फीसदी अधिक है।

473 कंपनियों के उपलब्ध आंकड़ों के नमूने के अनुसार सितंबर तिमाही में कच्चे माल और उससे जुड़ी लागत कुल बिक्री का लगभग 41 प्रतिशत रही। हालांकि यह आंकड़ा जून तिमाही की तुलना में थोड़ा कम है। फिर भी यह सितंबर 2025 में समाप्त तीन महीनों की अवधि में दर्ज किए गए 39.8 प्रतिशत के आंकड़े से अधिक है।

स्टोर्स और स्पेयर्स से मतलब उन सहायक वस्तुओं से है जिनका उपयोग विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, जैसे लुब्रिकेंट्स या कलपुर्जे। गैर-वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों में स्टील और ऑटोमोबाइल जैसी विनिर्माण कंपनियां तथा खनन और निर्माण जैसे अन्य क्षेत्रों की कंपनियां शामिल हैं।

सितंबर तिमाही के नतीजों के मौजूदा दौर के बीच ये आंकड़े अहम हो जाते हैं। यह तीसरी ऐसी तिमाही है, जिस पर फरवरी में शुरू हुए पश्चिम एशिया संघर्ष का असर पड़ा है।

कंपनियों के पास आमतौर पर कच्चे माल का स्टॉक होता है, जो उत्पादन लागत में होने वाली अस्थायी बढ़ोतरी से बचाव कर सकता है। लेकिन ऐसा आमतौर पर सीमित समय के लिए ही होता है। जून के ये ऊंचे आंकड़े सितंबर तिमाही के मौजूदा आय सत्र के लिए संभावित चुनौतियों का संकेत हैं।

ब्लूओशन ऐसेट मैनेजमेंट के संस्थापक और मुख्य निवेश अधिकारी निपुण मेहता के अनुसार कच्चे माल की बढ़ती लागत कुछ खास क्षेत्रों में मांग को प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए घरेलू उपकरण बनाने वाली उन कंपनियों पर इसका असर पड़ सकता है जो कीमतें नहीं बढ़ा पाई हैं। मेहता का मानना है कि केबल बनाने वाली कंपनियों और सीमेंट कंपनियों जैसे कई अन्य क्षेत्रों ने लागत के इस बढ़ते दबाव का बेहतर तरीके से मुकाबला किया है।

क्वांटम एडवाइजर्स के पोर्टफोलियो मैनेजर नीलेश शेट्टी के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) जैसे सेवा उद्योगों और फार्मास्युटिकल्स जैसे क्षेत्रों पर सबसे कम असर पड़ेगा, क्योंकि इनमें कच्चे माल की लागत बिक्री का एक छोटा हिस्सा होती है। हालांकि, उनका भी यही मानना है कि अंततः ज्यादातर कंपनियां लागत में हुई इस बढ़ोतरी का बोझ ग्राहकों पर डाल देंगी।

बजाज ऑटो के मुख्य वित्तीय अधिकारी दिनेश थापर ने कंपनी की जून तिमाही की अर्निंग्स कॉल के दौरान बताया कि स्टील, एल्युमीनियम, प्लैटिनम और रोडियम जैसी सामग्रियों की लागत में 10 से 40 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है।



इंडियन बैंक Indian Bank

कॉर्पोरेट कार्यालय, चेन्नै

इंडियन बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के अग्रणी बैंक ने धन प्रबंधन वर्टिकल तैयार करने के लिए परामर्शदात्री सेवाएं लेने हेतु एक आरएफपी जारी किया है।

इच्छुक पक्ष विस्तृत विवरण के लिए बैंक की वेबसाइट: https://www.indianbank.bank.in/tenders/ और GeM पोर्टल देखें।

बॉश की नजर एसी बाजार पर

जर्मनी की कंपनी बॉश की इकाई बॉश होम कम्फर्ट की नजर भारतीय एयर कंडीशनर (एसी) बाजार में अगले दो साल में दो अंक की हिस्सेदारी बढ़ाने पर है। कंपनी अगले साल बॉश ब्रांड के एसी उतारने की तैयारी में है। इसके साथ ही कंपनी देश के शीर्ष पांच ब्रांड में जगह बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। कंपनी के प्रबंध निदेशक संजय सुधाकरन ने यह बात कही है। कंपनी भारत में अपने कारोबार का विस्तार दोहरे ब्रांड की रणनीति के तहत करेगी। इसके लिए वह हिताची और बॉश, दोनों ब्रांड को अलग-अलग उपभोक्ता वर्गों के लिए पेश करेगी। बॉश होम कम्फर्ट समूह ने अगस्त, 2025 में जॉनसन कंट्रोल्स और हिताची के वैश्विक आवासीय एवं हल्के वाणिज्यिक एसी कारोबार का अधिग्रहण किया था। *भाषा*

दिल्ली संस्करण : बिजनेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक नंदन सिंह रावत द्वारा नीतेंद्र कुमार श्रीवास्तव, जागरण प्रकाशन लिमिटेड, डी-210-211, सेक्टर-63 नोएडा-201301 उ.प्र. और पृथ्वीस दास, डी.बी. कॉर्प लिमिटेड 10, जेएलएन मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर - 302015 से मुद्रित एवं नेहरू हाउस, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित

संपादक : कैलाश नौटियाल, पीआरजीआई रजिस्ट्रेशन नं. DELHIN/2008/27804 पाठक संपादक को lettershindi@bsmail.in पर संदेश भेज सकते हैं। टेलीफोन - 011-23720202/23762742

सबस्क्रिप्शन और सर्कुलेशन के लिए संपर्क करें... सुश्री मानसी सिंह हेड, कस्टमर रिलेशन्स बिजनेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड, एच/4, बिल्डिंग एच, पैरागन सेंटर, बिड़ला सेंचुरियन के सामने, पी बी मार्ग, वर्ली, मुंबई-400013 ईमेल.. subs_bs@bsmail.in या 57575 पर एसएमएस करें REACHBS कोई हवाई अधिभार नहीं

Nippon India Mutual Fund

Wealth sets you free



व्यक्ति बदल सकते हैं, पर भरोसेमंद तरीके, कभी नहीं.

जाँची–परखी हुई प्रक्रियाएँ किसी भी निवेश कंपनी की सफलता के लिए प्रमुख होती हैं क्योंकि यही उस कंपनी की कार्यशैली को दर्शाती हैं. इसलिए, ऐसा निवेश प्रबंधक चुनें जो सिर्फ़ कुछ कुशल व्यक्तियों के बल पर नहीं, बल्कि मज़बूत प्रक्रियाओं के विश्वास पर टिका हो.

सुदृढ़ प्रक्रियाएँ और रिस्क मैनेजमेंट आपको अपने लक्ष्यों को स्थिरता और निरंतरता के साथ प्राप्त करने में मदद करते हैं.

mf.nipponindiaim.com/EdgeOfKnowledge

अपने म्यूचुअल फंड वितरक या निवेश सलाहकार से संपर्क करें। **8000112244** पर मिस्ड कॉल दीजिए

निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की निवेशक शिक्षा और जागरूकता पहल.

म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए सहायक जानकारी: सभी म्यूचुअल फंड निवेशकों को वन टाइम KYC (नो योर कस्टमर) प्रक्रिया से गुज़रना होता है. निवेशकों को केवल पंजीकृत म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए, जिसकी जाँच SEBI की वेबसाइट पर 'Intermediaries/Market Infrastructure Institutions' के अंतर्गत की जानी चाहिए. अपनी शिकायतों के निवारण के लिए आप https://scores.sebi.gov.in पर विज़िट कर सकते हैं. KYC, विभिन्न विवरणों में बदलाव और शिकायतों के निवारण पर अधिक जानकारी के लिए, विज़िट करें mf.nipponindiaim.com/investoreducation/what-to-know-when-investing

Nippon India Mutual Fund, MF/022/95/1

म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें.

rediffusion.in

संक्षेप में

राज्यों के स्थापना दिवस पर मोदी की शुभकामनाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरलम के स्थापना दिवस पर इन राज्यों के लोगों को शुभकामनाएं दीं और वहां के सभी निवासियों की शांति, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। मोदी ने यह भी उम्मीद जताई कि आने वाले साल इन छह राज्यों के लोगों के लिए नए अवसर, अधिक समृद्धि और निरंतर प्रगति लेकर आएंगे। उन्होंने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'मध्य प्रदेश के सभी भाई-बहनों को राज्य के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं! हमारा यह प्रदेश गौरवशाली विरासत, समृद्ध संस्कृति और अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य की भूमि है। यहां के विश्वविख्यात धरोहर स्थल इसकी ऐतिहासिक पहचान को और भव्य बनाते हैं।' *भाषा*

10 वर्षीय बॉन्ड की यील्ड 7% तक आएगी!

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा मानक ब्याज दर में आगे आधा प्रतिशत की वृद्धि किए जाने की स्थिति में भी मार्च, 2027 तक भारतीय सरकारी बॉन्ड पर यील्ड घटकर 6.75 से 7 प्रतिशत पर आ सकती है। एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट में रविवार को कहा गया कि कम उधारी और यील्ड के ऐतिहासिक रुझानों से बाजार को समर्थन मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक, 'भारत के 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति पर यील्ड मार्च, 2027 के अंत तक 6.75 प्रतिशत से सात प्रतिशत के दायरे में स्थिर हो सकतती है।' 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति पर यील्ड फिलहाल लगभग 7.43 प्रतिशत है, जबकि भारतीय और अमेरिकी 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड यील्ड के बीच का अंतर लगभग 2.50 प्रतिशत के आसपास बना हुआ है। *भाषा*

पीलीभीत : दो ईआरओ के निलंबन का आदेश

निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत विधान सभा क्षेत्र में मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर दो मतदाता पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को निलंबित करने का आदेश दिया है। आयोग ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में दंडात्मक प्रावधान जोड़ने को भी कहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को शनिवार को भेजे पत्र में आयोग ने निर्देश दिया कि ईआरओ मयंक गोस्वामी और हेमंत चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाए। पत्र में कहा गया है कि दोनों के खिलाफ आरोप पत्र जांच-पड़ताल के लिए निर्वाचन आयोग को सौंपे जाने चाहिए और आयोग की पूर्व अनुमति के बिना उन्हें बहाल नहीं किया जा सकता। *भाषा*

जीएसटी संग्रह 25.6% बढ़ा

शुद्ध माल एवं सेवा कर संग्रह अक्टूबर में बढ़कर 2.03 लाख करोड़ रुपये हो गया

मोनिका यादव
नई दिल्ली, 1 नवंबर

आयात से मिलने वाले कर राजस्व में तेजी बढ़ोतरी की मदद से केंद्र और राज्य सरकारों का शुद्ध माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह रिफंड घटाने के बाद अक्टूबर में सालाना आधार पर 25.6 प्रतिशत बढ़कर 2.03 लाख करोड़ रुपये हो गया। यह चालू वित्त वर्ष में दर्ज की गई अब तक की सबसे तेज वृद्धि दर है। वित्त मंत्रालय द्वारा रविवार को जारी अंतरिम आंकड़ों से यह जानकारी मिली है।

चालू वित्त वर्ष में सकल जीएसटी संग्रह में भी सबसे तेज वृद्धि दर्ज की गई, जो सालाना आधार पर 22.9 प्रतिशत बढ़कर 2.31 लाख करोड़ रुपये हो गया। कुल आंकड़ों के लिहाज से चालू वित्त वर्ष में सकल और शुद्ध जीएसटी संग्रह अप्रैल में क्रमशः 2.42 लाख करोड़ रुपये और 2.10 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने के बाद दूसरे सबसे ऊंचे स्तर पर रहे।



चालू वित्त वर्ष में सकल जीएसटी संग्रह में भी सबसे तेज वृद्धि दर्ज हुई और सालाना आधार पर 22.9% बढ़कर 2.31 लाख करोड़ रुपये हो गया

वित्त वर्ष 27 के पहले सात महीने के दौरान अप्रैल, जुलाई और सितंबर के बाद सकल जीएसटी संग्रह चौथी बार 2 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया। अप्रैल के बाद, जब जीएसटी संग्रह 2.1 लाख करोड़ रुपये था, यह दूसरी बार है जब शुद्ध जीएसटी संग्रह ने यह आंकड़ा पार किया है।

शुद्ध जीएसटी राजस्व में यह हालिया बढ़ोतरी सितंबर में दर्ज 18.1 प्रतिशत की वृद्धि, अगस्त में 8.3 प्रतिशत और जुलाई में 15.8 प्रतिशत की वृद्धि के बाद हुई है। आयात से जुड़ा जीएसटी राजस्व घरेलू संग्रह की तुलना में लगातार आगे बना रहा। अक्टूबर में आयात से प्राप्त सकल एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) राजस्व पिछले साल के मुकाबले 42.2 प्रतिशत बढ़कर 72,246 करोड़ रुपये हो गया। यह कुल सकल जीएसटी संग्रह का लगभग एक-तिहाई हिस्सा है।

रिफंड समायोजित करने के बाद आयात से प्राप्त शुद्ध जीएसटी राजस्व 56.2 प्रतिशत बढ़कर 58,319 करोड़ रुपये हो गया। इस महीने के दौरान सकल घरेलू जीएसटी राजस्व 15.8 प्रतिशत बढ़कर 1.59 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि शुद्ध घरेलू संग्रह 16.4 प्रतिशत बढ़कर 1.45 लाख करोड़ रुपये हो गया।

टैक्स कनेक्ट एडवाइजरी सर्विसेज के साझेदार विवेक जालान ने कहा कि अक्टूबर 2026 का संग्रह काफी अहम लगता हो गया है, क्योंकि अक्टूबर 2025 वह पहला पूरा महीना था, जिसमें जीएसटी 2.0 के तहत दर सुधार का असर राजस्व के आंकड़ों में दिखाई दिया था।

देश का कच्चा तेल आयात रिकॉर्ड स्तर तक उछला

भाषा
नई दिल्ली, 1 नवंबर

भारत का कच्चे तेल का आयात अक्टूबर में बढ़कर रिकॉर्ड लगभग 56 लाख बैरल प्रतिदिन के स्तर पर पहुंच गया। ऊर्जा क्षेत्र की आसूचना कंपनी केप्लर के आंकड़ों के अनुसार भारतीय रिफाइनरी इकाइयों ने भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद पश्चिम एशिया और रूस से कच्चे तेल की खरीद बढ़ाई है। केप्लर के प्रमुख विश्लेषक निखिल दुबे ने बताया कि अक्टूबर में पश्चिम एशिया से भारत को करीब 23 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल की आपूर्ति हुई, जबकि रूस से आयात लगभग 20 लाख बैरल प्रतिदिन के स्तर पर बना रहा।

उन्होंने कहा कि जहाज से जहाज के बीच तेल हस्तांतरण बढ़ने से होर्मुज स्ट्रैट के रास्ते कच्चे तेल की आवाजाही में मदद मिली। इससे सितंबर और अक्टूबर के दौरान खाड़ी देशों से आपूर्ति में सुधार हुआ और भारतीय रिफाइनरी इकाइयों को तेल खरीद के अधिक विकल्प मिले। हालांकि, नवंबर और दिसंबर में रूस से तेल की आपूर्ति में कुछ कमी आने की आशंका है।

काला सागर क्षेत्र में हमलों से माल ढुलाई लागत बढ़ रही है, जिससे रूसी तेल भारतीय खरीदारों के लिए महंगा पड़ सकता है। दूसरी ओर खाड़ी देशों के आपूर्तिकर्ता भारतीय बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धी कीमतों पर तेल उपलब्ध करा रहे हैं। दुबे के मुताबिक, यदि होर्मुज स्ट्रैट से तेल की आपूर्ति दोबारा बाधित होती है, तो भारतीय रिफाइनरी कंपनियां अधिक परिवहन लागत के बावजूद रूसी तेल की खरीद फिर बढ़ा सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 16 अक्टूबर को ग्राहम अधिनियम के तहत मिली छूट से कुछ भारतीय खरीदारों की रूसी तेल खरीद से जुड़े जोखिमों को लेकर चिंताएं कम हो सकती हैं। इससे रिफाइनरी इकाइयों को खरीद संबंधी फैसले लेने में अधिक लचीलापन मिलेगा।

भारत कच्चे तेल की कुल जरूरत का लगभग 90 प्रतिशत आयात करता है। ऐसे में वैकल्पिक स्रोतों से तेल उपलब्धता और उसकी वास्तविक लागत देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि रूस और पश्चिम एशिया के बीच तेल खरीद का फैसला केवल भू-राजनीतिक परिस्थितियों से नहीं, बल्कि कीमत, परिवहन खर्च और आपूर्ति की सुरक्षा जैसे व्यावसायिक पहलुओं से भी तय हो रहा है।

अक्टूबर में यूपीआई का औसत दैनिक मूल्य पहुंचा 1 लाख करोड़ रुपये पार

अजिंक्य कावले
मुंबई, 1 नवंबर

त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही अक्टूबर में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के जरिए होने वाले लेनदेन का औसत दैनिक मूल्य पहली बार 1 लाख करोड़ रुपये पार पहुंच गया। इस महीने औसत दैनिक लेनदेन की संख्या 82.2 करोड़ रही। यूपीआई के लिए यह भी अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा रहा।

अक्टूबर में 25.47 अरब लेनदेन हुए, जो अक्टूबर 2025 में हुए 20.7 अरब लेनदेन की तुलना में लगभग 23 प्रतिशत अधिक रहे। अक्टूबर 2026 में 31.53 लाख करोड़ रुपये के लेनदेन हुए, जो अक्टूबर 2025 में हुए 27.27 लाख करोड़ रुपये के लेनदेन की तुलना में 16 प्रतिशत अधिक रहे।

यूपीआई की संख्या और मूल्य पर यह ध्यान ऐसे समय में दिया जा रहा है, जब दीवाली के बाद कुछ चुनिंदा पर्सन-टु-मर्चेंट (पी2एम) लेनदेने पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू करने का प्रस्ताव है। कैशफ्री के सह-संस्थापक रीजू दत्ता ने कहा, 'त्योहारी सीजन के कारण इसमें बढ़ोतरी हुई। नवरात्रि और बड़ी ऑनलाइन सेल अक्टूबर में आई और लोगों ने रोजमर्रा के भुगतानों के साथ-साथ त्योहारों की बड़ी खरीदारी के लिए भी यूपीआई का इस्तेमाल किया। अप्रैल से अगस्त तक यूपीआई भुगतानों की संख्या तो बढ़ती रही, लेकिन उनका कुल दैनिक मूल्य स्थिर रहा और औसत भुगतान राशि कम होती गई। सितंबर और अक्टूबर में भुगतानों की संख्या की तुलना में उनके मूल्य में तेजी से



बढ़ोतरी हुई और लगातार दो महीने तक औसत भुगतान राशि में इजाफा हुआ।' सितंबर में 29.37 लाख करोड़ रुपये के 24.06 अरब लेनदेन किए गए। अगस्त में 29.82 लाख करोड़ रुपये के कुल 24.5 अरब भुगतान किए गए।

उद्योग जगत के अधिकारियों ने कहा कि भुगतान प्रणाली का दीर्घकालिक टिकाऊपन इसके सुचारू रूप से काम करते रहने के लिए काफी अहम है, खासकर त्योहारी सीजन जैसे अधिक खपत वाले समय के दौरान।

फाइब के प्रबंध निदेशक और समूह के मुख्य कार्य आधिकारी अक्षय मेहरोत्रा ने कहा, 'प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) संरचना को शुरू में 15 अक्टूबर को लागू किया जाना था और खबरों के अनुसार अब दीवाली के बाद तक टाल दिया गया है। यह भारत के डिजिटल भुगतान के बुनियादी ढांचे के दीर्घकालिक टिकाऊपन के संबंध में अहम सवाल खड़ा करता है। चूंकी खरीदारी के चरम सीजन में लेनदेन की संख्या बढ़ जाती है, तो यह जरूरी हो जाता है कि डिजिटल भुगतान ग्राहकों और व्यापारियों दोनों के लिए ही किफायती बने रहें और साथ ही यह भी सुनिश्चित हो कि पारि स्थितिकी तंत्र व्यावसायिक रूप से टिकाऊ बना रहे।'

इंडियन ऑयल ने पूंजीगत व्यय के लक्ष्य का 37% खर्च किया

सुधीर पाल सिंह
नई दिल्ली, 1 नवंबर

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने सितंबर 2026 को समाप्त चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में अपने पूंजीगत व्यय के लक्ष्य का 37 प्रतिशत खर्च कर लिया है। वित्त वर्ष 2026-27 में कंपनी के लिए 32,700 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कंपनी के पूंजीगत व्यय की गति महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की बढ़ती मांग को पूरा करने में भारत की जरूरत से जुड़ी है।

कंपनी ने अप्रैल-सितंबर 2026 के दौरान 12,162 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इसमें से अधिकांश खर्च (लगभग 9,300 करोड़ रुपये) रिफाइनिंग और मार्केटिंग पर किया गया है, जबकि 1,300 करोड़ रुपये पेट्रोकेमिकल परियोजनाओं पर खर्च किए गए।

इंडियन ऑयल ने पेट्रोकेमिकल परियोजनाओं पर 1,306 करोड़ रुपये, नई पाइपलाइन बिछाने पर 582 करोड़ रुपये, प्राकृतिक गैस परियोजनाओं पर 133 करोड़ रुपये, अनुसंधान एवं विकास (आरऐंडडी) पर 109 करोड़ रुपये खर्च किए, जबकि छह महीने की अवधि के दौरान अन्वेषण और उत्पादन (ईऐंडपी) पर केवल 121 करोड़ रुपये खर्च किए गए। कंपनी की पूंजीगत व्यय की स्थिति पिछले साल से विपरीत है। कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष की पहली छमाही में सितंबर के अंत तक लक्ष्य का 47 प्रतिशत धन खर्च कर दिया था।

कंपनी के कॉरपोरेट फाइनैंस और ट्रेजरी के कार्यकारी निदेशक नितिन कुमार ने निवेशकों को एक कॉन्फ्रेंस कॉल में बताया, 'ये निवेश हमारे दीर्घकालिक रणनीतिक खाके और राष्ट्रीय ऊर्जा प्राथमिकताओं के अनुरूप हैं।' उन्होंने कहा कि कंपनी क्षमता निर्माण और एकीकरण के लिए चरणबद्ध तरीके से काम कर रही है। कुल मिलाकर इंडियन ऑयल इस समय 1.04 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इसमें दो बड़ी परियोजनाएं- पारादीप रिफाइनरी में 13,805 करोड़ रुपये का पैराक्सिलीन-प्यूरिफाइड टेरेफ्थेलिक एसिड (पीएक्स-पीटीए) कॉम्प्लेक्स और 3,220 करोड़ रुपये की नई मुद्रा-पानीपत कच्चा तेल पाइपलाइन परियोजनाएं शामिल हैं।

GANESHA ECOSPHERE LIMITED
CIN : L51109UP1987PLC009090
Regd. Office : Raipur (Rania), Kalpi Road, Distt. Kanpur Dehat - 209304 (U.P.)
E-mail: secretarial@ganeshaecosphere.com, Website : www.ganeshaecosphere.com
Tel. No.: 0512-2555505-06, +91 9198708383

Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter and Half Year ended 30th September, 2026

(₹ in Lakh)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended 30.09.2026 (Unaudited)	Half Year ended 30.09.2026 (Unaudited)	Quarter ended 30.09.2025 (Unaudited)
1.	Revenue from Operations	51,296.07	93,662.74	36,338.16
2.	Net Profit for the period before Tax	3,613.92	7,323.39	59.42
3.	Net Profit/ (Loss) for the period after tax#	2,807.57	5,711.05	(49.99)
4.	Total Comprehensive Income/(Loss) for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income/(Loss) (after tax)]	2,834.04	5,837.06	(139.43)
5.	Equity Share Capital	2,679.60	2,679.60	2,679.60
6.	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)	-	-	-
7.	Earnings Per Share (of Rs.10/- each)			
	- Basic (in Rs.):	10.50* ^	21.36* ^	(0.28)* ^
	- Diluted (in Rs.):	10.50* ^	21.36* ^	(0.24)* ^
	*Not annualised			

The Group does not have any Exceptional and Extraordinary item to report for the above results.
^ Pursuant to the Ganesha Ecosphere Employees' Stock Option Scheme, 2021, Ganesha Employees' Welfare Trust is holding 63,043 Equity Shares of the Parent Company, which have been reduced while computing basic and diluted earnings per share.

Notes:
Additional Information on standalone financial results is as follows:

(₹ in Lakh)

Particulars	Quarter ended 30.09.2026 (Unaudited)	Half Year ended 30.09.2026 (Unaudited)	Quarter ended 30.09.2025 (Unaudited)
Revenue from Operations	31,648.83	57,878.94	25,935.20
Profit before Tax	1,907.75	3,753.28	1,043.36
Profit after Tax	1,449.89	2,824.84	781.83

The above is an extract of the detailed format of Unaudited Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results are available on the Stock Exchange websites www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the Company's website www.ganeshaecosphere.com and can be accessed by scanning the following Quick Response (QR) Code:

Place: Kanpur
Date: 31.10.2026

For Ganesha Ecosphere Limited
sd/-
(Vishnu Dutt Khandelwal)
Executive Vice Chairman
(Whole Time Director)
DIN: 00383507

Special window for re-lodgement of transfer requests of physical shares

SEBI vide its Circular No. HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 dated January 30, 2026 has opened a special window for a period of One Year from February 05, 2026 till February 04, 2027,allowing shareholders to lodge/ re-lodge transfer deeds of physical securities, which were sold/purchased prior to April 01, 2019 but were not lodged with Company/RTA or which were lodged earlier but were rejected/returned/not attended due to deficiency in the documents/process/or otherwise. Investors who missed the earlier cut-off are encouraged to utilize this special window and submit the requisite documents to the Company/ RTA i.e. Skyline Financial Services Private Limited. Kindly note that request(s) which are accompanied by original share certificate(s) along with transfer deed(s) and other supporting documents will only be considered under the Special Window.

कोल इंडिया की आपूर्ति पहली बार हुई 7 करोड़ टन से ज्यादा

साकेत कुमार
नई दिल्ली, 1 नवंबर

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने अक्टूबर में अब तक की सर्वाधिक मासिक कोयला आपूर्ति दर्ज की और यह पहली बार 7 करोड़ टन का आंकड़ा पार कर गई। देश में बिजली की बढ़ती मांग के बीच ताप विद्युत संयंत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकारी स्वामित्व वाली इस खनिक ने कोयला उत्पादन और निकासी को बढ़ा दिया था।

कंपनी ने अक्टूबर 2026 के दौरान 7.03 करोड़ टन कोयले की आपूर्ति की, जो पिछले वित्तीय वर्ष के इसी महीने में हुई 5.92 करोड़ टन की आपूर्ति के मुकाबले 19 प्रतिशत की वृद्धि है। इससे पहले का मासिक रिकॉर्ड 6.94 करोड़ टन का था, जो मार्च 2026 में बना था।

बिजली क्षेत्र को की गई आपूर्ति भी 5.71 करोड़ टन के अब तक के सर्वाधिक मासिक स्तर पर पहुंच गई। इसने मई 2024 में दर्ज 5.65 करोड़ टन के पिछले रिकॉर्ड को पछाड़ दिया। अक्टूबर में की गई यह आपूर्ति अक्टूबर 2025 में इस क्षेत्र को की गई 4.8 करोड़ टन की आपूर्ति के मुकाबले 19 प्रतिशत अधिक रही। हाल ही में देश के कई बिजली संयंत्रों में कोयले का स्टॉक खतरनाक स्तर तक कम हो चुका है, जिससे बिजली की कमी के संबंध में चिंताएं बढ़ गई हैं।



उत्पादन बढ़ा

- अक्टूबर में अब तक की सर्वाधिक मासिक कोयला आपूर्ति दर्ज की गई
- बिजली क्षेत्र को आपूर्ति भी अब तक के सर्वाधिक मासिक स्तर 5.71 करोड़ टन पर पहुंच

यह रिकॉर्ड प्रदर्शन ऐसे समय में सामने आया है, जब भारत का कोयला आयात कम हुआ है। कोयला मंत्रालय के रविवार को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार अगस्त 2026 में भारत का कुल कोयला आयात 5.83 प्रतिशत घटकर 10.457 करोड़ टन रह गया, जबकि एक साल पहले इसी महीने में यह 11.105 करोड़ टन था। देश के कोयला-आधारित बिजली संयंत्रों में मिश्रण के लिए किए जाने वाले आयात में खासी गिरावट आई।

व्हाट्सऐप के जरिये पीएफ खाते की जानकारी पाने की सुविधा शुरू

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने रविवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की सेवाओं को व्हाट्सऐप के जरिये उपलब्ध कराने की शुरुआत की। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में यह जानकारी दी। मंत्रालय के बयान के अनुसार, इस सुविधा के तहत कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के अंशधारक ईपीएफओ की सत्यापित व्हाट्सऐप सेवा के जरिये अपने पीएफ खाते में जमा राशि, पिछले पांच लेनदेन और पासबुक का ब्योरा देख सकेंगे। इसके अलावा, उन्हें व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी मिलेगा और प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएमवीबीआरवाई) से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करने में सहायता मिलेगी। इससे रोजमर्रा की सेवाएं मोबाइल फोन पर आसानी से उपलब्ध होंगी और लोगों को ईपीएफओ कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत कम पड़ेगी।

मंत्री ने ईपीएफओ के 74वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर निष्क्रिय ईपीएफ खातों के पात्र मामलों में स्वतः निपटान की सुविधा भी शुरू की। इसके तहत आधार से सत्यापित ऐसे निष्क्रिय ईपीएफ खातों के अंशधारकों को अलग से दावा आवेदन जमा करने की जरूरत नहीं होगी, जिनमें 1,000 रुपये तक की राशि जमा है। *भाषा*

आरईआई एक्सपो में जैव-ऊर्जा क्षेत्र को 3,200 करोड़ रु के निवेश प्रस्ताव : आईबीए

ग्रेटर नोएडा में हाल में आयोजित नवीकरणीय ऊर्जा इंडिया (आरईआई) एक्सपो 2026 में निवेशकों ने बायोगैस और संपीडित बायोगैस (सीबीजी) क्षेत्र में 3,200 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। उद्योग संगठन इंडियन बायोगैस एसोसिएशन (आईबीए) ने यह जानकारी दी। आईबीए के बयान के अनुसार, तीन दिन की प्रदर्शनी 22 से 24 अक्टूबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट ऐंड सेंटर में आयोजित की गई। इसने उद्योग से जुड़े पक्षों को नई कारोबारी साझेदारियों, उभरती प्रौद्योगिकियों और देश में जैव ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा के लिए मंच उपलब्ध कराया। *भाषा*

कर कानून को 'अपराध-मुक्त' करने का कदम अहम

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद द्वारा 'अपराध-मुक्त' करने और प्रवर्तन शक्तियों के युक्तिकरण पर हुए फैसलों को भारत के विश्वास पर आधारित आर्थिक शासन की ओर बदलाव की दिशा में सबसे महत्त्वपूर्ण संस्थागत सुधारों में से एक बताया है। परिषद की 8 अक्टूबर को हुई बैठक में लिए गए निर्णयों के आकलन के बाद सीआईआई ने कहा कि इन बदलावों का महत्त्व कराधान से कहीं आगे तक है।

मुख्य सुधारों में सीजीएसटी ऐक्ट की धारा 69 को हटाकर गिरफ्तारी की शक्तियों को समाप्त करने का प्रस्ताव, जुर्माना 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करना, धारा 132 के तहत निर्दिष्ट अपराधों को सीमित करना और सजा में अधिक न्यायिक विवेक के साथ कारावास के प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाना शामिल है। *बीएस*

बीएस सूडोकू 5734

परिणाम संख्या 5733

				3				
7		4		9	8			
	1				2	9		
9		2					7	6
		5			4		2	
1	2			8				5
		7				3		
6						1		

3	1	2	8	7	6	9	5	4
5	9	7	4	2	3	6	1	8
8	6	4	9	1	5	7	2	3
9	7	1	2	3	8	5	4	6
4	2	5	1	6	7	3	8	9
6	3	8	5	4	9	1	7	2
1	5	3	6	8	4	2	9	7
7	8	9	3	5	2	4	6	1
2	4	6	7	9	1	8	3	5

कैसे खेलें ? आसान

हर रो, कॉलम और 3 के बाई 3 के बॉक्स में 1 से लेकर 9 तक की संख्या भरें।

डिस्क्लेमर.. बिज़नेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट और फीचर लेखों के माध्यम से बाजारों, कॉरपोरेट जगत और सरकार से जुड़ी घटनाओं की निष्पक्ष तस्वीर पेश करने का प्रयास किया जाता है। बिज़नेस स्टैंडर्ड के नियंत्रण एवं जानकारी से परे परिस्थितियों के कारण वास्तविक घटनाक्रम भिन्न हो सकते हैं। समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्टों के आधार पर पाठकों द्वारा किए जाने वाले निवेश और लिए जाने वाले कारोबारी निर्णयों के लिए बिज़नेस स्टैंडर्ड कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से स्वयं निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है। बिज़नेस स्टैंडर्ड के सभी विज्ञापन सद्भाव में स्वीकार किए जाते हैं। इनके साथ बिज़नेस स्टैंडर्ड न तो जुड़ा हुआ है और न ही उनका समर्थन करता है। विज्ञापनों से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा संबंधित विज्ञापनदाता से ही किया जाना चाहिए। मै. बिज़नेस स्टैंडर्ड प्रा. लि. का सर्वाधिकार सुरक्षित है बिज़नेस स्टैंडर्ड प्रा. लि. से लिखित अनुमति लिए बगैर समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी सामग्री का किसी भी तरह प्रकाशन या प्रसारण निषिद्ध है। किसी भी व्यक्ति या वैधानिक निकाय द्वारा इस प्रकार का निषिद्ध कार्य किए जाने पर दीवानी और फौजदारी कार्यवाही शुरू की जाएगी।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 19 अंक 222

बैंकिंग से आगे सोचना जरूरी

केंद्र सरकार ने गत सप्ताह एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया ताकि देश के बैंकिंग क्षेत्र के हालात की समीक्षा की जा सके और यह नियामकीय, ढांचागत, संस्थागत और विधायी सुधारों की अनुशंसा कर सके। इसके पीछे उद्देश्य भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, समावेशी और इतना मजबूत बनाना है कि वह 2047 तक विकसित देश की जरूरतों को पूरा कर सके। इस समिति का गठन इस वर्ष के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के बाद किया गया है। पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश एन. पटेल की अध्यक्षता वाली इस समिति को कई महत्त्वपूर्ण विषयों की समीक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें बैंकिंग संबंधी कार्यप्रणालियां और विवेकपूर्ण नियामकीय मानदंड, मौजूदा नियामकीय एवं कानूनी ढांचा, पूंजी संबंधी आवश्यकताओं से जुड़े मुद्दे (विकास वित्तीय संस्थानों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित) तथा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण ढांचा शामिल हैं। समिति को बैंकिंग क्षेत्र में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस और डिजिटल नवाचार का रोडमैप तैयार करने की जिम्मेदारी भी दी गई है।

वर्तमान स्थिति का आकलन करने और भविष्य की संभावनाओं के साथ-साथ उनसे जुड़े नियामकीय एवं कानूनी ढांचे की समीक्षा करने वाली किसी भी पहल का स्वागत किया जाना चाहिए। भारत को मुख्य रूप से बैंक वित्तपोषण पर निर्भर अर्थव्यवस्था माना जाता है। एक कुशल बैंकिंग प्रणाली बचत को वास्तविक निवेश में लगाने में मदद कर सकती है। समिति के कार्यक्षेत्र में भी लगभग सभी महत्त्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है। हालांकि यह बैंकिंग प्रणाली के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेगी लेकिन कुछ विशिष्ट मुद्दों पर इसकी टिप्पणियों का विशेष रूप से इंतजार रहेगा। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक और नई पीढ़ी के पेमेंट्स बैंक तथा स्मॉल फाइनैंस बैंक मौजूद हैं।

इससे बैंकिंग क्षेत्र काफी विविधतापूर्ण और गतिशील बना है। विभिन्न अनुमानों से पता चलता है कि देश में ऋण की मांग का एक बड़ा हिस्सा अब भी पूरा नहीं हो पा रहा है। मसलन नीति आयोग की 2025 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2020-21 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की ऋण संबंधी मांग का केवल 19 फीसदी हिस्सा ही औपचारिक स्रोतों के माध्यम से पूरा हो पाया था। वास्तव में समिति के लिए यह एक अच्छा शुरुआती बिंदु हो सकता है। आखिर ऋण की इतनी बड़ी मांग अधूरी क्यों रह जाती है?

यह भी देखना होगा कि क्या आज भारत को इतने अधिक सरकारी बैंकों की आवश्यकता है। याद रहे कि वैश्विक वित्तीय संकट के बाद केंद्र सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बड़े पैमाने पर पूंजी डालनी पड़ी थी। सरकारी बैंकों के लिए अलग मानदंड के मुद्दे पर भी बहस होती रही है। सामान्य रूप से नियमन को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने की जरूरत है। उदाहरण के लिए इस वर्ष की शुरुआत में एक बड़े निजी बैंक के चेयरमैन ने प्रशासनिक और नैतिक मुद्दों का हवाला देते हुए अचानक इस्तीफा दे दिया था। ये मुद्दे वास्तव में क्या थे यह अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है। बड़े बैंक पूरी वित्तीय व्यवस्था के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं इसलिए ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

समिति प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के ढांचे से जुड़े बहुचर्चित मुद्दे की भी समीक्षा करेगी। कई लोगों का मानना है कि इस ढांचे में बदलाव की जरूरत है। सभी बैंकों से एक जैसे काम की अपेक्षा का कोई औचित्य नहीं है। उम्मीद है कि समिति सांविधिक तरलता अनुपात बनाए रखने से जुड़ी आवश्यकताओं सहित नियामकीय प्रावधानों की व्यापक समीक्षा करेगी। यह देखना होगा कि बाजार अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता के हित में क्या इन आवश्यकताओं को धीरे-धीरे कम करने की जरूरत है? क्या ऐसे प्रावधान बैंकिंग क्षेत्र में रुचि को प्रभावित कर रहे हैं?

समिति इन मुद्दों की समीक्षा करेगी लेकिन ध्यान रखना जरूरी है कि बैंक व्यापक वित्तीय प्रणाली का केवल एक हिस्सा हैं। एक बड़ी, विकासशील और जटिल अर्थव्यवस्था में वित्तपोषण यानी धन की जरूरतें विभिन्न प्रकार के वित्तीय संस्थानों और साधनों के माध्यम से पूरी होती हैं। इसलिए भारतीय वित्तीय क्षेत्र के कामकाज की समग्र रूप से समीक्षा करने की आवश्यकता है। इसके बावजूद उच्चस्तरीय बैंकिंग समिति का गठन सही दिशा में उठाया गया कदम है। सरकार को अपने इस प्रयास का दायरा और व्यापक करना चाहिए तथा भारत को विकसित देश बनाने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं की समीक्षा करनी चाहिए।

नेतन्याहू का न हारना ही उनकी जीत

यह नेतन्याहू की जीत है क्योंकि उन्हें हराया नहीं जा सका है। उन्होंने इजरायल को भी पूरी तरह बदल दिया है। इजरायल में शांति के नाम पर वोट मांगना लगभग असंभव हो गया है।

करीब एक दशक पुराने दोस्तों डॉनल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने पश्चिमी उदारवादियों और वामपंथियों के नफरत करने वाले लोगों की सूची में शीर्ष स्थान पर कब्जा कर रखा है। उनके राजनीतिक पराभव की कामना की जाती रही है लेकिन दोनों अपने विरोधियों को निराश करते रहे हैं।

ट्रंप दो बार राष्ट्रपति बन गए। उन्होंने उदारवादियों के मखौल और उनकी अवज्ञा को धता बताया। नेतन्याहू 2021-22 की एक साल की नफ्ताली बेनेट और यायर लैपिड की बाधा को छोड़ विगत 17 में से 16 सालों से सत्ता में रहे हैं।

इस बार उन्हें जनादेश नहीं मिला लेकिन उन्होंने सबसे अधिक सीटें हासिल कीं, उन्हें धुर दक्षिणपंथ का समर्थन हासिल है। वह गठबंधन बनाने की हालत में हैं और वह एक नए चुनाव का माहौल भी बना सकते हैं जो इजरायल के लिए नया नहीं है।

इसे केवल इसलिए नेतन्याहू की जीत कहा जाएगा क्योंकि उन्हें हराया नहीं गया। उन्होंने हमास की 'मदद' से इजरायल को बुनियादी रूप से बदल दिया है।

किसी अन्य परिस्थिति में संभव था कि गादी आइजेनकोट अपने गठबंधन को 48 सीटों से बढ़ाकर बहुमत के लिए जरूरी 61 सीटों से आगे ले जा सकते थे। इसके लिए बस उन्हें दोनों अरब पार्टियों के साथ गठबंधन करना पड़ता। इनमें से एक पार्टी, रा'म 2021-22 में नफ्ताली बेनेट और यायर लैपिड के अल्पकालिक गठबंधन में शामिल हुई भी थी।

लेकिन अब कोई भी यहूदी राजनीतिक दल अरब पार्टियों को तब तक अपने साथ नहीं ले सकता जब तक वे हमास को आतंकी संगठन घोषित न करें। अरब पार्टियां ऐसा नहीं करेंगी इसलिए इजरायल के अरब नागरिकों को बाहर रखकर ही कोई गठबंधन बन सकेगा। इस तरह नेतन्याहू और हमास ने इजरायल को बदल दिया है।

अमेरिका में होने वाले मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेट कुछ हद तक राजनीतिक संतुलन बहाल कर सकते हैं लेकिन वह हकीकत नहीं बदलेगी जिसने ट्रंप को लगभग असीमित सत्ता तक पहुंचाया। आव्रजन, व्यापार और मानवाधिकारों के मामले में उनका प्रभाव उनके सत्ता से हटने के बाद भी लंबे समय तक बना रहेगा। हमें यह स्वीकार करना होगा कि मतदाता भावनाओं से प्रभावित होते हैं लेकिन उनके फैसले तर्कसंगत भी होते हैं। अर्थव्यवस्था महत्त्वपूर्ण है, लेकिन तीन चीजें उनकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर हैं-राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा और पहचान का संरक्षण।

ट्रंप ने दूसरा चुनाव कानून-व्यवस्था, आव्रजन और उनके शब्दों में 'सबसे ऊपर' राजनीतिक शुद्धता के मुद्दे पर केंद्रित किया। इसमें अकादमिक जगत में विविधता, समानता और समावेशन (डीईआई) को लेकर बढ़ती बहस, लैंगिक पहचान की तरलता और खुली सीमाओं जैसे मुद्दे शामिल थे।

इजरायल का चुनाव राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित था। इजरायलियों के लिए 7 अक्टूबर 2023 का दिन होलोकॉस्ट के बाद का सबसे भयावह अनुभव था। इस घटना ने इजरायल को बदल दिया और बाद में शुरू हुए युद्धों के लिए जनसमर्थन तैयार किया और नेतन्याहू को सत्ता विरोधी लहर से बचाए रखा। भारत सहित लोकतांत्रिक देशों में उदारवादी विमर्श में प्रचलित रूढ़ धारणाओं के विपरीत इजरायल में गहरी बहस और लोकतांत्रिक परंपरा मौजूद है। वहां उदारवादी और मुखर मतदाताओं का एक मजबूत वर्ग है जो फिलिस्तीनियों के प्रति सहानुभूति रखता है। पश्चिमी किनारे में बस्तियों के निवासियों की हिंसा का विरोध करता है और यहां तक कि दो-राष्ट्र समाधान का समर्थन भी करता है।



राष्ट्र की बात
शेखर गुप्ता

मैंने दशकों से हारेत्ज नामक इजरायली अखबार की सदस्यता ले रखी है। यह भारत के किसी भी मुख्यधारा के अखबार की तुलना में कहीं अधिक वामपंथी रुख रखता है। वह नेतन्याहू की आलोचना करता है और उसने ऐसी खबरों का खुलासा किया है जिनसे राजनीतिक रूप से उन्हें भारी नुकसान पहुंचना चाहिए था। इनमें यह खबर भी शामिल है कि 7 अक्टूबर से पहले उन्होंने मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात की चेतावनियों को नजरअंदाज किया था। यह आरोप भी लगाया जाता रहा है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया।

दूसरी ओर अति-रूढ़िवादी यहूदी राजनीतिक दल हैं जो पश्चिमी किनारे और गाजा से सभी फिलिस्तीनियों को बेदखल करना चाहते हैं। इजरायली समाज में गहरे मतभेद हैं और वहां अंधभक्ति की परंपरा नहीं है। लेकिन ये विभाजन चुनाव में दिखाई नहीं दिए। यहूदियों ने दो कट्टरपंथी नेताओं में से एक को चुना। 21 फीसदी अरब अल्पसंख्यक वर्ग को आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली चुनाव प्रणाली में सीटें तो मिलती हैं लेकिन अंततः उनके वोटों का कोई खास महत्त्व नहीं रह जाता क्योंकि सुरक्षा और अस्तित्व के सवाल पर बहुमत एकजुट हो जाता है। नेतन्याहू ने ही जनरल गादी आइजेनकोट को इजरायल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) का प्रमुख नियुक्त किया था। आइजेनकोट के सैनिक बेटे की गाजा में लड़ते हुए मौत हो गई और वे भी हमास का सफाया करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पर्याप्त संख्या में मतदाताओं ने बदलाव का जोखिम उठाने के बजाय निरंतरता को चुना। यहां विचार करने की जरूरत है कि कभी इजरायल में ताकतवर रहा वामपंथ अचानक कब और क्यों अप्रासंगिक हो गया? और दूसरा, वहां के अरब नागरिकों के भारी चुनावी समर्थन का कोई महत्त्व क्यों नहीं रह गया?

इजरायल में वामपंथ (लेबर) के वर्चस्व का दौर भारत में बहुत अधिक याद नहीं किया जाता। डेविड बेन-गुरियन, गोल्डा मायर, लेवी एश्कोल और यित्जाक राबिन आधुनिक इजरायल के महानतम जायोनी नेता और संस्थापक सभी लेबर पार्टी से थे। दिग्गज लेफ्टिनेंट जनरल मोशे दयान लेबर के समाजवादी और स्वयं को जायोनी नास्तिक घोषित करने वाले नेता थे। 1977 में उन्होंने लेबर छोड़कर मेनाखेम बेगिन के लिकुड गठबंधन का समर्थन किया और विदेश मंत्री के रूप में मिस्र के साथ शांति के लिए कैंप डेविड समझौते पर बातचीत की।

1948 से 1977 तक इजरायल की राजनीति में लेबर का पूरी तरह वर्चस्व रहा। बेगिन की लिकुड पार्टी ने इसे तोड़ा। इसके बाद शिमोन पेरेज, राबिन और एहुद बराक के नेतृत्व में लेबर को 1984, 1992, 1995 और 1999 में कुछ समय के लिए सत्ता में वापसी का मौका मिला लेकिन इसके बाद उसका प्रभाव धीरे-धीरे खत्म होता चला गया।

1992 से 2000 के बीच लेबर पार्टी ने ओस्लो समझौते के तहत बातचीत के जरिए मिस्र की तर्ज पर शांति स्थापित करने की कोशिश की लेकिन यह प्रयास विफल रहा। इस दौरान फिलिस्तीनी हमले और आत्मघाती बम विस्फोट बढ़ते गए। पहली बार यह प्रक्रिया राबिन की हत्या के साथ समाप्त हुई और फिर 2000 में दूसरा इंतिफादा (फिलिस्तीनी विद्रोह) शुरू होने की स्थिति बन गई। आखिरकार इजरायलियों को लेबर की 'शांति के बदले जमीन' की अवधारणा अव्यावहारिक और दिशाहीन लगी। तब से इजरायल में शांति के नाम पर वोट मांगना लगभग असंभव हो गया है। विडंबना यह है कि भारत सहित दुनिया के अधिकांश देश दो-राष्ट्र समाधान का समर्थन करते हैं लेकिन इस संघर्ष के दोनों प्रत्यक्ष पक्षों में से कोई भी इसे स्वीकार नहीं करना चाहता।

अरब मतों का महत्त्व इतना नगण्य होने पर भी हमें गंभीरता से अध्ययन करने की जरूरत है क्योंकि हाल के दिनों में भारत में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था अपनाने की मांग उठी है। माना जाता है कि इससे अल्पसंख्यक समुदायों को उनकी आबादी के अनुपात में सीटें मिल सकेंगी। इजरायल का अनुभव इस धारणा की एक कठोर वास्तविकता से सामना कराता है। वहां मुख्य रूप से मुस्लिम अरब समुदाय की आबादी इजरायल की कुल आबादी के 20 फीसदी से अधिक है। वे सरकार, कारोबार और यहां तक कि सशस्त्र बलों में भी काम करते हैं हालांकि उन्हें अनिवार्य सैन्य सेवा से छूट मिली हुई है। हाल ही में उन्होंने रिकॉर्ड संख्या में वोट हासिल किए जिसके परिणामस्वरूप 120 सदस्यीय नेसेट (इजरायली संसद) में उन्हें 19 सीटें मिलीं। इजरायल के राजनीतिक परिदृश्य में वे राष्ट्रवाद की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। वे 7 अक्टूबर की घटना की 'निंदा' तो करते हैं लेकिन उसे आतंकवाद नहीं कहते और न ही हमास को आतंकवादी संगठन मानते हैं।

यदि भारत में आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था लागू कर दी जाए और मुस्लिम पार्टियों को उनकी आबादी के अनुपात में सीटें मिलें (543 में से लगभग 80) तो क्या कोई 'धर्मनिरपेक्ष' गठबंधन उन्हें अपने साथ स्वीकार करेगा अगर वे पाकिस्तानी या हुर्रियत के झंडों अथवा प्रतीकों के साथ जश्न मनाएं? या लश्कर और जैश को आतंकवादी संगठन कहने से इनकार कर दें?

यह किसी भी चुनावी लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों के लिए सबक है। उन्हें खुद को अलग-थलग करने से बहुत कम लाभ होता है। उन्हें मुख्यधारा के उन राजनीतिक समूहों के साथ गठबंधन करना होगा जिन्हें वे स्वीकार्य मानते हैं और मिलकर एक व्यापक गठबंधन तैयार करना होगा। इसके लिए वैचारिक समझौते और राष्ट्रवाद के प्रति अडिग प्रतिबद्धता दोनों की जरूरत है। इसी तरह 25 वर्षों के गठबंधन राजनीति के दौर में भारत में मुस्लिम वोट ने राजनीतिक ताकत हासिल की थी। दूसरा रास्ता यह है कि आप आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग करें और अपने वोटों की संख्या तो जुटा लें लेकिन इजरायल के अरब नागरिकों की तरह राजनीतिक रूप से हाशिये पर चले जाएं।

पेशेवरों और प्रवर्तकों के बीच असहज करने वाला द्वंद्व

टाटा संस में मची उठापटक ने प्रवर्तकों, पेशेवर प्रबंधकों और निदेशकमंडल (बोर्ड) के बीच वह खाई उजागर कर दी है जिससे भारतीय कंपनी जगत को लगातार जूझना होता है। भारतीय कंपनी जगत में इस बात को लेकर अटकल तेज हैं कि आखिर यह सब कैसे हुआ। साथ ही, इसे लेकर भी चिंता है कि भविष्य में संचालन के ढांचे पर इसके क्या दूरगामी असर होंगे।

यह न तो नियंत्रण पाने के लिए अंशधारकों समूहों के बीच की कोई मामूली लड़ाई है और न ही किसी प्रवर्तक द्वारा मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) को अचानक नौकरी से बाहर कर देने का मामला है। ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। मगर यह शायद पहली बार है जब एक पेशेवर प्रबंधक -सीईओ ने (जिसे बोर्ड का समर्थन हासिल है और गैर-अंशधारक सरकारी संस्थाओं का भी साथ है) 66फीसदी हिस्सेदारी रखने वाले प्रवर्तक को ही प्रमुख निर्णयों से दरकिनार करने की कोशिश की है। ये निर्णय न केवल कारोबार की दिशा प्रभावित करते हैं बल्कि प्रवर्तक की हिस्सेदारी पर भी असर डालते हैं।

भारत में प्रवर्तकों को कंपनी के बुनियादी निर्माता का दर्जा प्राप्त है जिनके पास कुछ विशेष अधिकार और जिम्मेदारियां होते हैं। इनमें कुछ कानून में दर्ज हैं तो कुछ हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं।

भारत में सीईओ और अंशधारकों के बीच टकराव के दो ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। इनमें आईटीसी और लार्सन ऐंड टुब्रो (एलऐंडटी) का जिक्र किया जा सकता है। आईटीसी के मामले में यह लड़ाई प्रवर्तक ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको (बीएटी) के खिलाफ थी जो कंपनी पर नियंत्रण पाना चाहती थी और कारोबार विस्तार रोकना चाहती थी। वहीं, एलऐंडटी के मामले में यह लड़ाई एक प्रभावशाली अंशधारक समूह के खिलाफ थी जहां सीईओ ने प्रबंधन पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष किया था। दोनों ही मामलों में सरकार ने सीईओ का समर्थन किया। उसने ऐसा अपने नियंत्रण वाली वित्तीय संस्थाओं के जरिये 30 से 40 फीसदी हिस्सेदारी का इस्तेमाल कर किया जो पूंजीवाद के 'जिसकी लाठी, उसकी भैंस' कहावत के अनुरूप है।



रमा बीजापुरकर

टाटा संस के मामले की खास बात यह है कि इसमें सरकार के नियंत्रण वाली संस्थाओं के पास शेयरों का बड़ा हिस्सा नहीं है और यहां जंग का मैदान सालाना आम सभा (एजीएम) या असाधारण आम सभा (ईजीएम) नहीं है। बिना किसी अंशधारक के समर्थन वाले सीईओ और ऐसे बोर्ड सदस्य (जो किसी बड़े अंशधारक समूह का प्रतिनिधित्व नहीं करते) मिलकर 66 फीसदी हिस्सेदारी वाले प्रवर्तक को चुनौती दे सकते हैं, उन पर अपनी हिस्सेदारी कम करने का दबाव डाल सकते हैं और फैसलों पर उनका नियंत्रण भी नहीं रहने देते। यह सत्ता के उन ढांचों के लिए एक नई तरह की चुनौती है जो समय, परंपरा, रीति-रिवाजों और संस्कृति की कसौटी पर (भले ही सही हो या गलत) लंबे समय से टिके हुए थे। इससे प्रवर्तकों को पेशेवर सीईओ और बोर्ड के साथ अपने संबंधों और काम करने के तरीकों पर फिर से विचार करने की जरूरत पड़ गई है।

भारत में पेशेवर प्रबंधकों और प्रवर्तकों के बीच हमेशा कुछ न कुछ तनाव रहा है। इनके बीच के मतभेद अक्सर सीईओ के इस्तीफा देने पर खत्म होते हैं। ये मतभेद कई मोर्चों पर हो सकते हैं यानी कंपनी की दिशा, जोखिम लेने की क्षमता और समझदारी, कारोबारी महत्त्वाकांक्षाएं या फिर वेतन-भत्ते (हालांकि, हाल के दिनों में सीईओ के वेतन और शेयर विकल्प काफी बढ़ गए हैं, इसलिए वेतन को लेकर विवाद कम हुए हैं)। अक्सर विवाद इस बात पर भी होता है कि किस तरह के निर्णय लेने की असली ताकत किसके पास है यानी क्या यह 'वास्तविक मालिक' (प्रवर्तक) के पास है या 'देखभाल करने वाले' (पेशेवर सीईओ) के पास?

भारत में अभी भी प्रबंधन और स्वामित्व का अलग-अलग होना आम बात नहीं है, हालांकि इसके कुछ शुरुआती उदाहरण सामने आने लगे हैं। शेयर बाजार के दिग्गज जानकारों का मानना है कि प्रबंधन में मालिक की मौजूदगी अच्छी होती है क्योंकि इससे अंशधारकों का महत्त्व बढ़ाने पर साझा ध्यान बना रहता है। कई कर्मचारी भी यही चाहते हैं कि कंपनी की कमान प्रवर्तक के हाथ में हो क्योंकि उन्हें लगता है कि सीईओ या बोर्ड के मुकाबले प्रवर्तक के होने से चीजें अधिक भरोसेमंद और कर्मचारियों के प्रति अधिक उदार हो सकती हैं। यहां तक कि इन्फोसिस जैसी कंपनी में भी (जिसे पेशेवरों ने ही शुरू किया था) इसके 'संस्थापक' (जो स्वयं को यही कहलाना पसंद करते थे) बारी-बारी से कंपनी चलाते थे जो उनकी पहले से तय योजना के अनुसार होता था। टाटा समूह ने हमेशा निजी लाभ के बजाय न्यासी की तरह काम करते हुए व्यापक जनहित को प्राथमिकता दी है। इस टकराव के क्या नतीजे होंगे यह अभी साफ नहीं है। क्या किसी पेशेवर अधिकारी द्वारा किए गए ऐसे बड़े उलटफेर को देखकर प्रवर्तक घबरा जाएंगे? वे इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? क्या वे पुराने दिनों की तरह वफादारी और केवल किसी खास विषय की जानकारी के आधार पर बोर्ड के सदस्यों को चुनेंगे? खासकर तब, जब देश का कानून और बाजार नियामक स्वतंत्र निदेशकों को अधिक अधिकार और जवाबदेही सौंप रहे हैं? क्या बोर्ड पर अब बाहरी निर्देशों का दबाव और बढ़ेगा कि उन्हें किसके पक्ष में वोट देना है? क्या वे प्रवर्तकों और किसी बड़ी ताकत द्वारा हस्तक्षेप बीच फंस जाएंगे? क्या सीईओ के पास काम करने की स्वतंत्रता कम हो जाएगी और उन पर पाबंदियां बढ़ जाएंगी और क्या इससे भारत की उस छवि को और नुकसान पहुंचेगा जो हाल के दिनों में एक सुरक्षित और स्थिर निवेश गंतव्य के रूप में बनी थी? शायद इन सभी सवालों का जवाब 'हां' है।

चूंकि, इस पूरी बहस का एक मुख्य आधार टाटा संस का राष्ट्रीय और व्यापक महत्त्व है इसलिए इसके बोर्ड को अपने कई बार बदले गए फैसलों के पीछे के कारणों को लेकर अधिक पारदर्शी रुख अपनाने की जरूरत है।

(लेखिका ग्राहक-आधारित कारोबारी रणनीति के क्षेत्र में एक कारोबार सलाहकार हैं)

आपका पक्ष

प्रदूषण रोकने को सार्वजनिक वाहनों का करें इस्तेमाल

जब दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है तब इससे निपटने के लिए सख्त पाबंदियां लगाई जाती हैं। दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए 1 नवंबर से बीएस 6 मानक से कम वाले दूसरे राज्यों के पेट्रोल-डीजल वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। वहीं, आपातकालीन वाहनों को इससे छूट दी गई है। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण के बहुत से कारण हो सकते हैं। इसके लिए विशेषज्ञों को काम करना चाहिए तथा उन्हें इसका हल निकालना चाहिए। अब तक दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण के लिए पराली और पटाखे ही सबसे बड़े कारण बताए जाते रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि सर्दियों में वातावरण में एक शीत परत बन जाती है जो दूषित हवा को बेअसर नहीं होने नहीं देती। वह एक दायरे तक सीमित रहती है और जब तक



दिल्ली में रविवार को जामा मस्जिद के ऊपर धुएं की चादर छाई रही तथा वायु गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में पहुंच गई

बारिश न हो तब तक यह प्रदूषित हवा धरती के करीब ही रहती है। वायु प्रदूषण साल दर साल चुनौती बनती जा रही है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को रोकने के लिए सरकार को दोषी ठहराना शायद समझदारी नहीं है क्योंकि वायु प्रदूषण को बढ़ाने के लिए आम लोग भी कम जिम्मेदार नहीं है। बढ़ते प्रदूषण से जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ने की आशंका है। अभी भी वक्त है प्रदूषण को रोकने के ठोस उपाय किए जाएं और इसके लिए सरकार तथा लोगों को बिना किसी स्वार्थ के एकजुट होकर प्रयास करने होंगे। लोगों को अपने वाहनों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए तथा सार्वजनिक वाहनों से यात्रा करनी चाहिए। यह पहल भी दिल्ली और इसके आसपास क्षेत्रों में प्रदूषण को कुछ कम करने के लिए अच्छी होगी।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

डिजिटल धोखाधड़ी पर उच्चतम न्यायालय सख्त

उच्चतम न्यायालय ने पिछले दिनों कहा कि बैंकों को डिजिटल अरेस्ट जैसे डिजिटल धोखाधड़ी पीड़ितों को मुआवजा देने की आवश्यकता हो सकती है। शीर्ष अदालत यह भी चाहती है कि बैंक किसी ग्राहक के सामान्य लेनदेन पैटर्न से असंगत लेनदेन को अस्थायी रूप से निलंबित करें और संदिग्ध गतिविधियों की स्वतः रिपोर्ट करें तथा नजदीकी पुलिस थानों को अलर्ट करें। ये तंत्र निश्चित रूप से निर्दोष ग्राहकों की रक्षा करेंगे और धोखाधड़ी को रोकेंगे। हालांकि, बैंकों को वास्तविक समय के धोखाधड़ी पहचान प्रणालियों, लेनदेन निगरानी और ग्राहक सहायता क्षमता में भारी निवेश करना पड़ सकता है। अगर बैंक असामान्य लेनदेन को निलंबित करते हैं तो बड़े, तात्कालिक या पहली बार भुगतान करने वाले वास्तविक ग्राहकों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। वहीं, नुकसान किसने किया इसकी जांच भी काफी समय ले सकती है। अगर बैंक केवाईसी सुरक्षा उपायों को लागू करने में विफल रहते हैं और म्यूल खातों को बिना रोकटोक संचालित होने देते हैं, तो उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। बैंकों, आरबीआई और साइबर पुलिस के बीच बेहतर समन्वय भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है।

बाल गोविंद, नोएडा

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई



विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर अटलांटा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में उनकी आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया। मंत्री ने शनिवार को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने के लिए बड़ी संख्या में जुटे भारतीय प्रवासियों से संवाद भी किया।

विदेशी मेहमानखानों में बिछेंगे सीतापुर के दरी, कालीन, गलीचे

एसएमई की बात

भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले लघु एवं मझोले उद्योगों (एसएमई) पर केंद्रित हमारी नई विशेष श्रृंखला आज शुरू हो रही है। इसमें शहरों और क्लस्टरों में फैले छोटे उद्योगों की उपलब्धियों, उनकी जमीनी समस्याओं और सुधार के सुझावों को प्रमुखता से उजागर किया जाएगा

सिद्धार्थ कलहंस
लखनऊ, 1 नवंबर

उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में सदियों से फल-फूल रहे दरी उद्योग के बनाए उत्पाद अब विदेशों में भी घरों की रौनक बढ़ाने जा रहे हैं। यहां तैयार होने वाली उम्दा किस्म की दरियों की मांग तमाम राज्यों में तो पहले ही है, अब फिजी, पनामा, सऊदी अरब और दक्षिण अफ्रीका के बाजारों में भी ये दरियां बिकेंगी।

सीतापुर में अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में आयोजित बायर-सेलर मीट के दौरान नौ देशों के खरीदार यहां की दरियां जांचने-परखने पहुंचे। इनमें से फिजी, पनामा और सऊदी अरब के खरीदारों ने मौके पर ही ऑर्डर दे दिए। दूसरे देशों के प्रतिनिधि बाद में सौदे करने की बात कहकर नमूने ले गए। बायर-सेलर मीट में हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के थोक व फुटकर कारोबारी भी पहुंचे थे।

दरी से योगा मैट, रनर तक

सीतापुर में हाथ से बन रही दरियों की सबसे ज्यादा मांग महाराष्ट्र और दक्षिण के राज्यों में है। मुंबई, नाशिक, पुणे जैसे शहरों में यहां की सूती दरियां सबसे ज्यादा जाती हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक में ऊनी दरियों की मांग है। भारी मांग पूरी करने के लिए सीतापुर के बुनकर पहले घरों में इस्तेमाल होने वाली दरी ही बनाते थे मगर बदलते दौर में उन्होंने योगा मैट, बेडसाइड रनर और सेंटर टेबल रनर जैसे उत्पाद बनाकर विदेशों में भेजना भी शुरू कर दिया है। जिले के खैराबाद कस्बे में बुनकर सूती और ऊनी दरियों के साथ कालीन और गलीचे भी बनाने लगे हैं।

जिले में 30,000 से ज्यादा परिवार दरी की बुनाई से जुड़े हैं। दरी कारोबारी आरडी मिश्रा बताते हैं कि 20 फीसदी बड़े कारोबारी पावरलूम चलाते हैं। लेकिन ज्यादा मांग हाथ से बुनी दरियों की है। बीच में चीन से आने वाली मशीन की दरियों ने सीतापुर के माल की मांग गिरा दी थी मगर अब चीन ही नहीं भारत में लुधियाना की पावरलूम दरियों से भी ज्यादा ग्राहक सीतापुर की दरियों के हैं।

सदियों पुराना दरी उद्योग

- अमेरिका, यूरोप के साथ फिजी, पनामा, सऊदी अरब और दक्षिण अफ्रीका के खरीदारों तक पहुंचेगी सीतापुर की दरी
- योगा मैट, बेड साइड रनर और सेंटर टेबल रनर भी जा रहे विदेश
- सीतापुर में 30,000 से ज्यादा परिवार बुनते हैं दरी, कालीन और गलीचे
- इस बार सालाना कारोबार 1,000 करोड़ रुपये तक ले जाने का लक्ष्य



कारोबार की तेज रफ्तार

नामचीन बुनकर राजा अंसारी बताते हैं कि सीतापुर में 20 रुपये प्रति वर्ग फुट से 300 रुपये प्रति वर्ग फुट तक कीमत वाली दरियां तैयार की जाती हैं। हाथ की बारीक बुनाई वाली ऊन की दरियां और गलीचे सबसे महंगे हैं, जबकि सूती दरियां सस्ती पड़ती हैं। योगा मैट 60 रुपये से शुरू होकर 500 रुपये तक मिल जाती हैं। इसी तरह हथकरघे पर तैयार बेडरनर मंहगा और पावरलूम पर बना सस्ता बिकता है। यहां के उत्पाद ओडीओपी मार्ट के साथ कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी मिलते हैं।

इन बदलावों से सीतापुर से दरी का कारोबार तेज रफ्तार से दौड़ने लगा है। 2021-22 में इस उद्योग का कारोबार 150 से 200 करोड़ रुपये रहा था मगर 2024-25 में यह 400 करोड़ रुपये के पार निकल गया। चालू वित्त वर्ष में कारोबार 1,000 करोड़ रुपये तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है।

अंग्रेजों ने बनाया दरी का अड्डा

सीतापुर में दरी उद्योग 200 साल से भी ज्यादा पुराना है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17 वीं व 18 वीं सदी में खैराबाद व दरियाबाग में हथकरघा निर्यात केंद्र खोले थे। बाद के दिनों में बुनकरों की तादाद बढ़ी, काम फैला और सीतापुर की दरी आम लोगों को भी आसानी से कम दामों पर मिलने लगी। कुछ समय से तराई क्षेत्र में कपास की खेती खत्म हुई तो बुनकर सूती दरी के लिए कच्चा माल गुजरात और महाराष्ट्र से तथा ऊन पंजाब से मंगाते हैं। खैराबाद के दरी कारोबारी हकीम अंसारी का कहना है कि पहले के जमाने में यहां का माल साइकलों पर रख कर गांव-गांव बेचा जाता था मगर अब बाहर के व्यापारी माल का नमूना देखकर ऑलाइन आर्डर कर देते हैं।

ओडीओपी की संजीवनी

योगी आदित्यनाथ सरकार के महत्त्वाकांक्षी एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) कार्यक्रम में शामिल किए जाने के बाद सीतापुर के दरी उद्योग को पंख लग गए हैं। सदियों से हाथ से बुनी जा रही इन दरियों को अब तकनीक और बाजार की जुगलबंदी मिल रही है, जिससे देश में भी इनका बाजार गहरा रहा है। ओडीओपी में शामिल करने के बाद सरकार ने खैराबाद, बिसवां और लहरपुर कस्बों में छितरे हुए दरी कारोबार को व्यवस्थित करने और नए जमाने के मुताबिक ढालने की नीयत से कॉमन फैसिलिटी सेंटर तथा डाइंग सेंटर शुरू किया है। सीएफसी में दरी बुनकरों को एक ही छत के नीचे डिजाइन और कच्चे माल के साथ के साथ बाजार से संपर्क की सुविधा मिल जाती है। डाइंग सेंटर में दरियों को आधुनिक तकनीक और नए तरीके से रंगने की सुविधा मिल रही है। यहां के बुनकरों को अब सब्सिडी के साथ 50 लाख रुपये तक का कर्ज मिल रहा है और हर साल सैकड़ों बुनकरों को बेहतर तकनीक का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

मध्य प्रदेश में एमएसएमई के लिए बनेगी अलग कंपनी

अगले दो महीने में सभी जिलों में एमएसएमई इकाइयों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी जमीन

संदीप कुमार
भोपाल, 1 नवंबर

मध्य प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के विकास को समुचित गति प्रदान करने और उनकी औद्योगिक जरूरतें पूरी करने के लिए राज्य सरकार अलग से एक एमएसएमई औद्योगिक विकास कंपनी (एमएसएमई-आईडीसी) गठित करेगी। यह पूरी तरह से राज्य सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी होगी और प्रदेश के भीतर एमएसएमई इकाइयों के लिए औद्योगिक बुनियादी ढांचा, जमीन तथा अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को अपने आवास पर इसकी घोषणा की।

नई कंपनी मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी) की तर्ज पर काम करेगी, लेकिन इसका पूरा ध्यान एमएसएमई क्षेत्र पर ही रहेगी। एमपीआईडीसी मुख्य रूप से 500 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाले बड़े उद्योगों के लिए औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकसित करने का काम करता है। आज घोषित नई कंपनी के गठन से छोटे और मझोले उद्यमों के लिए भी औद्योगिक जमीन तथा बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की सरकार की योजना है।



मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास में एमएसएमई इकाइयों को सब्सिडी की राशि प्रदान की

निजी निवेश से औद्योगिक पार्क

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले दो महीने में प्रदेश के सभी जिलों में एमएसएमई इकाइयों के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा निजी निवेशकों को औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा। प्रोत्साहन के लिए सरकार ऐसे निवेशकों को 50 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान देगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य उद्योग से जुड़े बुनियादी ढांचे के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना और प्रदेश के सभी क्षेत्रों में एमएसएमई इकाइयों के लिए निवेश के अवसर तैयार करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का भविष्य निवेश, उद्योग और नवाचार पर टिका हुआ है। इसलिए राज्य सरकार उद्यमियों के नवाचार और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव सहयोग उपलब्ध कराएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 75 औद्योगिक भूखंडों के लिए आशय-पत्र भी प्रदान किए। इन भूखंडों पर लगभग 83 करोड़ रुपये का निवेश होने की संभावना है और रोजगार के 640 नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है।

एमएसएमई और स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के माध्यम से 900 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को 450 करोड़ रुपये से अधिक तथा 120 से अधिक स्टार्टअप को 47.80 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि भेजी। इस अवसर पर एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि पिछले एक वर्ष में उद्यमियों को 1,250 औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराए गए हैं। चालू वित्त वर्ष में यह संख्या बढ़कर 3,000 हो जाएगी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2028 तक प्रदेश में 30 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने और कुल 5,000 उद्योगों को भूखंड उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

उद्यमियों की बढ़ीं उम्मीद

एसोसिएशन ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज मंडीदीप के पूर्व प्रेसिडेंट और संरक्षक राजीव अग्रवाल ने बिज़नेस स्टैंडर्ड से कहा, 'नई कंपनी बनने से सबसे बड़ा फायदा एमएसएमई उद्योगों के लिए औद्योगिक जमीन आसानी से मिलना सबसे बड़ा फायदा हो सकता है। सबसे बड़ा लाभ औद्योगिक जमीन की उपलब्धता का आसान होना हो सकता है। सरकार ने दो महीने के भीतर प्रदेश के हर जिले में उद्योगों के लिए जमीन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। निजी निवेशकों को औद्योगिक पार्क विकसित करने की अनुमति और प्रति हेक्टेयर 50 लाख रुपये की सरकारी सहायता देने का प्रावधान छोटे उद्योगों के लिए बेहतर औद्योगिक बुनियादी ढांचा तैयार करने में मददगार हो सकता है। इससे सेक्टर आधारित औद्योगिक पार्क, छोटे आकार के भूखंड और साझा सुविधाएं विकसित करने की संभावनाएं बढ़ेंगी। यदि प्लग-एंड-प्ले और फ्लैटेड फैक्ट्री जैसी सुविधाएं भी प्रभावी ढंग से विकसित होती हैं, तो उद्यमियों को अपनी फैक्ट्री के लिए पूरा बुनियादी ढांचा अलग से तैयार करने की जरूरत कम होगी।'

उन्होंने कहा कि इस पहल से औद्योगिक विकास बड़े शहरों और स्थापित औद्योगिक केंद्रों तक सीमित रहने के बजाय छोटे जिलों और कस्बों तक पहुंचेगा और स्थानीय स्तर पर विनिर्माण, रोजगार और सहायक उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही बड़ी कंपनियों के लिए पुर्जे, पैकेजिंग, फैब्रिकेशन और अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले छोटे उद्यमों के लिए नए अवसर पैदा हो सकते हैं।



महंगाई में भी रोशन है बाजार की दीवाली

रामवीर सिंह गुर्जर
नई दिल्ली, 1 नवंबर

महंगाई चौतरफा बढ़ रही है तो त्योहारों के मौसम में होने वाले कारोबार भी इससे अछूते कैसे रहेंगे। मगर दिल्ली के थोक बाजारों में त्योहारी कारोबार पर महंगाई का खास असर नहीं दिख रहा है। दिल्ली में चांदनी चौक, भागीरथ पैलेस, खारी बावली और सदर जैसे बाजार कारोबार के बड़े ठिकाने हैं और त्योहार के दिनों में तो इनकी रौनक देखते ही बनती है। इन बाजारों में दिल्ली-एनसीआर के ग्राहक ही नहीं पहुंचते बल्कि दूसरे राज्यों के खरीदार भी आते हैं। यहां के कारोबारी कह रहे हैं कि सामान इस साल महंगा जरूर हुआ है मगर बिक्री में किसी तरह की कमी नहीं दिख रही है। दाम बढ़ें तो आम तौर पर बिक्री कम हो जाती है, लेकिन इस साल अभी तक ऐसा नहीं दिखा है।

दीवाली से पहले सजावट का सामान खूब बिकता है और भागीरथ प्लेस इसके लिए बड़ा बाजार माना जाता है। यहां देश के भीतर बना लाइटिंग का सामान बिकता है और चीन से आया माल भी सजाया जाता है। यहां लाइटिंग सामग्री का कारोबार करने वाले प्रवीण कुमार राणा बताते हैं कि धातुएं महंगी हो गई हैं और रुपया कमजोर होने से आयात भी महंगा हुआ है। इसलिए लाइटिंग सामग्री के दाम इस बार बढ़े हैं और माल पिछली दीवाली से 20 फीसदी महंगा बिक रहा है। इसके बाद भी इसकी बिक्री में अभी तक कोई कमी नहीं आई है। उनका कहना है कि इन दिनों बड़े खरीदार ज्यादा आ रहे हैं, जो दाम बढ़ने के बावजूद थोक में खरीदारी कर रहे हैं। कुछ दिनों में खुदरा खरीदारी करने वाले आम ग्राहक भी आने लगेंगे। राणा को इस साल बिक्री 5 से 7 फीसदी बढ़ने की उम्मीद है।

पुरानी दिल्ली का डिप्टीगंज बाजार बर्तन कारोबार के लिए मशहूर है। यहां बर्तन के प्रमुख कारोबारी सुधीर जैन महंगाई का साफ असर पड़ने की बात कहते हैं। उन्होंने कहा, 'बर्तन बनाने में एल्युमीनियम और स्टेनलेस स्टील का ज्यादा इस्तेमाल होता है और इन दोनों की कीमतें बढ़ गई हैं। इससे बर्तनों के दाम भी 10 फीसदी तक बढ़े हैं मगर बिक्री में गिरावट नहीं दिख रही है।' बर्तनों की सबसे ज्यादा बिक्री धनतेरस पर होती है और जैन बताते हैं कि इस बार पिछले साल से ज्यादा बिक्री की उम्मीद में थोक कारोबारी जमकर माल ले गए हैं। उन्हें दाम बढ़ने पर भी कुल मिलाकर 5 से 10 फीसदी ज्यादा बिक्री होने की आस है।

ज्यादा जगमगा रहे दिल्ली के बाजार

- त्योहारी सामान के दाम 5 से 30 फीसदी बढ़े
- फिर भी दिल्ली में बिक्री 5 से 10 फीसदी बढ़ने का अनुमान
- देश में 7 लाख करोड़ रुपये त्योहारी कारोबार के आसार
- दिल्ली में हो सकता है 70-80 हजार करोड़ रुपये का कारोबार

दीवाली पर तोहफों में मेवा और मिठाई देने का रिवाज बहुत अधिक है और कंपनियां भी अपने कर्मचारियों तथा बड़े ग्राहकों के लिए भारी मात्रा में मेवे खरीदती हैं। नट ऐंड ड्राईफ्रूट कौंसिल इंडिया के संस्थापक सदस्य रवि मेहता ने कहा, 'देश में सामान्य महंगाई बढ़ने और आयात भी महंगा होने से इस साल पिस्ते के दाम 25 से 30 फीसदी बढ़ गए हैं। बादाम भी 20-25 फीसदी और काजू-किशमिश 5 फीसदी महंगे हुए हैं। फिर भी इस बार मेवों की बिक्री पिछली दीवाली के बराबर रहने या 5 फीसदी बढ़ने की संभावना है क्योंकि कंपनियों ने तोहफे को तौर पर मेवों के बहुत ऑर्डर दिए हैं।'

मेहता के मुताबिक मेवों के थोक कारोबारियों ने भी खरीद में कोई कटौती नहीं की है क्योंकि उन्हें फुटकर बिक्री तेज रहने की उम्मीद है। आंकड़े बताते हैं कि देश में हर साल मेवों का 70-75 हजार करोड़ रुपये का कारोबार होता है, जिसमें दिल्ली की हिस्सेदारी 20 से 25 हजार करोड़ रुपये रहती है। इसमें 4-5 हजार करोड़ रुपये की बिक्री त्योहारों पर ही हो जाती है।

थोक बाजारों में फूल, लड़ियां, सजावटी सामान, मोमबत्ती वगैरह की दुकानें भी गुलजार हैं। मोमबत्ती और मोम से बने सजावटी दिये बेचने वाली मुमताज आलम ने बताया कि मोम महंगा होने से सामान 10 से 15 फीसदी महंगा हो गया है मगर दीवाली पर इनकी बिक्री में कमी कभी नहीं आती।

दिल्ली व्यापार महासंघ के अध्यक्ष देवराज बवेजा त्योहारों पर महंगाई की मार पड़ने की बात तो स्वीकार करते हैं। लेकिन बिक्री के रुझान देखकर उनका कहना है कि कारोबार इस बार पिछले साल से ज्यादा रहता है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का भी अनुमान है कि इस साल नवरात्र से दीवाली तक करीब 7 लाख करोड़ रुपये का कारोबार होगा और दिल्ली में त्योहारी कारोबार 70 से 80 हजार करोड़ रुपये रह सकता है।

मौसम का झटका, कपास उत्पादन घटने का खटका

कमोडिटी बाजार

अनियमित बारिश और बढ़ती गर्मी ने कपास के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक देश भारत में कारोबारियों व किसानों की चिंता बढ़ा दी है

संजीव मुखर्जी
नई दिल्ली, 1 नवंबर

चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है। किंतु अक्टूबर में शुरू हुए नए 2026-27 सीजन में कपास का उत्पादन 12 से 18 फीसदी घटकर 2.9 करोड़ गांठ (एक गांठ में 170 किलो रुई) ही रहने का अनुमान है। 2025-26 सीजन में उत्पादन 3.3 करोड़ गांठ रहने का अनुमान था। कम बारिश और अधिक तापमान से कपास उत्पादक प्रमुख राज्यों में पैदावार प्रभावित होने की आशंका है।

उत्तर भारतः कपास की बोआई 18 फीसदी गिरी है। हालांकि खेतों में खड़ी फसल की स्थिति अच्छी है, लेकिन मिट्टी में नमी घटने और तापमान अधिक रहने से पैदावार तथा कुल उत्पादन प्रभावित हो सकता है। स्थानीय उद्योग के मुताबिक इस साल 28-30 लाख गांठ कपास हो सकता है, जो पिछले साल के आसपास ही होगा।

गुजरातः कारोबारियों के मुताबिक गुजरात में कपास की फसल की स्थिति अभी दूसरे राज्यों के मुकाबले खराब नहीं है। किंतु दिन के समय तापमान असामान्य रूप से अधिक रहा तो पैदावार घट सकती है। राज्य में कपास का उत्पादन पिछले साल से 12 फीसदी तक कम रहने का अनुमान है। स्थानीय उद्योग का अनुमान है कि गुजरात में 56 लाख गांठ कपास हो सकता है। दूसरे राज्यों से 7 से 12 लाख गांठ कपास आया तो नए सीजन में गुजरात में कुल उत्पादन 62 से 70 लाख गांठ रहेगा।

महाराष्ट्रः राज्य में कपास की बोआई पिछले साल के बराबर हुई है। विदर्भ-अकोला क्षेत्र में कुछ जिलों में फसल अच्छी है और कुछ में बहुत खराब। यहां कुल 50 से 53 लाख गांठ उत्पादन होने का अनुमान है। खानदेश क्षेत्र में जलगांव जिले में फसल की स्थिति अच्छी है और धुले में खराब। क्षेत्र में कुल 10-12 लाख गांठ उत्पादन होने का अनुमान है। मराठवाड़ा में बारिश कम और तापमान अधिक रहने के कारण 40-50 फीसदी फसल खराब होने की आशंका है। इसलिए उत्पादन 23 से 25 लाख गांठ ही रह सकता है।

राधा लक्ष्मी ग्रुप के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक अतुल गणात्रा को महाराष्ट्र में इस बार कपास पिछले साल से 20 फीसदी कम यानी 85 से 90 लाख गांठ ही होने का अनुमान है। गणात्रा कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी रह चुके हैं।



कपास की बिगड़ती आस

राज्य	उत्पादन (लाख गांठ में)	
	न्यूनतम	अधिकतम
उत्तर भारत	28	30
महाराष्ट्र	85	90
गुजरात	62	70
मध्य प्रदेश	17	18
तेलंगाना	35	37
आंध्र प्रदेश	12	13
कर्नाटक	18	20
ओडिशा	2	2.5
तमिलनाडु	5	5
अन्य राज्य	2	2
कुल	270	290.50

नोटः 1 गांठ में 170 किलो कपास। कुल आंकड़े अनुमानित हैं, इसलिए अलग-अलग राज्यों के आंकड़ों का जोड़ कुल योग से अलग हो सकता है।

मध्य प्रदेशः प्रदेश में कपास की बोआई का रकबा 5 फीसदी बढ़ा है। कुछ दिन पहले तक फसल की स्थिति अच्छी थी। इस साल राज्य में रुई की गांठों का उत्पादन पिछले साल के आसपास करीब 17-18 लाख गांठ रहने की उम्मीद है।

तेलंगानाः यहां कपास की बोआई पिछले साल से 5 फीसदी अधिक हुई है। किंतु केवल आधे हिस्से में फसल अच्छी है और बाकी आधे में पैदावार पर आशंका के बादल हैं। आदिलाबाद और वारंगल जिलों में फसल की स्थिति अच्छी है। लेकिन महबूबनगर और नलगोंडा जिलों में कम बारिश से फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। इसलिए राज्य में कपास उत्पादन पिछले साल से 20 फीसदी कम हो सकता है।

आंध्र प्रदेशः पिछले तीन महीनों में पर्याप्त बारिश नहीं होने से कपास की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। इससे प्रदेश में कपास का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले करीब 35 फीसदी घटकर 12-13 लाख गांठ ही रहने का अनुमान है।

कर्नाटकः कपास की बोआई पिछले साल के बराबर हुई है। लेकिन पूरे राज्य में बारिश कम रहने से उत्पादन पिछले साल के मुकाबले 30-35 फीसदी घटकर केवल 18-20 लाख गांठ रह जाने की आशंका है।

तमिलनाडुः बोआई दीवाली के बाद ही शुरू होने की उम्मीद है। कपास उत्पादन करीब 5 लाख गांठ रहने का अनुमान है।

ओडिशाः ओडिशा में कपास की बोआई 15-20 फीसदी कम रही है और जरूरत से ज्यादा बारिश के कारण कपास उत्पादन करीब 30 फीसदी घटकर 2-2.5 लाख गांठ रहने का अनुमान है।

सोने का भाव इस साल अभी तक करीब 25 फीसदी टूट चुका है, जिस कारण ऊहापोह में फंसे निवेशक

दीवाली पर गोल्ड ईटीएफ में लगाएं पैसा!

अंशु

सोने की कीमतों में गिरावट के बावजूद गोल्ड ईटीएफ में निवेशकों की दिलचस्पी बनी हुई है। सितंबर में गोल्ड ईटीएफ में 4,451 करोड़ रुपये का निवेश आया, जो अगस्त के 2,597 करोड़ रुपये के मुकाबले 71.4 फीसदी अधिक है। सोने का भाव भी इस जनवरी में करीब 5,595 डॉलर प्रति औंस हो गया था, जो अब घटकर करीब 4,200 डॉलर प्रति औंस रह गया है।

दीवाली नजदीक आने पर सोने में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ सकती है। लेकिन करीब 17 म्यूचुअल फंड कंपनियों ने गोल्ड ईटीएफ में निवेश करने वाली फंड ऑफ फंड्स योजनाओं में नए निवेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। ऐसे में निवेशकों के सामने बड़ा सवाल है कि कीमतों में आई गिरावट क्या सोने में निवेश का मौका है और क्या त्योहारी मांग गोल्ड ईटीएफ की चमक बढ़ा सकती है?

दीवाली नजदीक आने के साथ त्योहारी मांग से सोने में निवेशकों की दिलचस्पी और बढ़ सकती है। किंतु करीब 17 म्यूचुअल फंड कंपनियों ने गोल्ड ईटीएफ में निवेश करने वाली फंड ऑफ फंड्स योजनाओं में नए निवेश पर फिलहाल रोक लगा दी है।

बढ़ेगी गोल्ड ईटीएफ की मांग?

कोटक म्यूचुअल फंड में ईटीएफ के फंड मैनेजर सतीश डोंडापति को त्योहारी सीजन में गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड फंड में निवेश बढ़ने की उम्मीद है। हालिया गिरावट में भाव कम होने से वे निवेशक भी आ सकते हैं, जो सोने में निवेश के लिए बेहतर कीमत का इंतजार कर रहे थे।

निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड में कमोडिटीज हेड और फंड मैनेजर विक्रम धवन बताते हैं कि पारंपरिक आभूषणों और सोने के छोटे बिस्कुटों (बार) की मांग 10-20 फीसदी घटी है। उनका कहना है, 'अक्सर धातु के रूप में सोने की मांग घटने और भाव ठहर जाने पर गोल्ड ईटीएफ में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ जाती है। ऐसे में आभूषणों की मांग कमजोर रहने के बावजूद त्योहारी सीजन में गोल्ड ईटीएफ में नया निवेश बढ़ सकता है।'

अभी निवेश करें या इंतजार करें?

निवेश केवल इसलिए न कर दिया जाए कि सोने के भाव निचले स्तर पर हैं। डोंडापति मानते हैं कि निवेशक आगे और गिरावट का इंतजार करने की जगह मौजूदा भाव पर धीरे-धीरे सोना खरीदना शुरू कर सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड फंड के जरिये किस्तों में निवेश करने से खरीद की औसत कीमत सही रहती है और कीमतों में एकाएक उतार-चढ़ाव का असर कम हो जाता है।

ग्राफिक्स : दीपक शर्मा



शीर्ष 5 गोल्ड ईटीएफ का 1 साल का प्रदर्शन

गोल्ड ईटीएफ	रिटर्न (%)
क्वांटम गोल्ड ईटीएफ	17.89
आदित्य बिड़ला सन लाइफ गोल्ड ईटीएफ	16.91
जीरोधा गोल्ड ईटीएफ	16.85
डीएसपी गोल्ड ईटीएफ	16.84
मिरे ऐसेट गोल्ड ईटीएफ	16.84

स्रोतः वैल्यू रिसर्च |
29 अक्टूबर 2026 तक 1 साल के रिटर्न के आंकड़े

धवन भी निवेश में लंबे समय के लिए विविधता लाने के मकसद से धीरे-धीरे सधे तरीके से निवेश करने के पक्ष में हैं। उनके हिसाब से अगर कम समय में मुनाफा कमाने के बजाय जोखिम कम करने के लिए निवेश करना है तो पोर्टफोलियो में किसी भी समय एक हिस्सा सोने को दिया जा सकता है।

हकीकत में कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि सोना कब सबसे नीचे पहुंच गया है। धवन के अनुसार अनुभवी निवेशक कीमतों के रुझान और तकनीकी संकेत देखकर खरीदफरोख्त कर सकते हैं मगर दीर्घकालिक संपत्ति बनाने को म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों को यह रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। बार-बार खरीद-बिक्री से कर भी ज्यादा चुकाना पड़ता है। निवेशक पहले कुल निवेश में सोने का हिस्सा तय करें और फिर गिरावट में एकमुश्त रकम लगाने के बजाय धीरे-धीरे सोना खरीदें।

निवेश की कितनी अवधि सही?

धवन कम से कम दो से तीन साल तक रकम लगाए रखना सही मानते हैं। उनका कहना है, 'पहले भी सोने में निवेश का फायदा बाजार की अलग-अलग स्थितियों और आर्थिक चक्रों में बखूबी दिखा है। लेकिन किसी भी परिसंपत्ति का पिछला प्रदर्शन भविष्य में भी वैसे ही नतीजे मिलने की गारंटी नहीं देता।'

डोंडापति के हिसाब से सोने में निवेश तीन से पांच साल के लिए करना चाहिए और फौरी उठापटक से मुनाफा कमाने के लिए गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड फंड नहीं खरीदने चाहिए। सभी विशेषज्ञ एकमत हैं कि सोना कम समय में मुनाफा कमाने का दांव नहीं है। निवेशक वित्तीय जरूरतों और लक्ष्यों के अनुसार निवेश की अवधि तय करें। जिस रकम की निकट भविष्य में जरूरत पड़ सकती है, उसे सोने में नहीं लगाएं।

पोर्टफोलियो में कितना हो सोना?

डोंडापति की राय में निवेशक जोखिम उठाने की क्षमता और निवेश अवधि के हिसाब से पोर्टफोलियो में 10-15 फीसदी निवेश सोने पर कर सकते हैं। शेयरों की ज्यादा हिस्सेदारी वाले पोर्टफोलियो में से कुछ रकम सोने में लगाने पर बाजार की उठापटक में सहारा मिल सकता है। निश्चित आय वाले साधनों में ज्यादा निवेश है तो भी सोना बॉन्ड बाजार में दबाव के समय मददगार हो सकता है।

धवन कहते हैं कि पोर्टफोलियो में 5 फीसदी से कम सोना रखने पर ज्यादा विविधता नहीं आती मगर 15 फीसदी से अधिक निवेश लंबी अवधि में जरूरत से ज्यादा हो सकता है। इसलिए पोर्टफोलियो में तमाम निवेश विकल्पों का अनुपात देखकर ही सोने में रकम लगानी चाहिए।

आगे कैसी रहेगी सोने की चाल?

निकट अवधि में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। अमेरिका में ऊंची बॉन्ड यील्ड व डॉलर की मजबूती गिरावट ला सकती है, लेकिन आर्थिक अनिश्चितता और केंद्रीय बैंकों की खरीदारी सोने को उठा सकती है। डोंडापति को मध्यम और लंबी अवधि में सोने पर दांव सही लगता है किंतु धवन को साल के अंत तक सोने और चांदी में उतार-चढ़ाव की आशंका है।

बाजार गिरे तो म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे करें?

विकाश लारांश



इन तीन पैमानों की करें पूरी पड़ताल

- जोखिम वहन करने की क्षमता के आधार पर चुन सकते हैं म्यूचुअल फंड योजनाएं
- केवल संभावित रिटर्न देखकर ही न करें निवेश, लंबी अवधि तक निवेश करने पर होता है ज्यादा फायदा
- कम जोखिम लेने वाले और कम समय के लिए निवेश करने वाले आर्बिट्राज, शॉर्ट ड्यूरेशन डेट या इक्विटी सेविंग्स फंड पर कर सकते हैं विचार

सितंबर 2026 में भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आई। सेंसेक्स और निफ्टी करीब 6 फीसदी टूटे और विदेशी निवेशकों ने करीब 44,000 करोड़ रुपये निकाले। लेकिन म्यूचुअल फंड में निवेश जारी रहा। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फी) के मुताबिक सितंबर में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) के जरिये 32,490 करोड़ रुपये की आवक का रिकॉर्ड बन गया, जिसका आंकड़ा अगस्त में 32,297 करोड़ रुपये था। सवाल है कि गिरते बाजार में नए म्यूचुअल फंड निवेशक कहां से शुरुआत करें? उनके लिए एसआईपी बेहतर है या एकमुश्त निवेश? और कम अवधि के लिए कौन-से फंड चुनें?

पहली बार निवेश कर रहे हैं तो किन योजनाओं को चुनें?

नए निवेशकों को फंड चुनते समय जोखिम लेने की अपनी क्षमता और निवेश की अवधि जरूर समझनी चाहिए। बहुत अधिक जोखिम लेने के बजाय विविधता वाली योजनाओं से शुरुआत बेहतर हो सकती है। मनीफ्रंट के सह-संस्थापक मोहित गांग का कहना है कि मध्यम जोखिम लेने वाले निवेशक फ्लेक्सी कैप या लार्ज ऐंड मिड कैप फंड पर विचार कर सकते हैं। इनमें बड़ी कंपनियों की स्थिरता के साथ मिड कैप कंपनियों की वृद्धि का फायदा मिल सकता है। लेकिन कम से कम तीन से पांच साल या ज्यादा समय के लिए निवेश सही रहेगा। साथ ही निवेश शुरू करने से पहले आकस्मिक जरूरत के लिए छह महीने के खर्च बराबर रकम अलग रख लेनी चाहिए।

एसकेआई कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्य अधिकारी नरेंद्र वाधवा के अनुसार नए निवेशक जोखिम की भूख के मुताबिक लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप या कम लागत वाले इंडेक्स फंड चुन सकते हैं। जोखिम समझे बगैर स्मॉल कैप, सेक्टोरल या थीमैटिक फंडों में ज्यादा रकम लगाने से बचना चाहिए।

बाजार गिरे तो एसआईपी या एकमुश्त निवेश?

यह जानना मुश्किल होता है कि बाजार कितना चढ़ेगा या गिरेगा। इसलिए एक साथ सारी रकम झोंकने के बजाय नियमित निवेश बेहतर हो सकता है क्योंकि बाजार के अलग-अलग स्तरों पर निवेश का मौका मिलता है। गांग की राय में नए निवेशक एसआईपी से शुरू कर सकते हैं और बाजार गिरने पर एकमुश्त निवेश भी कर सकते हैं। वाधवा भी लंबी अवधि के निवेशकों को बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान एसआईपी जारी रखने की सलाह देते हैं। उनके हिसाब से एकमुश्त निवेश करने वाले एक साथ रकम लगाने के बजाय किस्तों में निवेश करें।

अगले दो से तीन साल में चाहिए पैसा तो क्या करें?

निवेश का साधन संभावित रिटर्न देखकर ही नहीं करना चाहिए। जरूरी यह देखना भी है कि पैसा कब चाहिए। अगर दो-तीन साल में पैसे की जरूरत आनी है तो उसे शेयर बाजार के जोखिम से दूर रखना चाहिए। गांग का सुझाव है कि कम जोखिम लेने वाले और तीन साल से कम के लिए निवेश करने वाले आर्बिट्राज, शॉर्ट ड्यूरेशन डेट या इक्विटी सेविंग्स फंड पर विचार कर सकते हैं। वाधवा निवेशकों को अपनी उम्र, वित्तीय लक्ष्य और जोखिम क्षमता के अनुसार इक्विटी, डेट और अन्य परिसंपत्ति श्रेणियों के बीच संतुलन बनाने की सलाह देते हैं। उनके हिसाब से निकट भविष्य में जरूरी रकम के लिए उपयुक्त डेट विकल्प देखे जा सकते हैं।

जल्द मुनाफे की उम्मीद और बार-बार फंड बदलने से बचें

बाजार का निचला स्तर पकड़ने की कोशिश, गिरावट में घबराकर निकासी और पिछला रिटर्न देखकर फंड का चुनाव सबसे बड़ी गलती होती हैं। इनसे बचना चाहिए। गांग निवेशकों को बाजार की हर गिरावट पर घबराने और हालिया प्रदर्शन के पीछे भागने से बचने को कहते हैं।

वाधवा का कहना है कि जल्द रिटर्न की उम्मीद और हालिया प्रदर्शन देखकर बार-बार फंड बदलना निवेश की राह में बाधा बन सकता है। दोनों विशेषज्ञों का कहना है कि निवेश को जल्दी मुनाफा कमाने के बजाय लंबी अवधि में पैसा बनाने का जरिया समझना चाहिए। अनुशासन, विविधता और धीरज के साथ निवेश बाजार के उतार-चढ़ाव से काफी बचा सकता है।

इस हफ्ते निवेशकों के लिए आ रहीं दो नई योजनाएं

न्यू फंड ऑफर

विकाश लारांश

म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वालों के लिए नवंबर के पहले हफ्ते दो नई योजनाएं खुलने वाली हैं। कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड और क्वांट म्यूचुअल फंड अपने नए फंड ऑफर (एनएफओ) शुरू करने जा रहे हैं। कोटक फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान सीरीज 336 योजना डेट व मनी मार्केट के साधनों में निवेश करेगी और क्वांट सिल्वर ईटीएफ एफओएफ चांदी में निवेश करेगी।

कोटक का एनएफओ 2 नवंबर को खुलेगा और 4 नवंबर को बंद होगा।

क्वांट का एनएफओ 4 नवंबर से 6 नवंबर तक खुला रहेगा। फंड कंपनियों के मुताबिक दोनों योजनाओं में 5,000 रुपये से निवेश शुरू किया जा सकता है। कोटक फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान सीरीज 336 में 5,000 रुपये के बाद 10 रुपये के मल्टीपल में निवेश किया जा सकेगा और कोई एंट्री या एग्जिट लोड नहीं लगेगा।

इसका बेंचमार्क निफ्टी अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन डेट इंडेक्स होगा। क्वांट सिल्वर ईटीएफ एफओएफ में 5,000 रुपये के बाद कम से कम 1,000 रुपये के मल्टीपल में निवेश हो सकेगा। निवेशक यूनिट मिलने के 15 दिनों के भीतर पैसा निकालते हैं तो 1 फीसदी एग्जिट लोड लगेगा। इसके बाद कोई एग्जिट लोड नहीं होगा। देसी बाजार में चांदी की कीमत इसका बेंचमार्क होगी।

एनएफओ की जरूरी जानकारी

योजना	कोटक फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान सीरीज 336	क्वांट सिल्वर ईटीएफ एफओएफ
फंड कंपनी	कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड	क्वांट म्यूचुअल फंड
योजना की श्रेणी	डेट फंड	सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड्स
योजना का प्रकार	क्लोज-एंडेड	ओपन-एंडेड
खुलने की तारीख	2 नवंबर 2026	4 नवंबर 2026
बंद होने की तारीख	4 नवंबर 2026	6 नवंबर 2026
न्यूनतम निवेश	₹5,000	₹5,000
निवेश कहां होगा?	डेट और मनी मार्केट	क्वांट सिल्वर ईटीएफ यूनिट
रिस्कोमीटर/जोखिम	मध्यम	बहुत अधिक

स्रोतः फंड कंपनियां

कोटक फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान सीरीज 336

कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड की यह डेट श्रेणी की क्लोज्ड-एंड योजना है। इसकी अवधि 125 दिन होगी यानी निवेश के करीब 125 दिन बाद यह परिपक्व हो जाएगी और निवेशकों को उस समय के यूनिट मूल्य के हिसाब से पैसा वापस मिल जाएगा। इस योजना का मकसद सरकारी बॉन्ड, कंपनियों के बॉन्ड और दूसरे डेट व मनी मार्केट साधनों में निवेश करके पैसा कमाना है। फंड ऐसी प्रतिभूतियों में रकम लगाएगा, जो योजना की अवधि पूरी होने तक या उससे पहले ही परिपक्व हो जाएंगी। योजना की यूनिट बंबई स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होंगी। इसलिए निवेशक अवधि पूरी होने से पहले सीधे फंड कंपनी से पैसा नहीं निकाल सकेंगे। किंतु वे शेयर बाजार में अपनी यूनिट बेच पाएंगे।

क्वांट सिल्वर ईटीएफ एफओएफ

यह क्वांट म्यूचुअल फंड की ओपन-एंडेड फंड ऑफ फंड्स (एफओएफ) योजना है यानी निवेशक एनएफओ बंद होने के बाद भी इसमें पैसा लगा पाएंगे और जरूरत पड़ने पर निकाल भी सकेंगे। योजना में सीधे चांदी खरीदने के बजाय क्वांट सिल्वर ईटीएफ की यूनिट में निवेश किया जाएगा। इस तरह निवेशकों को म्यूचुअल फंड के जरिये चांदी में निवेश का मौका मिलेगा। फंड अपनी कुल परिसंपत्ति का 95 से 100 फीसदी हिस्सा क्वांट सिल्वर ईटीएफ में लगाएगा। बाकी 5 फीसदी तक की रकम डेट, नकद और मनी साधनों रखी जा सकेगी। इस फंड का प्रदर्शन मुख्य रूप से चांदी की कीमतों पर निर्भर करेगा। चांदी महंगी होने पर फंड की वैल्यू बढ़ सकती है और कीमत गिरने पर निवेशकों को नुकसान हो सकता है।

कौन कर सकता है निवेश और कितना है जोखिम?

कोटक का फंड उन निवेशकों के लिए सही रह सकता है, जो कम अवधि के लिए डेट में पैसा लगाना चाहते हैं और अवधि पूरी होने तक निवेश बनाए रख सकते हैं। रिस्कोमीटर पर इस योजना को मॉडरेट रिस्क यानी मध्यम जोखिम की श्रेणी में रखा गया है।

क्वांट सिल्वर ईटीएफ एफओएफ उन निवेशकों के लिए विकल्प हो सकता है, जो चांदी में लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं और कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव सह सकते हैं। रिस्कोमीटर पर इस योजना को बहुत अधिक जोखिम की श्रेणी में रखा गया है। दोनों योजनाएं नई हैं, इसलिए इनके पिछले रिटर्न का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।

डिसक्लेमर: यहां एनएफओ की जानकारी दी गई है। यह निवेश की सलाह नहीं है। म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश संबंधी फैसला करने से पहले योजना के दस्तावेज पढ़ें और जरूरत पड़ने पर अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें।

डिसक्लोजर: बिज़नेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड में कोटक समूह (या कोटक परिवार) के नियंत्रण वाली इकाइयों की बहुलांश हिस्सेदारी है।

टारगेट मैच्योरिटी फंड में रकम लगाएं, बढ़ती यील्ड का फायदा उठाएं

आपका पैसा

ऐसा फंड चुनें जिसकी अवधि पूरी होने तक आप निवेश रख सकें और देखें कि खर्च हटाने के बाद आपको उससे कितना रिटर्न मिलेगा

हिमाली पटेल

पिछले महीने के पहले पखवाड़े में 10 साल के सरकारी बॉन्डों की यील्ड 7.40 फीसदी तक पहुंच गई, जिससे लोगों का ध्यान उन डेट योजनाओं की ओर गया, जिनमें निवेश करने से इस समय चल रही ऊंची यील्ड मिलना पक्का हो जाएगा। टारगेट मैच्योरिटी फंड उन बॉन्डों में निवेश करते हैं, जिनकी मियाद किसी तय तारीख के आसपास पूरी होती है, लेकिन इनमें निवेश करने से पहले निवेशकों को देख लेना चाहिए कि निवेश जल्दी निकालने पर क्यो जोखिम हो सकते हैं।

पाइए ऊंची यील्ड

इडलवाइस म्युचुअल फंड के प्रेसिडेंट और मुख्य निवेश अधिकारी (सीआईओ) धवल दलाल कहते हैं, 'हमें बॉन्ड बाजार में अच्छी वैल्यू तैयार होती दिख रही है और 2 से 3 साल में पूरे होने वाले एएए रेटिंग के बॉन्डों पर 7.5 से 7.75 फीसदी तक यील्ड मिल रही है।'

बैंकों की सावधि जमा (एफडी) भारतीय रिजर्व बैंक की रीपो रेट पर टारगेट मैच्योरिटी फंडों के मुकाबले अलग रुख दिखाती हैं। आनंद राठी वेल्थ में कार्यकारी निदेशक मनीष श्रीवास्तव कहते हैं, 'बैंक एफडी की ब्याज दर मौद्रिक नीति में होने वाले बदलावों से जुड़ी हारहती हैं और ऊंची ब्याज दर का फायदा ग्राहक को तब मिलता है, जब रिजर्व बैंक रीपो दर बढ़ाता है। लेकिन टारगेट मैच्योरिटी फंड बॉन्ड यील्ड के हिसाब से चलते हैं और बाजार के बदलाव पर फौरन प्रतिक्रिया करते हैं।'

इनक्रेड मनी के मुख्य कार्याधिकारी विजय कुप्पा के मुताबिक ये फंड बढ़ती दरों के इशारों पर तेजी से नहीं चलते। अगर निवेश के यूनिट खरीदने के बाद यील्ड बढ़ती हैं तो नेट ऐसेट वैल्यू (एनएवी) घट जाएगी मगर जो यील्ड लॉक-इन की है, वह बनी रहेगी।

क्या गणित है इसका

टारगेट मैच्योरिटी फंड मुख्य तौर पर तय अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करता है। पूरी अवधि तक निवेश रखने से ब्याज दर और क्रेडिट का जोखिम कम हो सकता है। निवेशक जरूरत के हिसाब से 1, 3, 5 या 10 साल के फंड चुन सकते हैं। टारगेट मैच्योरिटी फंडों के पूरे होने की तारीख पहले से तय होती और निवेशक को उसी तारीख पर रकम मिल जाती है। दलाल कहते हैं, 'निवेशकों को ये अपने सरल ढांचे, ऊंची क्रेडिट गुणवत्ता वाले पोर्टफोलियो से आकर्षित करते हैं क्योंकि पहले से पता होता है कि पूरी अवधि में कितना रिटर्न मिलेगा।'

चुनें सही परिपक्वता

दलाल के अनुसार 1 से 3 साल के टारगेट मैच्योरिटी फंड में जोखिम हटाने के बाद रिटर्न अच्छा मिलता है, लिक्विडिटी बेहतर होती है और दरें बढ़ने पर उठापटक भी कम होती है। श्रीवास्तव समझाते हैं, '2 साल के लिए निवेश कर रहा व्यक्ति 10 साल के टारगेट मैच्योरिटी फंड से दूर रहे क्योंकि अवधि लंबी होने पर ब्याज दर का जोखिम रहता है।'

जोखिम जरूर समझ लें

श्रीवास्तव की सलाह है, 'अवधि पूरी होने से पहले लिक्विडिटी की चिंता हो सकती है, इसलिए निवेशकों को अपनी निवेश अवधि के मुताबिक टारगेट मैच्योरिटी फंड चुनना चाहिए।'

ब्याज दर का जोखिम तभी खत्म होगा, जब निवेशक फंड की अवधि पूरी होने तक निवेश बनाए रखेंगे। कुप्पा समझाते हैं, 'यदि रिटेल निवेशक अंत तक बने नहीं रहते तो उन्हें बाजार का रुख बदलने पर उसी या उससे ऊंची दर पर दोबारा निवेश करने का मौका भी नहीं मिलता।'

इमेजिंग : दीपक शर्मा



बेहतर रिटर्न पर नजर

- टारगेट मैच्योरिटी फंड उन बॉन्डों में निवेश करते हैं, जिनकी मियाद तय तारीख पर पूरी होती है
- इस तरह के फंड पर रिटर्न बॉन्ड यील्ड के हिसाब से मिलता है
- टारगेट मैच्योरिटी फंड से प्राप्ति पर आयकर स्लैब के हिसाब से कर लगता है

आकें खर्चों के बाद असली रिटर्न

जो निवेशक परिपक्वता तक निवेश बनाए रखते हैं, उन्हें लगभग उतना ही रिटर्न मिल जाता है, जितन निवेश के समय अनुमान लगाया गया था। इसे यील्ड टु मैच्योरिटी कहा जाता है। दलाल कहते हैं, 'दोबारा निवेश, फंड के खर्च और उसके पास रखी नकदी आदि की वजह से कुछ अंतर आ सकता है। फिर भी हमारे हिसाब से ये फंड निवेशकों के लिए आकर्षक विकल्प हैं।'

आपके कितने माकूल?

जो निवेशक अपने पोर्टफोलियो में डेट जोड़ना चाहते हैं, वे टारगेट मैच्योरिटी फंड पर विचार कर सकते हैं। श्रीवास्तव के हिसाब से एफडी, डेट फंड, आर्बिट्राश फंड और लघु बचत योजनाओं के साथ ऐसे फंड अच्छी क्रेडिट गुणवत्ता और लिक्विडिटी के वाले डेट में निवेश का मौका दे सकते हैं। वह समझाते हैं कि डेट फंडों पर एफडी की तरह मामूली कर लगता है मगर उनसे हुआ फायदा पूंजीगत लाभ माना जाता है। इसलिए नियमों के हिसाब से पूंजीगत नुकसान के बदले फायदे पर कर माफी हो सकती है। दलाल की सलाह है कि साल भर के लिए निवेश करने निवेशक टारगेट मैच्योरिटी फंडों में पैसा लगा सकते हैं।

एफडी से तुलना

इन दोनों पर आयकर स्लैब के हिसाब से कर लगता है मगर टारगेट मैच्योरिटी फंड को कुछ लाभ होते हैं। यूटीआई ऐसेट मैनेजमेंट कंपनी के प्रेसिडेंट और हेड (फिक्स्ड इनकम) अनुराग मित्तल बताते हैं, 'सालाना लाभ पर नहीं बल्कि इन्हें बेचते समय आयकर स्लैब के हिसाब से कर लगता है। निवेशक एफडी की तरह जुर्माना चुकाए बगैर एनएवी पर इनसे निवेश निकाल सकते हैं।' एफडी में पैसा एक ही संस्थान में लगता है, जबकि ये फंड कई जगह निवेश करते हैं। वेंचरा के निदेशक जुझेर गाबाजीवाला बताते हैं कि दरें गिरने पर बॉन्ड मूल्य बढ़ने से इन फंडों का रिटर्न बढ़ सकता है और दरें बढ़ने पर घट भी सकता है।

निवेशकों को एफडी या टारगेट मैच्योरिटी फंड में निवेश से पहले अपने लक्ष्य और अवधि तय कर लेने चाहिए। मित्तल समझाते हैं कि निवेश की अवधि के हिसाब से मेल न खाए तो टारगेट मैच्योरिटी फंड ब्याज दर का जुआ बनकर रह जाता है।

फंड में कौन-कौन से बॉन्ड

सरकारी बॉन्डों वाले टारगेट मैच्योरिटी फंडों में सरकार की साख होती है और लिक्विडिटी भी खूब होती है। राज्य विकास ऋण लंबी अवधि में ब्याज दर का अच्छा अंतर दिलाते हैं। निवेशक देख लें कि सरकारी उपक्रमों (पीएसयू) के बॉन्डों में निवेश है या निजी कंपनियों के।

मित्तल कहते हैं, 'एएए पीएसयू बॉन्ड में बेहतरीन क्रेडिट और लिक्विडिटी होती है, जबकि निजी एएए बॉन्ड में क्रेडिट ऊंचा लेकिन डाउनग्रेड का खतरा होता है। करीब 7.90 फीसदी दर पर 3 से 5 साल के एएए पीएसयू बॉन्ड यील्ड और अवधि का संतुलन देते हैं। जोखिम से परहेज है तो राज्य विकास ऋण या सरकारी प्रतिभूति वाले फंड चुन लें।'

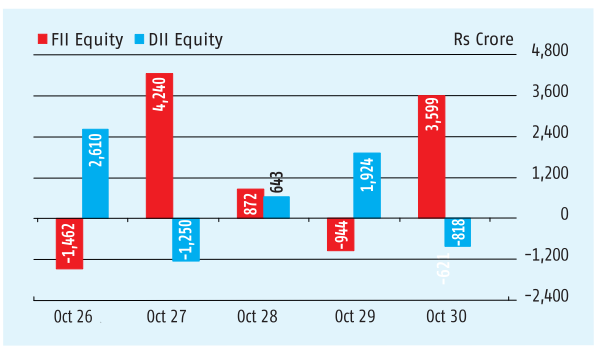
एनएसई डेरिवेटिव में एफआईआई निवेश

	Week ended Oct 23		Week ended Oct 30	
	Contract (Nos)	Tovr (` bn)	Contract (Nos)	Tovr (` bn)
Index Future	354150	544.9	348350	528.7
Stock Future	10920928	6833.9	5238016	3224.0
Index Option	91441834	137141.5	90167819	135001.7
Stock Option	5123010	3374.7	2929126	1875.2
Total	107839922	147894.9	98683311	140614.6

बीएसई 500 कंपनियों में एफआईआई शेयरधारिता

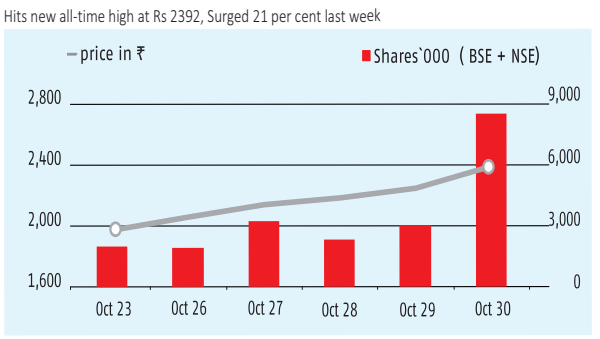
IN %	Jun-25	Sep-25	Dec-25	Mar-26	Jun-26
Manappuram Finance	31.15	31.56	30.14	24.44	23.56
Mangalore Refinery And Petro	1.63	1.55	2.35	3.70	2.48
Mankind Pharma	13.13	12.89	11.40	10.30	9.51
Marico	23.96	24.54	24.35	24.42	23.74
Maruti Suzuki India	15.35	15.93	15.91	14.28	12.98
Max Financial Services	45.04	45.10	45.47	48.22	48.42
Max Healthcare Institute	54.94	51.99	50.74	45.61	41.99
Mazagon Dock Shipbuilders	2.93	2.32	2.15	2.12	2.14
Minda Corporation	9.13	9.02	9.38	9.10	9.67
MMTC	0.25	0.23	0.17	0.28	0.31
Motherson Sumi Wiring India	10.83	10.78	10.65	10.25	9.42
Motilal Oswal Financial	7.89	8.13	7.53	7.68	7.55
Mphasis	19.74	19.21	20.54	20.26	20.26
MRF	19.59	19.20	19.11	18.94	18.38
Multi Commodity Exchange	22.64	19.95	21.60	26.99	30.70
Muthoot Finance	11.04	11.79	11.98	12.53	11.83
Narayana Hrudayalaya	12.15	12.18	13.06	12.14	11.58
Natco Pharma	16.95	15.73	16.86	19.07	18.69
National Aluminium Com	15.73	16.89	20.38	22.97	22.66
Nava	11.50	11.60	12.13	12.38	11.90
Navin Fluorine Inter	22.53	23.11	24.70	24.76	24.69
NBCC (India)	5.62	5.94	5.80	5.62	5.40
NCC	14.17	14.33	12.94	13.61	12.73

एफआईआई / डीआईआई निवेश



सप्ताह का शेयर (लॉरस लैब्स)

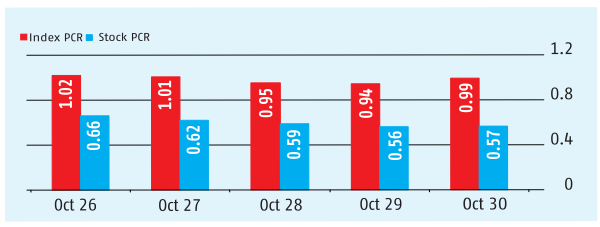
Hits new all-time high at Rs 2392, Surged 21 per cent last week



निफ्टी स्नैपशॉट

	Oct 26	Oct 27	Oct 28	Oct 29	Oct 30
Nifty 50 Spot	22753.2	22749.8	22698.8	22936.8	23053.1
Nifty 50 Future	22767.3	22776.7	22778.0	23047.4	23098.9
Prem/Discount	14.1	26.9	79.2	110.7	45.8
Fut(Open Int)	23195	23239	17513	17155	16944
Fut(Contract)	195689	175153	82214	59364	54486
Fut(Value Rs Cr)	28906.5	25970.0	12139.2	8859.1	8176.9
PCR(Open Int)	1.1	1.1	1.1	1.3	1.4
PCR(Contract)	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0
Major Call(Strike Price)	23000.0	22800.0	24000.0	23500.0	23500.0
Major Call(LTP)	20.1	10.2	1.8	6.8	6.7
Major Put(Strike Price)	22500.0	22750.0	20050.0	22000.0	22000.0
Major Put(LTP)	24.2	5.6	1.2	5.1	3.7

पुट/कॉल रेशियो



सेक्टर पर नजर

TOP GAINERS	OI '000	% chg	TOP LOSERS	OI '000	% chg
Stock/ Commodity Brokers	24535	4.4	Telecomm-Service	1875655	-36.4
Leather	18462	4.2	IT - Software	698230	-35.3
Agro Chemicals	52714	1.6	Others	46830	-34.5
			Information Tech	23318	-33.7
Top Losers			Trading	105501	-33.1
Cables	3520	-49.0	Retail	531936	-31.2
Hotels & Restaurants	30843	-44.0	Non Ferrous Metals	184255	-30.4
Diamond, Gems and	35074	-43.0	Edible Oil	41575	-30.1
Textiles	5458	-39.8	Miscellaneous	169441	-30.0
Plantation & Plantation	21300	-36.6	Pharmaceutical	6111	-29.9

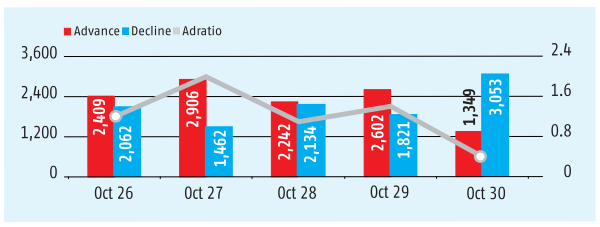
कीमत में बढ़ोतरी के साथ ओपन इंटरेस्ट

	Open Int as on			Price as on		
	Oct 23	Oct 30	% Chg	Oct 23	Oct 30	% Chg
Vodafone Idea	51176100	108240275	111.5	11.4	11.9	4.4
Shree Cement	450275	256725	-43.0	22735.0	22995.0	1.1
Indian Hotel	36554000	20991000	-42.6	781.8	811.7	3.8
Bank of Maha	55321500	32604000	-41.1	75.3	81.4	8.0
LTIMindtree	5184150	3090000	-40.4	4134.0	4233.5	2.4
Sona BLW Precis	22054900	13495825	-38.8	752.9	890.5	18.3
Tata Consumer P	24624050	15069450	-38.8	963.9	1025.9	6.4
Oil India	15622600	9854600	-36.9	447.9	454.0	1.4
Nykaa	54796875	34881325	-36.3	319.3	349.4	9.4
Ather Energy	7800750	5006625	-35.8	1380.0	1756.0	27.2
Marico	20692800	13304400	-35.7	766.5	800.0	4.4
Apollo Hosp	2611250	1698275	-35.0	7730.0	8448.0	9.3
Dr Reddys	25598750	16958125	-33.8	1229.5	1352.0	10.0
Eicher Motor	4076500	2701200	-33.7	7066.0	7220.0	2.2
Polycab India	2811125	1907750	-32.1	7440.0	7787.0	4.7
Chola Inv	17309375	11787600	-31.9	1463.8	1586.0	8.3
GE T&D Ind	4080375	2783750	-31.8	3700.0	4020.0	8.6
Hyundai Motor	6533450	4463250	-31.7	1850.0	1911.0	3.3

एनएसई सूचकांक

	Oct 23	Oct 30	% Chg
SPOTNifty 50	22600.0	23053.1	2.0
Bank Nifty	54287.4	54686.9	0.7
Nifty IT	31995.5	32606.9	1.9
Futures (LTP)			
Nifty 50	22576.6	23098.9	2.3
Bank Nifty	54242.2	54823.4	1.1
Nifty IT	54242.2	54823.4	1.1
Open Interest			
Nifty 50	22297925.0	16943615.0	-24.0
Bank Nifty	2921520.0	2378010.0	-18.6
Nifty IT	2921520.0	2378010.0	-18.6

तेजी / गिरावट बीएसई



मार्केट पोजीशन

HIGHEST	OI	% of MWL	LOWEST	OI	% of MWL
Angel One	66075000	684.88	Coromndl Int	126300	0.50
Adani Power	299147850	309.89	City Union Bk	7426050	5.01
CAMS	18461850	248.77	Navin Fluo	648225	9.18
LIC India	67431000	210.35	Oil India	12700800	13.49
MCX	11862225	155.36	Phoenix Mill	4493300	15.89
Bandhan Bank	188121600	131.78	Zomato	218390650	16.03
Kaynes T	5870550	125.77	360 ONE WAM	7394000	16.56
CGCEL	96262325	118.26	L & T	23909900	17.58
LIC Hsg Fin	52655000	116.54	Power Grid	87749600	17.95

OI As on Oct 30

कीमत में गिरावट के साथ ओपन इंटरेस्ट

	Open Int as on			Price as on		
	Oct 23	Oct 30	% Chg	Oct 23	Oct 30	% Chg
ICICI Lombard	9407125	6548775	-30.4	1592.0	1580.8	-0.7
Policy Bazar	23329950	16717400	-28.3	1015.0	1000.1	-1.5
IEX	81405900	58450950	-28.2	101.2	100.9	-0.3
SAIL	254443900	183972100	-27.7	164.4	161.0	-2.0
Federal Bank	121447500	89015000	-26.7	340.9	339.7	-0.4
Indus Tower	107453600	79769100	-25.8	380.0	378.3	-0.4
TCS	26656875	19816950	-25.7	2530.0	2502.6	-1.1
Power Fin	143648700	109592500	-23.7	316.0	313.6	-0.8
360 ONE WAM	6564000	5027500	-23.4	997.1	985.0	-1.2
Havells I	13867500	10636500	-23.3	1031.0	1013.8	-1.7
Bajaj Holding	153750	119700	-22.1	11175.0	10217.0	-8.6
Rail Vikas Niga	42111300	32968675	-21.7	181.3	179.7	-0.9
Amber Enter Ind	1281900	1014200	-20.9	6004.5	5865.0	-2.3
CG Power	27381050	21673300	-20.8	813.4	804.0	-1.1
Coal India	102681000	81302400	-20.8	397.5	389.0	-2.1
ICICI Life	24201700	19198600	-20.7	422.2	410.0	-2.9
Sagility	155592000	123576000	-20.6	44.2	42.1	-4.8
Dixon Tech	3134500	2493200	-20.5	11191.0	11000.0	-1.7

बीएसई सूचकांक

	Oct 23	Oct 30	Change	% Chg
Sensex	**73123.8**	**74459.5**	**1335.7**	**1.8**
OUTPERFORM SENSEX				
Healthcare	46951.9	50168.4	3216.5	6.9
Metal	36723.2	37765.5	1042.4	2.8
TECk	15802.5	16176.6	374.1	2.4
BSE-500	33538.0	34248.6	710.6	2.1
Auto	54824.8	55965.1	1140.3	2.1
BSE-200	10446.8	10660.9	214.1	2.0
Dollex-200	1831.5	1867.2	35.7	2.0
BSE-100	24039.1	24479.8	440.8	1.8
UNDERPERFORM SENSEX				
Smallcap	46825.3	46825.3	0.0	0.0
Midcap	44246.3	44246.3	0.0	0.0
Oil & Gas	24259.5	24322.7	63.2	0.3
Bankex	61086.7	61415.3	328.5	0.5
Cap. Goods	67988.6	68810.0	821.3	1.2
IT	30265.6	30666.1	400.5	1.3
PSU	18736.4	19037.4	301.0	1.6
Cons Durable	54822.9	55760.6	937.8	1.7
Dollex-30	6321.7	6431.0	109.3	1.7
Dollex-100	2618.6	2664.1	45.5	1.7
FMCG	16121.5	16410.3	288.8	1.8

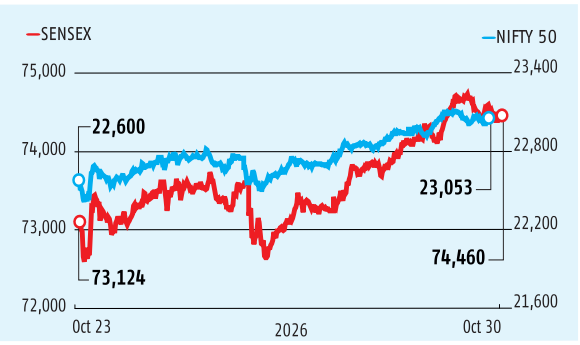
मार्केट एग्रीगेट्स

	WEEK END			WEEK END	
BSE	Oct 23	Oct 30	NSE	Oct 23	Oct 30
Shares(In Lakhs)	24764	26187	Shares(In Lakhs)	237562	266456
Turnover(In Crore)	35144	47528	Turnover(In crore)	436552	589400
Traded(000)	15410	19549	Traded(000)	178814	216185

डिलिवरी

	BSE		NSE	
DATE	Trd. shares (bn)	% Delivery	Trd. shares (bn)	% Delivery
Oct 30, 2026	6286.8	61.3	62668.5	40.6
Oct 29, 2026	5141.0	62.8	0.0	NaN
Oct 28, 2026	4507.2	64.4	44932.4	35.3
Oct 27, 2026	4827.6	62.3	53708.4	34.3
Oct 26, 2026	5431.3	61.2	53172.5	31.8
Oct 23, 2026	6737.4	59.0	63878.4	36.1
Oct 22, 2026	5655.7	58.6	60711.4	31.5
Oct 21, 2026	6420.3	62.9	57237.3	36.9
Oct 19, 2026	5955.8	61.0	51992.0	32.9

शेयर सूचकांकों में उतार चढ़ाव



बीएसई 500

	Oct 23	Oct 30	% chg
मुनाफे में			
Acutaas Chemicals	3138.6	4002.6	27.5
Ather Energy	1383.9	1755.1	26.8
Piramal Pharma	190.9	239.1	25.3
Laurus Labs	1974.0	2392.0	21.2
HEG Advanced Materials	198.8	238.3	19.9
Sona Blw Precision Forgings	752.8	890.3	18.3
Onesource Specialty Pharma	1332.7	1563.3	17.3
Urban Co	132.7	152.5	15.0
Aether Industries	1414.0	1620.5	14.6
Syrma SGS Technology	1434.5	1620.9	13.0
Navin Fluorine International	7679.1	8676.3	13.0
SJVN	47.4	53.4	12.8
PG Electroplast	472.0	532.0	12.7
Mankind Pharma	2217.0	2488.8	12.3
JSW Energy	445.6	500.0	12.2
Poonawalla Fincorp	412.9	462.3	12.0
SAI Life Sciences	1395.6	1559.7	11.8
Trent	2715.9	3015.1	11.0
Ola Electric Mobility	29.9	33.2	10.9
NHPC	70.0	77.5	10.6
Adani Energy Solutions	1219.9	1345.6	10.3
Zydus Lifesciences	1127.9	1244.0	10.3
Dr Reddy's Laboratories	1224.5	1350.2	10.3
Cemindia Projects	1145.6	1262.8	10.2
TVS Holdings	11083.6	12190.5	10.0
FSN E-Commerce Ventures	319.0	350.7	9.9
Syngene International	366.9	402.6	9.7
Leela Palaces Hotels & Resorts	577.7	633.5	9.7
Gland Pharma	2825.4	3097.5	9.6
L&T Technology Services	3910.6	4279.3	9.4
Apar Industries	14355.2	15700.3	9.4
Ramkrishna Forgings	591.1	646.2	9.3
Adani Green Energy	1185.0	1295.4	9.3
Blue Star	1496.0	1633.0	9.2
GE Vernova T&D India	3685.0	4021.5	9.1
Acme Solar Holdings	371.7	404.9	8.9
KPR Mill	1024.8	1115.0	8.8
घाटे में			
eClerx Services	1892.2	1556.7	-17.7
Dalmia Bharat	1595.1	1324.7	-16.9
Hexaware Technologies	590.7	501.4	-15.1
Intellect Design Arena	583.2	504.6	-13.5
Sumitomo Chemical India	360.6	315.7	-12.4
Aegis Logistics	1250.1	1097.5	-12.2
Five-Star Business Finance	448.3	394.5	-12.0
Atul	5578.4	5023.0	-10.0
Aditya Birla Sun Life Asset Ma	893.1	804.9	-9.9
Suzlon Energy	37.4	33.9	-9.5
Redington	359.4	326.8	-9.1
DCM Shriram	962.1	874.7	-9.1
Godrej Agrovet	607.8	553.9	-8.9
Aegis Vopak Terminals	242.8	221.6	-8.7
Supreme Industries	3450.0	3151.0	-8.7
Bajaj Holdings & Investment	11175.0	10220.5	-8.5
Mazagon Dock Shipbuilders	1862.0	1705.0	-8.4
JSW Dulux	286.4	263.6	-8.0
Balrampur Chini Mills	640.2	589.9	-7.9
IFCI	59.3	54.7	-7.8
Cyient	1229.3	1136.0	-7.6
AU Small Finance Bank	934.0	864.0	-7.5
Cello World	354.1	328.6	-7.2
Jubilant Ingrevia	601.7	559.1	-7.1
Honeywell Automation India	31485.3	29514.6	-6.3
IndiaMart InterMesh	1573.5	1486.8	-5.5
Afcons Infrastructure	218.0	206.1	-5.5
Mahindra & Mahindra Financial	277.1	262.2	-5.4
Inox Wind	58.9	55.8	-5.3
Latent View Analytics	221.7	210.5	-5.1
AWL Agri Business	173.0	164.4	-5.0
CRISIL	4748.1	4516.6	-4.9
Shriram Finance	867.0	825.0	-4.8
Sagility	44.1	42.0	-4.8

सेक्टर सूचकांक

Return (%)	Oct 30	1 week	1 month	3 month	6 month	1 year
BSE Sensex	74,460	1.8	2.7	-4.5	-3.2	-11.8
Nifty 50	23,053	2	1.9	-5.2	-3.9	-10.9
BSE 100	24,480	1.8	0.9	-5.7	-3.6	-9.8
BSE 200	10,661	2	0	-6.3	-4	-9.1
BSE 500	34,249	2.1	-0.9	-6.3	-3.6	-8.5
Nifty Midcap	57,301	2.7	-3.4	-8.5	-4.2	-4.7
Nifty Next50	67,709	2.9	-2.9	-6.9	-2.8	-3.4
Nifty 500	21,896	2.2	-0.8	-6.2	-3.5	-8.2
BSE Auto	55,965	2.1	-3.8	-9.8	-2.1	-6.6
BSE Bankex	61,415	0.5	-0.5	-5.3	-0.5	-5.9
BSE CG	68,810	1.2	-7.2	-9.1	-10.9	-1.9
BSE CD	55,761	1.7	-4.9	-14.5	-5.6	-8.6
BSE FMCG	16,410	1.8	-2.9	-11.2	-13.1	-20.8
BSE Healthcare	50,168	6.9	0.2	-1	12.4	11.8
BSE IT	30,666	1.3	14.8	2.5	8	-12.8
BSE TECk	16,177	2.4	14.5	2.8	7.7	-8.6
BSE Realty	6,346	3.9	-4.3	-9.6	3.6	-14.1
BSE Metal	37,766	2.8	-6.8	-7.6	-10.5	6.3
BSE Oil&Gas	24,323	0.3	-2.3	-7.2	-12.1	-14.9
BSE PSU	19,037	1.6	-2.6	-7.5	-13	-7.3

मोटा सौदा

Date	Stock	Client	Type	Quantity	Price (`)
Oct 30	Sagility	Sagility B.V.	SELL	560000000	42.8
Oct 30	Swiggy	Tencent Cloud Europe B.V.	SELL	54347662	180.7
Oct 30	Swiggy	Societe Generale	BUY	23740000	180.7
Oct 30	Sri Lotus Developers	Smallcap World Fund Inc	BUY	14140027	240.0
Oct 30	Sagility	Bnp Paribas Financial Markets	BUY	56185380	42.8
Oct 30	Swiggy	Morgan Stanley Asia Singapore Pte	BUY	13190000	180.7
Oct 30	Sagility	Societe Generale	BUY	47506626	42.8
Oct 30	Swiggy	Goldman Sachs Bank Europe Se	BUY	10550000	180.7
Oct 30	Sagility	Ghisallo Master Fund Lp	BUY	44564304	42.8
Oct 30	Sagility	Icici Prudential Mutual Fund	BUY	35087719	42.8
Oct 30	Sagility	Icici Prudential Life Ins Company	BUY	32588537	42.8
Oct 30	Sagility	Goldman Sachs Funds	BUY	27267148	42.6
Oct 29	IIFL Capital Services	Theleme India Master Fund	SELL	3124131	348.0
Oct 30	Strides Pharma Science	Sbi Life Insurance Company	BUY	662369	1045.3
Oct 26	SG Mart	Riambel Capital Pcc - Rcc1	BUY	789702	799.5
Oct 29	Birlasoft	Societe Generale	BUY	1647762	341.8
Oct 28	Jubilant Ingrevia	East Bridge Capital Master Fund I	BUY	921668	601.8
Oct 30	Swiggy	Nippon India Mutual Fund	BUY	2767000	180.7
Oct 30	Swiggy	Ghisallo Master Fund Lp	BUY	2608392	180.7
Oct 30	Ratnaveer Precision	Tirth Gems	BUY	1175000	358.1
Oct 26	Tourism Finance Corp	Mansi Share And Stock Broking	SELL	2800000	147.9
Oct 30	Equitas SFB	Sspl Securities	BUY	8100000	50.6
Oct 29	Equitas SFB	Sspl Securities	BUY	6300000	57.2
Oct 27	Seshasayee Paper	Atyant Capital India Fund I	SELL	1723521	206.2
Oct 29	Rain Industries	Matruchhaya Mercantile	BUY	1659104	208.3
Oct 26	Tourism Finance Corp	Mansi Share And Stock Broking	BUY	2310000	147.0
Oct 30	Swiggy	Aditya Birla Sun Life Mutual Fund	BUY	1492270	180.7
Oct 27	MSTC	Wisdomtree Emerging Markets Fund	SELL	413676	561.3
Oct 30	MM Forgings	Integrated Insurance Broking Services	BUY	330031	482.7
Oct 29	Mufin Green Finance	Aakanksha Satyen Mamtora	BUY	1120000	131.6
Oct 29	Mufin Green Finance	Three Words Capital	SELL	1090000	131.5
Oct 27	Seshasayee Paper	Time Square Investments	BUY	570000	215.0
Oct 29	Technocraft Ventures	Govind Ji Gupta	BUY	250000	475.9
Oct 27	Advit Jewels	Ramesh Sawalram Saraogi	BUY	325000	332.7
Oct 27	Technocraft Ventures	Govind Ji Gupta	SELL	200000	481.5
Oct 30	Sunshine Pictures	Arihant Capital Markets	BUY	245190	388.9
Oct 26	STL Networks	Uno Metals	SELL	2600000	34.5
Oct 28	STL Networks	Uno Metals	SELL	2790000	31.9

वैश्विक सूचकांक

Return (%)	Oct 30	1 week	1 month	3 month	6 month	1 year
FTSE 100	10,722	0.3	1.1	-1.6	3.3	9.9
Nikkei 255	64,660	3.1	-3.1	4.5	9.1	26
Hang Seng	22,959	-0.6	-6.7	-11.2	-10.9	-12.6
Nasdaq	26,185	0.9	-2.5	4.2	5.2	11
Dow Jones	52,343	0.2	2.8	0.3	5.4	10.1
Rs/$	95	0	0.9	0.8	0	-6.6
Brent Crude (spot)$/Bbl	111.7	0.5	14.4	27.8	1.4	74.4

ओपन इंटरेस्ट ब्रेकअप

	Price as on Oct 30		Open interest		% of Open interest		
	Close (cash)	LTP (future)	Shares	` crore	Futures	Call	Put
Adani Enter	2579.4	2579.9	27564	7109.9	64.2	18.8	17.0
Adani Ports	1850.0	1844.5	27575	5101.3	55.7	23.8	20.4
Apollo Hosp	8448.0	8346.0	4010	3387.9	42.3	32.7	24.9
Asian Paints	2320.0	2327.7	13299	3085.3	50.4	24.6	25.0
Axis Bank	1217.0	1217.9	121699	14810.8	80.6	10.6	8.8
Bajaj Auto	10350.0	10325.0	4962	5135.9	40.5	33.0	26.5
Bajaj Fin	939.1	943.2	99011	9298.1	72.8	14.3	12.9
Bajaj Finsrv	1667.6	1677.4	13160	2194.6	63.6	20.0	16.4
Bharat Elctn	369.9	369.5	155304	5744.7	62.3	21.4	16.3
Bharti Airtel	1973.7	1973.6	71992	14209.1	74.6	14.3	11.1
Cipla	1378.9	1381.0	17354	2392.9	58.9	21.5	19.6
Coal India	389.0	391.1	129422	5034.5	62.8	23.7	13.5
Dr Reddys	1352.0	1354.2	27749	3751.6	61.1	18.2	20.7
Eicher Motor	7220.0	7236.0	4735	3418.6	57.0	21.1	21.8
Grasim Ind	2981.4	2979.6	9088	2709.3	76.0	12.8	11.2
HCL Techno	1428.1	1437.7	26229	3745.7	75.2	13.1	11.7
HDFC Bank	692.8	692.7	571080	39564.4	67.8	19.4	12.8
HDFC Std Life	524.9	525.2	60407	3170.7	67.8	20.0	12.2
Hindalco	884.7	889.9	80172	7092.9	76.9	12.7	10.4
HUL	1864.6	1846.6	34542	6440.7	55.2	27.7	17.1
ICICI Bank	1398.0	1399.0	148800	20802.3	77.7	11.6	10.6
Infosys	1185.0	1182.9	109238	12944.8	67.4	15.9	16.7
InterGlobe Avia	4877.6	4861.1	11018	5374.0	55.1	20.5	24.4
ITC	265.6	268.1	348876	9266.1	61.5	23.4	15.1
Jio Financial	204.5	205.5	348590	7128.7	64.1	21.4	14.5
JSW Steel	1246.0	1253.3	48765	6076.2	85.5	8.4	6.1
Kotak Mah Bank	461.6	461.6	239732	11066.0	66.6	16.6	16.8
L & T	3871.7	3859.3	23910	9257.2	56.4	22.3	21.2
Mah & Mah	2840.3	2858.0	21079	5987.0	66.9	18.3	14.8
Maruti Suzuki	11397.0	11532.0	4991	5688.0	49.3	29.2	21.5
Max Health	860.0	864.6	22613	1944.7	66.2	22.2	11.6
Nestle India	1167.0	1176.1	22840	2665.4	58.7	27.6	13.7
NTPC	316.3	313.5	116261	3676.7	71.9	15.2	12.9
ONGC	225.4	227.0	108945	2455.6	58.6	25.6	15.8
Power Grid	265.0	260.8	87750	2325.4	61.4	20.8	17.8
Reliance Ind	1164.9	1170.7	358531	41765.2	46.6	32.3	21.1
SBI	961.9	964.7	168407	16198.3	63.7	17.3	19.0
SBI Life Ins	1658.6	1668.7	9900	1642.0	77.0	13.2	9.7
Shriram TrFn	823.2	828.2	50820	4183.2	61.6	26.4	12.0
Sun Pharma	1777.7	1791.2	27902	4960.1	59.1	22.7	18.2
Tata Consumer P	1025.9	1026.2	21300	2185.2	70.7	14.2	15.1
Tata Motors	265.4	267.2	152722	4053.3	64.3	19.7	16.0
Tata Steel	167.6	168.6	447246	7495.8	73.9	14.5	11.6
TCS	2502.6	2514.8	37120	9289.7	53.4	23.0	23.6
Tech Mahindra	1790.8	1803.4	26383	4724.6	66.0	18.2	15.7
Titan Company	4436.5	4467.6	9087	4031.5	60.3	21.0	18.7
Trent	3017.3	3037.8	15971	4818.8	53.4	25.3	21.3
UltraTech	11045.0	11112.0	2785	3075.8	72.3	16.4	11.3
Zomato	343.7	343.9	218391	7505.0	59.8	19.8	20.4

विषय: साइबर जोखिम कम करने के उपाय?

बैंकों और ग्राहकों की सावधानी से रुकेगी साइबर धोखाधड़ी की कहानी

साइबर ठगी से बचने के लिए सतर्क रहें

डिजिटल जोखिम कम करने के लिए सतर्कता और तुरंत कार्रवाई करना सबसे जरूरी है। अपना ओटीपी, यूपीआई पिन, सीवीवी और नेट बैंकिंग पासवर्ड किसी से साझा न करें। कोई पुलिस, सीबीआई या जज बनकर वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी का डर दिखाए या पैसे मांगे, तो घबराएं नहीं। अनजान लिंक पर क्लिक करने और सार्वजनिक वाई-फाई पर बैंकिंग करने से बचें।

आशीष सकलेचा
जावरा, मध्य प्रदेश

सख्त कानून से थमेगा साइबर अपराध

बैंकों और फिनटेक कंपनियों के डिजिटल बुनियादी ढांचे को 'जीरो-ट्रस्ट आर्किटेक्चर' तथा बहुस्तरीय प्रमाणीकरण से अभेद्य बनाना अनिवार्य है। वित्तीय धोखाधड़ी तुरंत रोकने के लिए '1930' जैसी हेल्पलाइन का विस्तार कर कार्रवाई करने में लगने वाले समय को कम से कम किया जाना चाहिए। साथ ही, एआई आधारित धोखाधड़ी से सुरक्षा तंत्र को बढ़ावा देना चाहिए।

डॉ. मोहिनी नेवासकर
गोरेगांव, महाराष्ट्र

जागरूकता ही बचाएगी ठगी से

साइबर अपराधी कभी अधिक मुनाफे का लालच देते हैं, तो कभी पुलिस कार्रवाई या बैंक खाता बंद होने का डर दिखाकर पैसे ऐंठते हैं। इससे बचने के लिए ओटीपी, यूपीआई पिन और पासवर्ड किसी से साझा न करें। अनजान लिंक से बचें और संदिग्ध ऐप डाउनलोड न करें। ठगी होने पर तुरंत 1930 पर शिकायत करें। सरकार, पुलिस और बैंकों को जागरूकता अभियान चलाने चाहिए।

सुभाष बुड़ावन वाला
रतलाम, मध्य प्रदेश

निजी जानकारी को गोपनीय रखें

साइबर जोखिम कम करने के लिए सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है मजबूत और समय-समय पर बदलते हुए अलग-अलग पासवर्ड का उपयोग करना। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने या संदिग्ध संदेशों का उत्तर देने से बचने के साथ ही ओटीपी, बैंक विवरण और निजी जानकारी को सदैव गोपनीय रखना भी महत्त्वपूर्ण है। मोबाइल और कंप्यूटर को नियमित रूप से अपडेट करना भी जरूरी है।

कृतिका अग्रवाल
मुंबई, महाराष्ट्र

'रुको, सोचो और जांचो' मंत्र अपनाएं

साइबर ठगी से बचने के लिए 'रुको, सोचो और जांचो' का मंत्र अपनाना जरूरी है। किसी अनजान लिंक, क्यूआर कोड या संदिग्ध कॉल पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें, बल्कि सोचें कि बैंक या पुलिस ऐसी जानकारी क्यों मांगेंगे और संदेह होने पर जांच करें। अपना यूपीआई पिन किसी से साझा न करें और न ही किसी के कहने पर दर्ज करें। फर्जी वीडियो कॉल से भी सावधान रहें।

मनमोहन राजावत
शाजापुर, मध्य प्रदेश

ठगी रोकने के लिए ठोस कदम जरूरी

साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए सरकार को केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि ठोस कदम उठाने चाहिए। हाल में एसबीआई के ग्राहकों का डेटा लीक होने की खबरें चिंता बढ़ाती हैं। साइबर ठगी की शिकायत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। बैंकों की छुट्टियों के दौरान भी शिकायत दर्ज कराने की सुविधा होनी चाहिए। सभी बैंकों को 24 घंटे मुफ्त हेल्पलाइन उपलब्ध करानी चाहिए।

राजेश कुमार चौहान
जालंधर, पंजाब

सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाएं

आज साइबर अपराध, डेटा में सेंध और डिजिटल पहचान की चोरी बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा ऑनलाइन सेवाओं के लिए गंभीर चुनौती बन गए हैं। डेटा का नियमित बैकअप, डेटा संग्रह को आवश्यकता तक सीमित रखना और डेटा में सेंध की स्थिति में तुरंत सूचना एवं प्रतिक्रिया तंत्र विकसित करना भी जरूरी है। लोगों को सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाना चाहिए।

मयंक लोभाने
इंदौर, मध्य प्रदेश

साइबर सुरक्षा नीति अपनाएं संस्थान

बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर साइबर हमलों और ठगी की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसके बावजूद कई संस्थान एक समान साइबर सुरक्षा नीति नहीं अपनाते। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दिशा-निर्देशों की मदद से वे ऐसी नीति बना सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। ओटीपी व्यवस्था में सुधार के साथ लेनदेन के लिए दोहरी सुरक्षा अपनाने की जरूरत है।

विनोद जौहरी
दिल्ली

संदिग्ध ईमेल और लिंक से बचें

ऑनलाइन सुरक्षा मजबूत करने के लिए जटिल पासवर्ड का इस्तेमाल करें और उन्हें समय-समय पर बदलते रहें। ईमेल, बैंक और सोशल मीडिया खातों पर दो-स्तरीय प्रमाणीकरण सक्रिय रखें। इससे पासवर्ड चोरी होने पर भी अतिरिक्त सुरक्षा मिलती है। सॉफ्टवेयर और ऐप को नियमित रूप से अपडेट करें। संदिग्ध ईमेल और लिंक से बचें तथा सुरक्षित वेबसाइटों का ही उपयोग करें।

ललित महालकरी
इंदौर, मध्य प्रदेश

मजबूत बनाना होगा साइबर सेल

इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साइबर अपराध और ऑनलाइन अभद्रता की चुनौतियां भी बढ़ी हैं। ऐसे में जागरूकता बेहद जरूरी है। अनजान लिंक, ईमेल और संदिग्ध अटैचमेंट खोलने से बचना चाहिए। पुलिस अधिकारियों को साइबर अपराधों से निपटने का प्रशिक्षण दिया जाए। साइबर सेल और हेल्पलाइन को मजबूत बनाया जाए।

सुधीर कुमार सोमानी
देवास, मध्य प्रदेश

सावधानी से कम होंगे साइबर जोखिम

भारत में फिशिंग, हैकिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डेटा चोरी के खतरे बढ़ रहे हैं। इनसे बचने के लिए मजबूत पासवर्ड, दो-चरणीय सत्यापन और नियमित सॉफ्टवेयर अपडेट जरूरी है। ओटीपी और निजी जानकारी किसी से साझा न करें। सार्वजनिक वाईफाई पर बैंकिंग जैसे संवेदनशील काम करने से बचें। सावधानी से ही साइबर तकनीक को सुरक्षित और उपयोगी बनाया जा सकता है।

अंबिका कुशवाहा
पटना, बिहार

सावधानी से ही सुरक्षा संभव है

साइबर अपराध, ऑनलाइन ठगी और पहचान की चोरी जैसे जोखिमों को कम करने के लिए जागरूकता आवश्यक है। बैंक के प्रत्येक खाते के लिए अलग-अलग पासवर्ड रखते हुए दो स्तरीय प्रमाणीकरण अपनाते हुए ओटीपी, पासवर्ड और बैंक संबंधी जानकारी गोपनीय बनाए रखना आवश्यक है। अनजान लिंक संदिग्ध मेल और फर्जी वेबसाइटों से सावधान रहना चाहिए।

मेघा योगेश
आष्टा, मध्य प्रदेश

बकौल विश्लेषक

बैंक सुरक्षा तंत्र मजबूत करें



डिजिटल बैंकिंग के कारण साइबर ठग ग्राहकों के बैंक खाते से भी पैसा निकाल रहे हैं चाहे वो डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से या लिंक, ओटीपी लेकर हो। साइबर जोखिम से बचने के लिए ग्राहकों को दो तरह के बैंक खाते रखने की जरूरत है। डिजिटल सुविधाओं वाले खाते में जरूरत के हिसाब से न्यूनतम राशि रखी जाए। वहीं दूसरा खाता वह हो, जिससे लेनदेन चेक या बैंक जाकर पैसा निकालकर किया जाए। बैंक खाते में सेंधमारी रोकने के लिए बैंकों को सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना चाहिए। सरकार को लोगों को ऐसे एप्लिकेशन मुफ्त में देने चाहिए जो कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, सर्वर और अन्य डिजिटल उपकरणों को साइबर हमलों, वायरस और हैकिंग से सुरक्षित रख सकें। साथ ही साइबर खतरों से बचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाने चाहिए। उपयोगकर्ताओं को किसी को भी डेटा साझा करने में सावधानी बरतनी चाहिए। डीपीडीपी कानून भी साइबर जोखिम कम करने में सहायक साबित हो सकता है।

बातचीत: रामवीर सिंह गुर्जर

एडवोकेट पुनीत भसीन
साइबर कानून विशेषज्ञ

बचाव के लिए बरतें जरूरी सावधानी



आज इंटरनेट, स्मार्टफोन, ऑनलाइन बैंकिंग और सोशल मीडिया हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। तकनीक ने जहां हमारे जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाया है, वहीं साइबर अपराधों के जोखिम भी बढ़ाए हैं। इन जोखिमों से बचने के लिए सभी ऑनलाइन खातों के लिए अलग-अलग और मजबूत पासवर्ड बनाएं तथा मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन सक्रिय रखें। किसी अनजान लिंक, ई-मेल या संदेश पर बिना जांच किए क्लिक न करें और ओटीपी, पिन, पासवर्ड तथा बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें। एआई के बढ़ते इस्तेमाल के दौर में नकली आवाज, वीडियो और संदेशों के प्रति भी सतर्क रहें। अपने मोबाइल, कंप्यूटर और ऐप्स को नियमित रूप से अपडेट रखें। सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा करते समय सावधानी बरतें और अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स की समय-समय पर जांच करें।

बातचीत : संदीप कुमार

डॉ. अतुल कुमार पांडेय
प्रमुख, साइबर विधि विभाग, एनएलआईयू, भोपाल

पुरस्कृत पत्र

1

देवेंद्रराज सुथार
जालोर, राजस्थान

पुरस्कार राशि 500 रुपये

मजबूत और बहुस्तरीय सुरक्षा तंत्र की दरकार

साइबर खतरे की चुनौती से निपटने के लिए एक मजबूत और बहुस्तरीय सुरक्षा तंत्र की आवश्यकता है। व्यक्तिगत स्तर पर डिजिटल सुरक्षा को अपनाना बेहद जरूरी है, जिसमें जटिल पासवर्ड का उपयोग, दो-स्तरीय प्रमाणीकरण और फिशिंग स्कैम्स से सतर्क रहना शामिल है। वहीं, कॉरपोरेट और सरकारी स्तर पर एआई आधारित थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम और नियमित सुरक्षा ऑडिट को अनिवार्य करना चाहिए। एक सुरक्षित डिजिटल भविष्य के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की भागीदारी से साइबर-जागरूकता ही एकमात्र रास्ता है।

श्रेष्ठ पत्र

रोशनी यादव
अयोध्या, उत्तर प्रदेश

मजबूत पासवर्ड जरूरी

साइबर सुरक्षा के लिए तकनीकी उपायों के साथ व्यक्तिगत सतर्कता भी जरूरी है। सभी डिजिटल खातों के मजबूत और अलग-अलग पासवर्ड रखें तथा दो-स्तरीय प्रमाणीकरण चालू करें। मोबाइल और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर व ऐप को नियमित रूप से अपडेट करें। अनजान ईमेल, संदेशों और संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें। सार्वजनिक वाई-फाई पर बैंकिंग या संवेदनशील काम न करें और जरूरी डेटा का सुरक्षित बैकअप रखें।

डॉ. ऋषभ देव पांडेय
भड़ेसर, छत्तीसगढ़

सावधानी से जोखिम कम

साइबर जोखिमों से बचने के लिए सतर्कता जरूरी है। इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल करते समय मजबूत पासवर्ड रखें और खातों की सुरक्षा के लिए दो-स्तरीय प्रमाणीकरण अपनाएं। अनजान लिंक, ई-मेल और संदिग्ध संदेशों पर क्लिक करने से बचें। किसी के साथ ओटीपी, पासवर्ड या बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी साझा न करें। मोबाइल, कंप्यूटर और सुरक्षा सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट करते रहें।

धीरेंदु कपिला
बेंगलूरु, कर्नाटक

सरकार निभाए भूमिका

साइबर जोखिम कम करने के लिए सरकार और बैंकों की संयुक्त भागीदारी जरूरी है। सरकार को साइबर जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। डिजिटल लेनदेन से जुड़ा वास्तविक समय का डेटा उपलब्ध कराने से लोगों को डिजिटल भुगतान की स्थिति समझने में मदद मिलेगी। बैंकों को ग्राहकों की जानकारी और लेनदेन सुरक्षित रखने के लिए एन्क्रिप्शन, बहुस्तरीय प्रमाणीकरण और नियमित सुरक्षा जांच अपनानी चाहिए।

...और यह है अगला मुद्दा

हर सोमवार को हम सम-सामयिक विषय पर व्यापार गोष्ठी में आपके विचारों को प्रकाशित करते हैं। साथ ही, होती है दो विशेषज्ञों की राय।

इस बार का विषय है -

सभी तरह के बैंकों में क्या हों सुधार?

अपनी राय अपने टेलीफोन नंबर और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें:
बिज़नेस स्टैंडर्ड (हिंदी), नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002
फैक्स नंबर- 011-3720201
या फिर ई-मेल करें
goshthi@bsmail.in

रिटेल बिलों की डिजिटल निगरानी

पृष्ठ 1 का शेष

एक अन्य अधिकारी ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर कहा कि खुदरा बिलों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज करने के विचार पर कई वर्षों से चर्चा हो रही है। हालांकि हर दिन होने वाले छोटे मूल्य के भारी संख्या में लेनदेन को प्रोसेस करने की चुनौती के कारण इसे लागू करने में देर हुई।

अधिकारी ने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर आंकड़ों को संग्रहीत और प्रोसेस करने के लिए सर्वर की पर्याप्त क्षमता की जरूरत होगी। पहले की तकनीकी व्यवस्था इतनी बड़ी मात्रा में आंकड़ों को संभालने के लिए तैयार नहीं थी।

उन्होंने कहा कि खुदरा स्तर पर ई-इनवॉइसिंग से विदेशी पर्यटकों को भी फायदा हो सकता है। वे भारत में की गई खरीदारी पर चुकाए गए जीएसटी का रिफंड अपने देश लौटते समय प्राप्त कर सकेंगे क्योंकि सीमा शुल्क अधिकारी कर भुगतान का आसानी से सत्यापन कर पाएंगे।

एक अन्य सरकारी अधिकारी ने बताया कि जीएसटी प्रणाली का तकनीकी ढांचा संभालने वाले जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने 2025 में इन्फोसिस को सात साल का नया ठेका दिया था। इससे पहले मूल ठेके की पांच साल की शुरुआती अवधि समाप्त होने के बाद उसे बढ़ाया गया था।

अधिकारियों का मानना है कि नए अनुबंध में आंकड़ों के भंडारण और प्रोसेसिंग की बढ़ी हुई क्षमता को ध्यान में रखा गया है। उन्होंने कहा कि एक साझा प्रणाली में बिलों का ब्योरा रखने से अनुपालन लागत घट सकती है। इससे अलग-अलग विवरणों और मैनुअल जांच पर निर्भर रहने के बजाय बिलों का मिलान और ऑडिट अधिक कुशलता से किया जा सकेगा। अधिकारियों के मुताबिक रीयल टाइम में तैयार (टाइमस्टैम्प यानी समय की जानकारी के साथ) डिजिटल रिकॉर्ड से पारदर्शिता भी बढ़ सकती है। साथ ही बिलों में बाद में किए जाने वाले बदलावों का पता लगाना भी आसान होगा।

सरकार ब्राजील और चिली जैसे देशों की ई-इनवॉइसिंग प्रणालियों का भी अध्ययन कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि इन दोनों देशों में कारोबारी और ग्राहक लेनदेन के लिए लंबे समय से इलेक्ट्रॉनिक बिलों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

विशेषज्ञों का कहना है कि खुदरा क्षेत्र में ई-इनवॉइसिंग का प्रभाव काफी व्यापक हो सकता है।

पीडब्ल्यूसी इंडिया में पार्टनर प्रशांत अग्रवाल ने कहा, 'सरकार ई-इनवॉइसिंग का इस्तेमाल उन ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए कर सकती है जो अपनी खरीदारी के लिए जीएसटी के अनुरूप वैध बिल मांगते हैं। इससे असंगठित क्षेत्र को संगठित क्षेत्र की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।'

विशेषज्ञों ने वित्तीय क्षेत्र को बी2बी ई-इनवॉइसिंग से मिली सभांवित छूट वापस लेने के प्रस्ताव का भी स्वागत किया है।

ईवाई इंडिया में टैक्स पार्टनर दिव्येश लपसीवाला ने कहा कि बैंकिंग, एनबीएफसी और बीमा जैसे क्षेत्रों में ई-इनवॉइसिंग लागू होने से अर्थव्यवस्था के सभी बी2बी लेनदेन इसके दायरे में आएंगे। उन्होंने कहा, 'इन क्षेत्रों के ग्राहकों को भी इसका फायदा मिलेगा। लेकिन इन क्षेत्रों को पर्याप्त समय देना जरूरी होगा क्योंकि यहां बी2बी लेनदेन की संख्या बहुत अधिक है और कई संस्थाएं अपने विशेष जरूरतों के अनुरूप तैयार किए गए बिलिंग सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं।'

लपसीवाला ने कहा, 'कुल मिलाकर यह एक सकारात्मक बदलाव है और जीएसटी नीति विभाग इस व्यवस्था को सफल बनाने के लिए क्षेत्रीय संगठनों के साथ मिलकर काम कर सकता है।'

नांगिया ग्लोबल के कार्यकारी निदेशक (अप्रत्यक्ष कर) शिवकुमार रामजी ने कहा कि बैंक और एनबीएफसी हर दिन लाखों छोटे शुल्कों से जुड़े लेनदेन करते हैं। उन्होंने कहा, 'बी2सी (व्यवसायी से खरीदार) पायलट परियोजना को संगठित खुदरा कारोबार, ई-कॉमर्स, क्विक कॉमर्स और ऑनलाइन गेमिंग जैसे प्रौद्योगिकी आधारित क्षेत्रों तक सीमित रखना और वित्तीय संस्थानों को पहले केवल बी2बी व्यवस्था के दायरे में लाना व्यावहारिक दृष्टिकोण है।'

महिला रोजगार में विरोधाभास

हिमांशी भारद्वाज



भारत में महिला कर्मचारियों की संख्या पिछले सात साल में दोगुनी हो गई है, लेकिन उनकी नौकरियां कम सुरक्षित, काम के कम घंटों वाली और पुरुषों की तुलना में कम वेतन वाली हो गई हैं। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनैशनल इकनॉमिक रिलेशंस (इक्रियर) के एक नए अध्ययन में यह बात सामने आई है।

'द पार्टिसिपेशन पैराडॉक्सः वीमेन्स वर्क ऐंड टाइम यूज इन इंडिया 2017-18 टु 2025' नामक इस अध्ययन में कहा गया है कि महिलाओं ने वेतन वाला काम संभाला है, जबकि घर पर उनके अवैतनिक काम का बोझ कम नहीं हुआ है। इसके चलते महिलाओं को आराम और अपनी देखभाल में लगने वाले वक्त में कटौती करनी पड़ रही है।

आवधिक श्रम बल सर्वे (पीएलएफएस) के आंकड़ों का हवाला देते हुए अध्ययन में कहा गया है कि कामकाजी महिलाओं की संख्या 2017-18 के 10.4 करोड़ से बढ़कर 2025 में 20.1 करोड़ हो गई, जो लगभग दोगुना है।

हालांकि यह वृद्धि मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में केंद्रित रही और लगभग पूरी तरह से कृषि क्षेत्र में रोजगार मिला है। अध्ययन में कहा गया है, 'पुरुषों के मामले में ढांचागत बदलाव नजर आ रहा है, लेकिन देश की महिलाओं के मामले में ऐसा नहीं है।'

नए श्रमिकों को नियमित वेतन वाली नौकरियां भी नहीं मिलीं। अध्ययन में कहा गया है, 'इसलिए कार्यबल में शामिल होने वाली अतिरिक्त महिलाओं ने मुख्य रूप से स्वरोजगार और अवैतनिक पारिवारिक श्रम के माध्यम से प्रवेश किया है। यह सबसे असुरक्षित और सबसे कम वेतन वाली श्रेणियां हैं।' ग्रामीण महिलाओं में नियमित वेतन वाली नौकरियों का हिस्सा दरअसल कम हुआ है।

अध्ययन में कहा गया है कि शहरी इलाकों में सेवा आधारित वृद्धि से अर्थव्यवस्था संचालित हो रही है, वहीं महिलाओं के मामले में यह कहना कठिन है कि अवसर में सुधार के कारण उन्हें रोजगार के अवसर मिले हैं। लेखकों का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में कामगारों की अनिवार्य जरूरतों के कारण महिला श्रमिकों को काम मिला है, चाहे वह कृषि क्षेत्र हो या परिवार द्वारा चलाए जा रहे उद्यम में महिलाओं को काम मिलने का मामला हो। काम के घंटों के आंकड़ों से भी यही पता चलता है। ग्रामीण महिलाओं के काम के साप्ताहिक घंटे 6 घंटे से कुछ अधिक कम हो गए, जो किसी भी समूह में सबसे बड़ी गिरावट है। अध्ययन में कहा गया है कि प्रति कर्मचारी घटते घंटों के साथ बढ़ती भागीदारी का अर्थ है कि कर्मचारियों की संख्या उन क्षेत्रों में बढ़ी है, जहां कम कुशलता वाले काम होते हैं। कृषि कार्य से लोगों को बाहर निकालने में विनिर्माण क्षेत्र प्रमुख रहा है। वहां भी महिलाओं की प्रमुख भूमिका नहीं है।

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक

(संसद के एक अधिनियम, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम 2021 द्वारा स्थापित एक विकास वित्तीय संस्थान)

कार्यालय: द कैपिटल, ए–विंग, 15वीं मंजिल–1503, जी ब्लॉक, बांद्रा–कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400051
दूरभाष: (022) 41042000; वेबसाइट: www.nabfid.org

30 सितंबर 2026 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त छमाही		समाप्त वर्ष
		30-09-2026 (अलेखापरीक्षित)	30-06-2026 (अलेखापरीक्षित)	30-09-2025 (अलेखापरीक्षित)	30-09-2026 (अलेखापरीक्षित)	30-09-2025 (अलेखापरीक्षित)	31-03-2026 (लेखापरीक्षित)
1	परिचालनों से कुल आय	3,266.42	2,896.14	1,764.75	6,162.56	3,474.38	7,585.12
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, अपवादात्मक तथा/या असाधारण मदों से पूर्व)	1,070.87	801.85	771.47	1,872.72	1,485.95	3,036.67
3	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (अपवादात्मक तथा/या असाधारण मदों के पश्चात)	1,070.87	801.85	771.47	1,872.72	1,485.95	3,036.67
4	कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (अपवादात्मक तथा/या असाधारण मदों के पश्चात)	1,070.87	801.85	771.47	1,872.72	1,485.95	3,036.67
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय {अवधि के लिए लाभ/(हानि) (कर के पश्चात) तथा अन्य समेकित आय (कर के पश्चात) को समाविष्ट करते हुए}	टिप्पणी 4 देखें					
6	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
7	आरक्षित निधि (पिछले वर्ष के तुलनपत्र के अनुसार) (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि को छोड़कर और भारत सरकार से प्राप्त अनुदान सहित)	-	-	-	-	-	14,418.98
8	प्रतिभूमि प्रीमियम खाता	-	-	-	-	-	-
9	निवल मूल्य	36,272.29	35,170.69	32,591.18	36,272.29	32,591.18	34,260.17
10	चुकता ऋण पूंजी/बकाया ऋण	1,38,905.73	1,20,026.43	54,307.38	1,38,905.73	54,307.38	1,06,170.74
11	बकाया प्रतिदेय वरीयता शेयर	-	-	-	-	-	-
12	ऋण इक्विटी अनुपात	3.93	3.50	1.74	3.93	1.74	3.19
13	प्रति शेयर आय (प्रत्येक ₹ 10/-)						
	मूलभूत : (अवार्षिकीकृत)	0.54	0.40	0.39	0.94	0.74	1.52*
	तनुकृत : (अवार्षिकीकृत)	0.54	0.40	0.39	0.94	0.74	1.52*
14	पूंजी मोचन आरक्षित	-	-	-	-	-	-
15	डिबेन्चर मोचन आरक्षित	-	-	-	-	-	-
16	कर्ज सेवा कवरेज अनुपात	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
17	ब्याज सेवा कवरेज अनुपात	1.53	1.53	1.88	1.53	1.85	1.83

*वार्षिकीकृत

टिप्पणी :–

1. उपर्युक्त भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता और अन्य प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 52 के अधीन विस्तृत प्रारूप में स्टॉक एक्सचेंज में फ़ाइल किए गए समाप्त तिमाही एवं छमाही के वित्तीय परिणामों का सारांश है। सितम्बर 30, 2026 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज और सूचीबद्ध संस्थान की वेबसाइट **(www.bseindia.com, www.nseindia.com** और **www.nabfid.org)** पर उपलब्ध है और निम्नलिखित क्विक रिस्पांस कोड को स्कैन करके भी देखा जा सकता है।
2. लिस्टिंग विनियमों के विनियम 52 (4) में संदर्भित अन्य लाइन आइटम के लिए स्टॉक एक्सचेंजों (बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) को प्रासंगिक खुलासे किए गए हैं और इन्हें यूआरएल **www.bseindia.com** और **www.nseindia.com** पर देखा जा सकता है।
3. उपरोक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई है और इसकी संस्तुति की गई है तथा अक्टूबर 30, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा इसे अनुमोदित किया गया है। सितम्बर 30, 2026 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के इन परिणामों की सीमित समीक्षा वैधानिक लेखापरीक्षक द्वारा की जा चुकी है जिन्होंने इस पर एक असंशोधित सीमित समीक्षा रिपोर्ट जारी की है।
4. कुल व्यापक आय और अन्य व्यापक आय से संबंधित जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है क्योंकि ''इंड एएस'' अभी तक लागू नहीं हुआ है।
5. पिछली अवधि के आंकड़ों को चालू अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप, जहां कहीं आवश्यक है, पुनः समूहीकृत/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

स्थान: मुम्बई
दिनांक: अक्टूबर 30, 2026

हस्ता./–
बी. एस. वेंकटेशा
डीएमडी – सीआरओ

हस्ता./–
मोनिका कालिया
डीएमडी – सीएफओ

हस्ता./–
राजकिरण राय जी.
प्रबंध निदेशक

बाजार
हलचल

मल्टी ऐसेट फंड भी फंसे, नहीं दे पा रहे रिटर्न

मल्टी-ऐसेट फंडों को म्यूचुअल फंड उद्योग में हर तरह के हालात में अच्छा प्रदर्शन करने वाला माना जाता है, पर आजकल ये फंड भी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। इस श्रेणी ने औसतन केवल 1.4 फीसदी का रिटर्न दिया है और कई योजनाएं तो घाटे में चली गई हैं। साल 2025 में इन फंडों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। उस समय जब इक्विटी, डेट और हाइब्रिड श्रेणियां यानी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड संघर्ष कर रहे थे, तब मल्टी-ऐसेट फंड रिटर्न में इन सबसे आगे थे। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। इक्विटी और डेट मार्केट में लगातार कमजोरी बनी हुई है और कीमती धातुओं की कीमतों में भी एक बड़ी तेजी के बाद गिरावट आई है। इन सब वजहों से तीनों तरह के परिसंपत्ति वर्ग पर बुरा असर पड़ा है, जिससे इस श्रेणी को मिलने वाला विविधीकरण का फायदा भी खत्म हो गया है।

खरीद की राह पर एफपीआई मगर सतर्कता कायम

कई हफ्तों तक लगातार बिकवाली करने के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) अब भारतीय शेयरों में खरीदारी की ओर लौटते दिख रहे हैं। लेकिन बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इसे अभी से रुझान में बदलाव मान लेना जल्दबाजी होगी। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के मुख्य निवेश रणनीतिकार वी.के. विजयकुमार ने कहा, इसे रुझान में बदलाव कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन शुरुआती संकेत सकारात्मक हैं। उन्होंने इस बदलाव के लिए आकर्षक मूल्यांकन, घरेलू वृद्धि की बेहतर संभावनाएं और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों को स्थिर रखने जैसे कारणों को बताया। चॉइस वेल्थ के मुख्य निवेश रणनीति अधिकारी धीरज गौर ने भी सावधानी बरतने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि लगातार नौ खराब हफ्तों के बाद एक अच्छा हफ्ता आना कोई ट्रेंड नहीं बन जाता। उन्होंने यह भी बताया कि इस खरीदारी का एक बड़ा हिस्सा जियो प्लेटफॉर्म्स के आवंटन के जरिये आया है।

संकलन : अभिषेक कुमार

डिक्सन के मार्जिन पर सतर्क हैं ब्रोकर

कीमत में गिरावट, बाजार हिस्सेदारी में हुआ इजाफा शेयर में ठीक-ठाक बढ़त के लिए है सकारात्मक

राम प्रसाद साहू
मुंबई, 1 नवंबर



भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सेवा (ईएमएस) कंपनी डिक्सन टेक्नॉलजीज ने सितंबर तिमाही में राजस्व के मोर्चे पर उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया जबकि परिचालन प्रदर्शन औसत से कम रहा। तिमाही के दौरान बिक्री में मजबूत वृद्धि का मुख्य कारण कीमतों में बढ़ोतरी थी, जो मेमरी की कीमतों में भारी उछाल की वजह से की गई थी। जहां पिछले एक साल में स्मार्टफोन उद्योग की कुल बिक्री में गिरावट आई है, वहीं डिक्सन स्थिर बिक्री संख्या के साथ अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने में सफल रही है। आगे चलकर, निवेशक वीवो के साथ जॉइंट वेंचर के तहत उत्पादन की प्रगति, बैकवर्ड इंटिग्रेशन से होने वाले फायदों और कमोडिटी की ऊंची कीमतों के बीच मार्जिन के रुझान पर नजर रखेंगे।

मौजूदा कीमत (11,000 रुपये) पर यह शेयर वित्त वर्ष 28 के अपने अनुमानित मुनाफे के 43 गुना पर ट्रेड कर रहा है। हालांकि दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद मार्जिन पर दबाव है और कुछ डाउनग्रेड भी हुए हैं। शुक्रवार को शेयर 4.3 फीसदी नीचे था। लेकिन पिछले तीन महीनों में 21 फीसदी से अधिक की गिरावट का मतलब है कि मौजूदा स्तरों से और गिरावट की गुंजाइश शायद सीमित हो।

ईएमएस क्षेत्र की प्रमुख कंपनी का राजस्व सालाना आधार पर 47 फीसदी बढ़ गया। यह प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर और अनुमानों से ज्यादा रहा। इस बढ़त में मोबाइल सेगमेंट का सबसे बड़ा योगदान रहा, जिसकी हिस्सेदारी इस तिमाही की कुल बिक्री में 92 फीसदी थी। इसकी बिक्री में सालाना आधार पर 50 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। जहां वॉल्यूम स्थिर रहा, वहीं मोबाइल और आईटी हार्डवेयर के मामले में वैल्यू के लिहाज से 35-40 फीसदी की अच्छी वृद्धि देखने को मिली।

ऐसा मेमरी मॉड्यूल की कीमतों में तेजी से हुई बढ़ोतरी के कारण हुआ। कंपनी मोबाइल सेगमेंट में अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ा रही है और उसने 97 लाख मोबाइलों की बिक्री की है। यह आंकड़ा सालाना आधार पर स्थिर रहा, जबकि तिमाही आधार पर इसमें 29 फीसदी की वृद्धि देखी गई। हालांकि, यह सेक्टर अभी सुस्त चल रहा है। एंट्री-टु-मिड लेवल सेगमेंट में बिक्री सालाना आधार पर 26 फीसदी गिर गई है, जबकि पूरे स्मार्टफोन बाजार की बिक्री में पिछले साल की तुलना में 16 फीसदी की गिरावट आई है। कंपनी को अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के विस्तार और बेहतर प्राप्ति की बदौलत आईटी हार्डवेयर/टेलीकॉम सेगमेंट में अपना दायरा बढ़ाने से फायदा मिला है।

मोबाइल से इतर दूसरे सेगमेंट यानी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में सालाना आधार पर 17 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। बिक्री में इसकी 5 फीसदी हिस्सेदारी है। पॉलिमर की ऊंची कीमतों और माल ढुलाई महंगी होने के कारण रेफ्रिजरेटर पर दबाव रहा, जबकि एंट्री-लेवल के एलईडी टीवी की मांग कमजोर रही। होम अप्लायंसेज की बिक्री में 3 फीसदी हिस्सेदारी रही जो सालाना आधार पर 37 फीसदी बढ़ी। इसमें वॉशिंग मशीनों की मांग में तेजी का मुख्य योगदान रहा।

हालांकि उद्योग में बिक्री कम देखी जा रही है। लेकिन कंपनी को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 27 में उसकी बिक्री संख्या 3.3 से 3.4 करोड़ तक पहुंच जाएगी। इसमें वीवो जेवी का भी योगदान होगा, और जिसमें वित्त वर्ष 27 की चौथी तिमाही से उत्पादन शुरू हो जाएगा। वित्त वर्ष 28 में यह आंकड़ा लगभग 5.5-6.0 करोड़ रहने की उम्मीद है।

मोतीलाल ओसवाल रिसर्च का अनुमान है कि वित्त वर्ष 28 में डिक्सन की बिक्री संख्या कई वजहों से बढ़ेगी- नए घरेलू ग्राहकों के जुड़ने से 60-80 लाख का अतिरिक्त वॉल्यूम मिल सकता है। मुख्य ग्राहकों मोटोरोला और ट्रांशन से होने वाला निर्यात वित्त वर्ष 27 के 35 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 28 में लगभग 50-60 लाख तक पहुंच सकता है और वीवो जेवी से 1.8-2.0 करोड़ का वॉल्यूम बढ़ सकता है। ब्रोकरेज ने इस शेयर के लिए खरीद की रेटिंग दी है और लक्षित कीमत 15,900 रु. तय की है।

ब्रोकरेज की टीना विरमानी की अगुआई वाली विश्लेषकों की टीम का मानना है कि वित्त वर्ष 28 में कंपनी को बैकवर्ड इंटिग्रेशन का पूरा फायदा मिलेगा। साथ ही, वीवी जेवी, निर्यात और नए ग्राहकों के जुड़ने से वॉल्यूम में भी सुधार देखने को मिलेगा। ब्रोकरेज ने वित्त वर्ष 27 और 28 के लिए कमाई के अनुमानों को क्रमशः 7 फीसदी और 2 फीसदी बढ़ा दिया है। ऐसा वित्त वर्ष 27 की पहली छमाही के प्रदर्शन और अल्पांश हिस्सेदारी में थोड़ी कमी को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

दूसरी तिमाही में मार्जिन का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। कंपनी ने बताया कि मार्जिन में सालाना आधार पर 110 आधार अंकों की गिरावट आई है और यह 2.7 फीसदी पर आ गया है। इसका कारण मोबाइल प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव (पीएलआई) का खत्म होना और कच्चे माल की लागत में हुई बढ़ोतरी का बोझ ग्राहकों पर डालने में देरी होना है। मोबाइल और ईएमएस सेगमेंट के मार्जिन में 100 आधार अंकों की गिरावट आई और ये 2.5 फीसदी रह गए। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की लाभप्रदता 50 आधार अंक घटकर 3.6 फीसदी रह गई और होम अप्लायंसेज के मार्जिन में 350 आधार अंकों की गिरावट के साथ यह 8.2 फीसदी पर आ गया।

इलारा सिक्योरिटीज ने इस शेयर की रेटिंग घटाकर रिड्यूस कर दी है और नया लक्ष्य 11,500 रुपये तय किया है। ब्रोकरेज फर्म के हर्षित कापड़िया के नेतृत्व वाले विश्लेषकों का मानना है कि ऐसा कई कारणों से हुआ है- वीवो के साथ जॉइंट वेंचर में देरी, मोबाइल वॉल्यूम पर लगातार दबाव और मोबाइल पीएलआई योजना खत्म होने तथा कम मार्जिन वाले आईटी हार्डवेयर सेगमेंट के विस्तार के कारण मार्जिन पर असर पड़ना। इसके अलावा, कमाई में बढ़ोतरी की रफ्तार भी पहले के मुकाबले धीमी हो रही है। वित्त वर्ष 23-26 के दौरान कमाई में 86 फीसदी की बढ़ोतरी का अनुमान था, जबकि वित्त वर्ष 26-29 के लिए यह अनुमान 10 फीसदी है।

हालांकि, दौलत कैपिटल ने इस शेयर की रेटिंग को एक्युमुलेट से बढ़ाकर खरीद कर दी है और लक्ष्य 14,040 रुपये तय किया है। ब्रोकरेज फर्म की निकहत कूर और सारंग शेट्टी के अनुसार हाल में शेयर की कीमत में आई गिरावट के बाद अब जोखिम और मुनाफे का अनुपात अनुकूल हो गया है।

बिक्री में मजबूत वृद्धि

आंकड़े करोड़ रु.	वित्त वर्ष 26	वित्त वर्ष 27*	वित्त वर्ष 28 *
राजस्व	48,872	74,222	94,852
सालाना बदलाव %	25.8	51.9	27.8
परिचालन लाभ	1,866	2,120	3,459
सालाना बदलाव %	23.8	13.6	63.2
मार्जिन %	3.8	2.9	3.6
शुद्ध लाभ	1,438	1,490	1,554
सालाना बदलाव %	31.3	3.6	4.3

* : अनुमान
स्रोत : मोतीलाल ओसवाल रिसर्च

यहां एआई से जुड़ा कारोबार हमेशा स्मॉलकैप शेयरों में रहा है

अब जब बड़ी टेक कंपनियों में गिरावट आई है तो क्या इस कारोबार पर भी असर पड़ेगा?

कैरवी लुक्का और प्रवीण पालांडे
मुंबई, 1 नवंबर

सबसे अच्छा रिटर्न देने वाली दस अग्रणी स्मॉलकैप कंपनियों में से सात अमेरिका में डेटा सेंटर की तेजी का फायदा उठा रही हैं। लेकिन अब जब वॉल स्ट्रीट पर भरोसा डगमगाया है तो विश्लेषक इन शेयरों को उनकी असल कीमत से कहीं ज्यादा महंगा मान रहे हैं। यह धारणा गलत साबित हुई है कि एआई के लिए अमेरिकी फंडिंग कभी नहीं रुकेगी। इसका असर इन कंपनियों के शेयरों की कीमतों पर नकारात्मक रूप से पड़ सकता है, भले ही इनके पास सचमुच में ऑर्डर ही क्यों न हों।

पिछले एक साल में सुस्त बाजार के बावजूद स्मॉलकैप शेयर निवेशकों की पहली पसंद रहे हैं। हालांकि यह तेजी काफी चुनिंदा रही है। निफ्टी स्मॉलकैप 250 इंडेक्स में शामिल केवल 90 शेयरों ने ही पिछले एक साल में फायदे वाला रिटर्न दिया है जबकि बाकी शेयरों में गिरावट आई है।

सबसे ज्यादा फायदे वाली कंपनियों में स्टरलाइट टेक्नॉलजीज सबसे ऊपर रही। इसके शेयर की कीमत पिछले एक साल में लगभग 602 फीसदी बढ़ गई। एचएफसीएल के शेयरों में 215 फीसदी की तेजी आई। आदित्य इन्फोटेक, सनसेरा इंजीनियरिंग, एक्यूटास केमिकल्स, वेल्सपन कॉर्प और एमटीएआर टेक्नॉलजीज के शेयरों में 132 से 190 फीसदी तक की बढ़त देखी गई। ये सभी शेयर उन अमेरिकी कंपनियों द्वारा किए जा रहे भारी पूंजी निवेश से जुड़े हैं, जो एआई क्षमताओं को विकसित करने में बड़ी रकम लगा रही हैं। हालांकि, कुछ कंपनियां इससे अलग भी हैं; जैसे कि कंडोम बनाने वाली कंपनी क्यूपिड जिसके शेयरों में 595 फीसदी की तेजी आई, दवा बनाने वाली रुबिकॉन रिसर्च और इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली एथर एनर्जी। एक फंड मैनेजर ने कहा कि भले ही एआई ट्रेड के मामले में भारत शायद दूसरी दिशा में हो, लेकिन एआई से जुड़े पूंजी निवेश के मामले में यह बिल्कुल सही दिशा में है।

ये संबंध वास्तविक हैं। मार्च के बाद से स्टरलाइट टेक्नॉलजीज की ऑर्डर बुक 4.6 गुना बढ़कर 35,274 करोड़ रुपये हो गई है, जिसमें दिग्गज टेक कंपनियों से 1.2 अरब डॉलर मूल्य के सौदे शामिल हैं। एचएफसीएल के प्रबंधन ने बताया है कि उनकी 18,500 करोड़ रुपये की फाइबर और डेटा सेंटर ऑर्डर बुक का एक बड़ा हिस्सा हाइपरस्केलर कंपनियों से आता है।

लेकिन, जहां ये संबंध तेजी वाले बाजारों में बहुत फायदेमंद होते हैं, वहीं बाजार का रुख बदलने पर ये उलटा असर भी डालते हैं। पिछले एक महीने में अल्फाबेट (-17%), ब्लूम एनर्जी (26%) और मेटा (-15%) जैसी कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई है, जिसका असर भारत के एआई से जुड़े कारोबार पर भी पड़ा है। पिछले एक महीने में फिलाडेल्फिया चिप इंडेक्स 17% और नैस्डैक 100 इंडेक्स 7% नीचे आ गया है।

विश्लेषक अब इन कंपनियों की वृद्धि संभावनाओं को लेकर संशय में हैं। एचएफसीएल, सनसेरा इंजीनियरिंग, वेल्सपन कॉर्प और एक्यूटास केमिकल्स में म्यूचुअल फंडों की हिस्सेदारी घटी है। दूसरी ओर, स्टरलाइट टेक्नॉलजीज, क्यूपिड, आदित्य इन्फोटेक, एमटीएआर टेक्नॉलजीज और एथर एनर्जी में एक साल पहले की तुलना में सितंबर 2026 तिमाही में म्यूचुअल फंडों की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी देखी गई है।

बाजार के प्रतिभागियों ने हालिया तेजी के आधार पर आगे के लिए बहुत उम्मीदें न लगाने की सलाह दी है, इसलिए कि स्मॉलकैप सेगमेंट के कुछ हिस्सों में मूल्यांकन काफी ऊंचे पहुंच गए हैं। दौलत कैपिटल के ग्रुप सीईओ और इंस्टिट्यूशनल इक्विटीज के प्रमुख अमित खुराना ने कहा, हालांकि इस साल स्मॉलकैप शेयरों ने अच्छा प्रदर्शन किया है जिसकी मुख्य वजह अन्य सेगमेंट की तुलना में इनका बेहतर वृद्धि प्रोफाइल और नए व्यवसायों का सामने आना है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में इनमें बड़ी गिरावट भी देखने को मिली है।

उन्होंने कहा कि कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी इस सेगमेंट के लिए बड़ी चुनौती है और लगातार बढ़ते लागत दबाव के कारण वित्त वर्ष 28 में इनके मल्टीपल्स में गिरावट आ सकती है। उन्होंने निवेशकों को सलाह दी कि वे सोच-समझकर निवेश करें और कंपनियों के पिछले शेयर कीमत प्रदर्शन के बजाय उनकी वृद्धि की निरंतरता पर ध्यान दें।

अक्टूबर में मुख्य प्लेटफॉर्म के आईपीओ ने जुटाए 44,451 करोड़ रुपये

शिल्पा रंगराजन
मुंबई, 1 नवंबर



अक्टूबर में मुख्य प्लेटफॉर्म पर आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिये 44,451 करोड़ रुपये जुटाए गए। इसमें अकेले जियो प्लेटफॉर्म्स के इश्यू का हिस्सा कुल रकम का लगभग दो-तिहाई था। एक साल पहले की इसी अवधि में 10 इश्यू आए थे तो इस बार 13 आए। लेकिन सितंबर के 34 इश्यू के मुकाबले यह संख्या काफी कम है। प्राइम डेटाबेस के आंकड़ों के अनुसार यह रकम सितंबर के 39,381 करोड़ रुपये से 12.9 फीसदी अधिक थी, लेकिन अक्टूबर 2025 में जुटाई गई 45,188 करोड़ रुपये की रकम से 1.6 फीसदी कम रही।

34,801 करोड़ रुपये की नई पूंजी सितंबर के मुकाबले 233 फीसदी और एक साल पहले की तुलना में 257 फीसदी अधिक रही। ऑफर फॉर सेल से प्राप्त राशि 9,650 करोड़ रुपये रही। इसमें क्रमशः 67 फीसदी और 73 फीसदी की गिरावट आई। 2026 में अब तक मुख्य प्लेटफॉर्म पर 109 इश्यू के जरिये 1.58 लाख करोड़ रुपये जुटाए गए हैं, जबकि पूरे 2025 में 1.76 लाख करोड़ रुपये जुटाए गए थे। एसएमई के इश्यू की संख्या 193 रही, जिनसे 8,629 करोड़ रुपये जुटाए गए।

आंकड़ों के अनुसार जियो की एंकर बुक 8,110 करोड़ रुपये की रही, जो इसके 30,188 करोड़ रुपये के इश्यू का लगभग 27 फीसदी है। इसमें विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का हिस्सा 3,920 करोड़ रुपये और म्यूचुअल फंडों का 2,785 करोड़ रुपये रहा। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) लगभग 500 करोड़ रुपये के निवेश के साथ सबसे बड़ा अकेला एंकर निवेशक रहा।

इस महीने सूचीबद्ध आठ मुख्य प्लेटफॉर्म के इश्यू में से छह अपनी इश्यू प्राइस से ऊपर बंद हुए। टोनबो इमेजिंग में 62 फीसदी की बढ़त रही। इसके बाद जियो (26.7 फीसदी) और एचडी फायर प्रोटेक्ट (13.4 फीसदी) का नंबर रहा। जेटवर्क मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेज में 8.4 फीसदी की गिरावट आई।

वेल्थमिल्स सिक्योरिटीज के इक्विटी रणनीतिकार क्रांति बाथिनी ने कहा, व्यापक बाजार में सुस्ती, भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के बावजूद भारतीय प्राथमिक बाजार काफी मजबूत बना हुआ है। लंबे इंतजार के बाद एनएसई और जियो जैसे बड़े आईपीओ के बाजार में आने, डिजिटल क्रांति और पिछले 2-3 वर्षों में पूंजी बाजार से जुड़े खुदरा निवेशकों की बड़ी संख्या ने आईपीओ बाजार को मजबूती दी है। इसके साथ ही, इन आईपीओ में म्यूचुअल फंडों का भारी निवेश भी मददगार साबित हुआ है।

29 अक्टूबर तक की समायोजित बाजार कीमत के आधार पर टोनबो अपने निर्गम कीमत से 73.4 फीसदी ऊपर और जियो 27.2 फीसदी ऊपर ट्रेड कर रहा था। बाकी पांच इश्यू ईएएए इंडिया ऑल्टरनेटिव्स, जो ऐडलवाइस की ऑल्टरनेटिव ऐसेट मैनेजमेंट फर्म है), बीएलएस पॉलिमर्स, एसएफसी एनवायरनमेंटल टेक, एमके संस फाइन ज्वेल्स और बॉम्बे कोटेड ऐंड स्पेशल स्टील्स 26 से 29 अक्टूबर के बीच खुले थे। अभी इनकी सूचीबद्धता होनी है। निचले कीमत दायरे के हिसाब से इन सभी ने कुल 2,525 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा था। इन्वेस्टरगेन डॉट कॉम के अनुसार ईएएए सोमवार को सूचीबद्ध होगी और इसके शेयर का ग्रे मार्केट प्रीमियम 3.9 फीसदी था।.

एसएमई क्षेत्र में 13 इश्यू आए। इनसे 643 करोड़ रु. जुटाए गए। यह सितंबर के 2,125 करोड़ रु., जब बाजार में 52 इश्यू आए थे, से 69.7 फीसदी कम है। यह अक्टूबर 2025 में 6 इश्यू के जरिये जुटाए गए 208 करोड़ रुपये से लगभग तीन गुना है। इसमें रविता इंजीनियरिंग सर्विसेज का 110 करोड़ रुपये का ऑफर सबसे बड़ा था।

सूचीबद्ध हुए चार एसएमई इश्यू में से केवल एक रविता इश्यू प्राइस से ऊपर (1.5 फीसदी) बंद हुआ। आरके फैशन एक्सेसरीज में 7.3 फीसदी और शेल्ज इंडिया में 5 फीसदी की गिरावट आई। नौ एसएमई इश्यू को अभी सूचीबद्ध होना है। बाथिनी ने कहा, आगे चलकर मिडकैप और स्मॉलकैप आईपीओ ज्यादा आ सकते हैं। जहां तक वित्त वर्ष 27 की बात है तो सभी लार्जकैप आईपीओ पहले ही सूचीबद्ध हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्राथमिक बाजार में सुस्ती की संभावना आईपीओ लाने वाली कंपनियों के खास बिजनेस मॉडल पर निर्भर करती है।

सवाल जवाब

कुछ क्षेत्रों में सिमटी है आय वृद्धि, शेयर विशेष पर दांव की सलाह

मोतीलाल ओसवाल ऐसेट मैनेजमेंट कंपनी (एएमसी) में इक्विटी प्रमुख अजय खंडेलवाल का कहना है कि मौजूदा स्तरों से एक और बड़ी गिरावट की गुंजाइश कम ही लगती है। लेकिन निकट भविष्य में उतार-चढ़ाव से इनकार नहीं किया जा सकता। अभिषेक कुमार को दिए ईमेल इंटरव्यू में खंडेलवाल ने बताया कि उनका फोकस उन स्ट्रक्चरल थीम पर है, जहां कमाई में मजबूत और स्पष्ट वृद्धि दिख रही है। बातचीत के मुख्य अंशः



पश्चिम एशिया में तनाव कम होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं और कच्चे तेल की कीमतें भी ऊंची बनी हुई हैं। ऐसे में, क्या भारतीय शेयर बाजारों ने इन जोखिमों को पहले ही शामिल कर लिया है या अभी और गिरावट की गुंजाइश है?

भारतीय शेयर बाजारों में पिछले लगभग दो वर्षों से समय और कीमत के स्तर पर गिरावट देखने को मिला है। इस दौरान इनका प्रदर्शन वैश्विक बाजारों के मुकाबले कमजोर रहा है। भू-राजनीतिक तनाव, खासकर पश्चिम एशिया का संघर्ष और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों ने पिछले छह महीनों में बाजार की धारणा पर और दबाव डाला है।

कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची रहीं तो कॉरपोरेट मार्जिन पर दबाव पड़ सकता है, खासकर उन उद्योगों में, जो तेल की कीमतों के प्रति संवेदनशील हैं। हालांकि, 2026-27 की पहली छमाही में ऊंची कीमतों और आपूर्ति में रुकावटों का असर काफी हद तक सीमित रहा। इस बीच, मूल्यांकन 2024 के अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गए हैं और अब अपने दीर्घकालिक औसत से भी कम हैं जबकि कमाई मजबूत बनी हुई है। निकट भविष्य में उतार-चढ़ाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन मौजूदा स्तरों से किसी बड़े गिरावट की गुंजाइश कम ही लगती है, जब तक कि कोई और प्रतिकूल घटना न हो या कमाई में भारी गिरावट न आ जाए।

ऐसे कौन से मुख्य संकेतक हैं जिन पर नज़र रखनी चाहिए और जो भारतीय शेयर पर दबाव बढ़ा सकते हैं या बाज़ार की दिशा बदल सकते हैं?

इन मुख्य संकेतकों में भू-राजनीतिक घटनाक्रम और कच्चे तेल की कीमतें शामिल हैं, जो महंगाई, कॉरपोरेट मार्जिन और मुद्रा पर असर डाल सकती हैं। बाजार की नकदी के लिए वैश्विक ब्याज दरें और विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेश की आवक महत्त्वपूर्ण रहेगी जबकि आईपीओ की एक मज़बूत संख्या प्राथमिक बाजार में आपूर्ति बढ़ा सकती है।

वैश्विक स्तर पर आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) से जुड़े निवेश के रुझान में कोई भी बदलाव पूंजी का रुख भारत सहित उभरते बाजारों की ओर मोड़ सकता है। घरेलू स्तर पर, ग्रामीण मांग पर अल नीनो का असर और खपत में सुधार का टिकाऊपन कंपनियों की कमाई के लिए बहुत अहम होंगे। इस महीने के अमेरिकी मध्यावधि चुनाव भी व्यापार नीति, बॉन्ड यील्ड और वैश्विक स्तर पर जोखिम की इच्छा को प्रभावित कर सकते हैं।

इन व्यापक आर्थिक चुनौतियों के बीच कौन से सेक्टर सुरक्षित लगते हैं और किनको लेकर आप सतर्क हैं?

हमारा ध्यान उन संरचनात्मक थीम पर है, जहां कमाई में मजबूत और स्पष्ट वृद्धि दिख रही है। रक्षा सहित विनिर्माण क्षेत्र को पूंजीगत व्यय, स्वदेशीकरण और बढ़ती ऑर्डर बुक का समर्थन मिल रहा है जबकि दवा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र घरेलू और वैश्विक स्तर पर वृद्धि के टिकाऊ अवसर प्रदान करते हैं।

पूंजी बाजार और नई तकनीक, जिसमें एआई आधारित बिजनेस मॉडल भी शामिल हैं, को बचत के वित्तीयकरण और डिजिटल अपनाने से फायदा मिल रहा है। प्रीमियम उत्पादों और लोगों की बढ़ती आकांक्षाओं से कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्रों को समर्थन मिल रहा है। हम रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं, ग्रामीण क्षेत्रों और कमोडिटी से जुड़े क्षेत्रों को लेकर सतर्क हैं। हमारा पूरा जोर सही शेयर के चयन पर है।

अनिश्चित माहौल के बावजूद स्मॉल और मिडकैप शेयरों ने लार्जकैप शेयरों से बेहतर प्रदर्शन किया है। क्या यह रुझान आगे भी रहेगा?

स्मॉल और मिडकैप शेयरों ने कमाई में बेहतर वृद्धि के दम पर लार्जकैप शेयरों को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि, यह रुझान आगे भी कायम या नहीं, यह इस पर निर्भर करेगा कि कमाई में वृद्धि, बाजार की उम्मीदों और मूल्यांकन के मुकाबले कैसी रहती है।

स्मॉल और मिडकैप शेयरों के मूल्यांकन में 2024 के उच्चतम स्तरों से सुधार आया है और अब ये अपने दीर्घकालिक औसत के करीब आ गए हैं। लेकिन स्मॉलकैप शेयर अभी भी अपने ऐतिहासिक औसत की तुलना में प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं, जिसका एक कारण उनकी मजबूत आय वृद्धि है। ऐसे में शेयरों का चुनाव बहुत महत्त्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आय वृद्धि पर यह प्रीमियम कुछ चुनिंदा सेक्टरों और कंपनियों तक ही सीमित है।

वर्तमान में मूल्यांकन किस स्तर पर हैं और आय वृद्धि की संभावना तथा मूल्यांकन के लिहाज से कौन सा एमकैप सेगमेंट सबसे बेहतर स्थिति में है?

बाजार में जारी गिरावट के बीच 2024 में अपने उच्चतम स्तरों की तुलना में सभी एमकैप सेगमेंट के मूल्यांकन में कमी आई है। लार्ज, मिड और स्मॉलकैप के मूल्यांकन अपने उच्चतम स्तरों से क्रमशः 32 फीसदी, 36 फीसदी और 10 फीसदी गिरे हैं। फिलहाल ये तीनों सेगमेंट क्रमशः 17, 23.2 और 21.3 के पीई मल्टीपल पर ट्रेड कर रहे हैं।

लार्जकैप और मिडकैप शेयर अपने लंबे समय के औसत की तुलना में क्रमशः 19 फीसदी और 6 फीसदी के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे हैं, जबकि स्मॉलकैप शेयर 15 फीसदी के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। मूल्यांकन के नजरिये से मिड और स्मॉल कैप शेयरों की तुलना में लार्जकैप शेयर ज्यादा आकर्षक लग रहे हैं। मिडकैप और स्मॉलकैप सेगमेंट में मूल्यांकन प्रीमियम, उनकी कमाई में होने वाली अपेक्षाकृत मजबूत वृद्धि को दर्शाता है।

दूसरी तिमाही की आय का सीजन चल रहा है। अब तक घोषित नतीजों के बारे में आपका क्या आकलन है और क्या पश्चिम एशिया संघर्ष का असर कंपनियों के प्रदर्शन पर पड़ने लग गया है?

दूसरी तिमाही के अब तक आए नतीजे बताते हैं कि दो साल तक लगभग स्थिर रहने के बाद कंपनियों की कमाई में व्यापक सुधार देखने को मिल रहा है। राजस्व, एबिटा और मुनाफे, सभी मोर्चों पर अच्छी वृद्धि दिखी है और कई कंपनियों के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं। यह सुस्ती के एक लंबे दौर के बाद कमाई के माहौल में आए सुधार का संकेत है। अब तक, पश्चिम एशिया संघर्ष का कंपनियों के प्रदर्शन पर असर सीमित रहा है और यह अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग दिखा है। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के बीच, प्रबंधन कच्चे माल की लागत पर नजर रख रहा है। दूसरी ओर, कमाई की गति बनी हुई है और मांग के रुझान भी मजबूत हैं। घरेलू वृद्धि से जुड़े क्षेत्रों के लिए कमाई का भविष्य, मांग की मौजूदा स्थितियों और अन्य संबंधित कारकों पर निर्भर करेगा।

ROYAL SUNDARAM INSURANCE
Sundaram Finance Group

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2026

REVENUE ACCOUNT

(FORM NL-1-B-RA) (₹ in lakhs)

S. No	Particulars	For the half year ended September 30, 2026				For the half year ended September 30, 2025			
		Fire	Marine	Misc	Total	Fire	Marine	Misc	Total
1	Premiums earned (net)	3,134	3,486	1,93,166	1,99,786	3,629	2,808	1,64,365	1,70,802
2	Profit / (loss) on sale / redemption of investments	215	112	11,273	11,600	167	61	8,228	8,456
3	Interest, dividend & rent – gross	1,239	284	28,667	30,190	1,197	193	26,305	27,695
4	Other								
	(a) Other income								
	(i) Transfer fee and duplicate certificate fee	-	-	13	13	-	-	13	13
	(ii) Miscellaneous Income	3	1	132	136	1	-	37	38
	(b) Contribution from the shareholders' account								
	(i) Towards excess expenses of management	-	-	-	-	-	-	-	-
	(ii) Towards remuneration of MD/CEO/WTD/Other KMPs	7	2	72	81	2	-	15	17
	TOTAL (A)	**4,598**	**3,885**	**2,33,323**	**2,41,806**	**4,996**	**3,062**	**1,98,963**	**2,07,021**
5	Claims incurred (net)	2,842	3,175	1,66,569	1,72,586	3,002	3,543	1,31,154	1,37,699
6	Commission	223	1,098	47,642	48,963	1,614	912	39,639	42,165
7	Operating expenses related to insurance business	1,865	514	21,343	23,722	1,951	443	18,529	20,923
8	Premium deficiency	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL (B)	**4,930**	**4,787**	**2,35,554**	**2,45,271**	**6,567**	**4,898**	**1,89,322**	**2,00,787**
9	Operating profit / (loss) C= (A - B)	(332)	(902)	(2,231)	(3,465)	(1,571)	(1,836)	9,641	6,234
10	APPROPRIATIONS								
	Transfer to shareholders' account	(332)	(902)	(2,231)	(3,465)	(1,571)	(1,836)	9,641	6,234
	Transfer to catastrophe reserve	-	-	-	-	-	-	-	-
	Transfer to other reserves	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL (C)	**(332)**	**(902)**	**(2,231)**	**(3,465)**	**(1,571)**	**(1,836)**	**9,641**	**6,234**

PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(FORM NL-2-B-PL) (₹ in lakhs)

S. No	Particulars	For the half year ended September 30, 2026	For the half year ended September 30, 2025
1	Operating profit/(loss)		
	(a) Fire insurance	(332)	(1,571)
	(b) Marine insurance	(902)	(1,836)
	(c) Miscellaneous insurance	(2,231)	9,641
2	Income from investments		
	(a) Interest, dividend & rent – gross	6,286	6,263
	(b) Profit on sale of investments	2,553	2,019
	(c) Loss on sale/ redemption of investments	(76)	(56)
	(d) Amortization of premium / discount on investments	(26)	(29)
3	Other income		
	a) Profit/(loss) on sale of assets	(1)	2
	b) Other income	157	12
	TOTAL (A)	**5,428**	**14,445**
4	Provisions (other than taxation)		
	(a) For diminution in the value of investments	-	-
	(b) For doubtful debts	-	-
	(c) Others	-	-
5	Other expenses		
	(a) Expenses other than those related to insurance business	5	253
	(b) Bad debts written off	-	-
	(c) Interest on subordinated debt	491	501
	(d) Expenses towards CSR activities	180	173
	(e) Penalties	-	-
	(f) Contribution to policyholders' a/c		
	(I) Towards excess expenses of management		
	(ii) Others (please specify)	-	-
	(iii) Towards Towards remuneration of MD/CEO/WTD/Other KMPs"	81	17
	(g) Others		
	(i) Expenses of investment	59	57
	(ii) Interest on Income Tax	269	-
	TOTAL (B)	**1,085**	**1,001**
6	Profit/(loss) before tax	4,343	13,444
7	Provision for taxation	(1,195)	(3,418)
8	Profit / (loss) after tax	3,148	10,026
9	APPROPRIATIONS		
	(a) Interim dividend paid during the period	-	1,347
	(b) Final dividend paid	1,123	-
	(c) Transfer to any Reserves or Other Accounts : Capitalisation of reserves towards issue of bonus shares	88,800	-
	Balance of profit / (loss) brought forward from last year	1,11,095	1,01,210
	Balance carried forward to balance Sheet	**24,320**	**1,09,889**

BALANCE SHEET

(FORM NL-3-B-BS) (₹ in lakhs)

S. No	Particulars	As at September 30, 2026	As at September 30, 2025
1	**Sources of funds**		
	Share capital	1,34,700	44,900
	Share application money pending allotment	-	-
	Reserves and surplus	51,080	1,37,649
	Fair value change account		
	-Shareholders' funds	522	1,151
	-Policyholders' funds	3,399	6,201
	Borrowings	5,000	12,600
	Total	**1,94,701**	**2,02,501**
2	**Application of funds**		
	Investments-shareholders	1,38,349	1,45,504
	Investments-policyholders	8,99,985	7,83,964
	Loans	-	-
	Fixed assets	9,653	8,473
	Deferred tax asset (Net)	3,622	1,837
	Current assets		
	-Cash and bank balances	4,010	4,487
	-Advances and other assets	1,32,609	1,30,807
	Sub-total (A)	**1,36,619**	**1,35,294**
	Deferred tax liability		
	Current liabilities	7,66,441	6,98,735
	Provisions	2,27,086	1,73,836
	Sub-total (B)	**9,93,527**	**8,72,571**
	Net current assets (C) = (A - B)	**(8,56,908)**	**(7,37,277)**
	Miscellaneous expenditure (to the extent not written off or adjusted)	-	-
	Debit balance in profit and loss account	**-**	**-**
	Total	**1,94,701**	**2,02,501**

DISCLOSURE AS PER REGULATION 52(8) READ WITH REGULATION 52(4) OF THE SEBI (LODR), 2016
EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED SEPTEMBER 30, 2026

(₹ in lakhs)

S No.	Particulars	Quarter ended		Year ended
		September 30, 2026	September 30, 2025	March 31, 2026
		Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from operations*	1,36,976	1,06,236	4,63,831
2	Net profit / (loss) for the period (before Tax, exceptional and / or extraordinary items)	656	1,460	18,409
3	Net profit / (loss) for the period before tax (after exceptional and / or extraordinary items)	656	1,460	18,409
4	Net profit / (loss) for the period after tax (after exceptional and / or extraordinary items)	463	1,069	13,701
5	Total comprehensive income for the period [comprising profit / (loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)] **	NA	NA	NA
6	Paid up equity share capital	1,34,700	44,900	44,900
7	Reserves (excluding revaluation reserve)	25,580	1,12,149	1,13,353
8	Securities premium account	25,500	25,500	25,500
9	Net worth	1,85,780	1,82,549	1,83,753
10	Outstanding redeemable preference share	-	-	-
11	Paid up debt capital/outstanding debt	5,000	12,600	12,600
12	Capital redemption reserve	-	-	-
13	Debenture redemption reserve	500	1,260	1,260
14	Earnings Per Share (of ₹10/-each) (for continuing and discontinued operations) 6			
	I. Basic: (not annualized) ₹	0.03	0.08	1.02
	II. Diluted: (not annualized) ₹	0.03	0.08	1.02
15	Debt-equity ratio (No. of times)	0.03	0.07	0.07
16	Debt service coverage ratio (No. of times)	3.71	6.79	19.43
17	Interest service coverage ratio (No. of times)	3.71	6.79	19.43

* Total Income from operations includes gross direct premium, inward reinsurance and excludes applicable taxes. ** IRDAI has notified Ind AS as the applicable financial reporting framework with effect from April 1, 2026. The Company has received a one-year forbearance from IRDAI, enabling it to continue preparing its financial statements until March 31, 2027, under the existing accounting framework.

Notes: (1).The above is an extract of the detailed format of quarterly / annual financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with IRDA Circular Reference No. IRDA/F&A/CIR/LFTD/027/01/2017 dated 30th January 2017, including amendments thereof. (2). The full format of the Quarterly /Annual financial results are available on the website of the Stock Exchange (www.nseindia.com) and the Company (www.royalsundaram.in). (3). The above financial results have been reviewed by Joint Statutory Auditors of the Company and recommended by the Audit committee and subsequently approved by the Board of Directors at their meetings held on October 30, 2026. (4). Pursuant to the Judgment delivered by the Hon'ble Supreme Court of India on June 11, 2026, recognizing the economic value of unpaid domestic work performed by homemakers for the purpose of determining compensation under the Motor Vehicles Act, the Company has assessed the potential Impact of the ruling on its Motor Third-Party (TP) portfolio. The Company has on a prudent and conservative basis recognized claim reserves amounting to ₹ 6,610 lakhs for the six month period ended September 30, 2026 which includes claim reserves amounting to ₹ 3,145 lakhs pertaining to previous quarter ended June 30, 2026. The Joint Statutory Auditors have placed reliance on the estimates arrived by the Appointed Actuary of the Company. (5). During the period, the Company exercised the call option and redeemed the subordinated debenture issued on September 27, 2021 (ISIN INE499S08039) amounting to ₹7,600 Lakhs in full including interest. (6). The Company has allotted 89,80,00,000 fully paid-up bonus equity shares of ₹10 each in the ratio of Two bonus equity shares for every One existing equity share held by the shareholders as on the record date August 24, 2026 by capitalizing reserves for an amount of ₹ 89,800 Lakhs as approved by the shareholders at the Annual General Meeting held on 29 July 2026. Consequently, the basic and diluted earnings per share (EPS) for the comparative periods have been restated in accordance with AS 20 - Earnings per Share, as if the bonus issue had been in effect for all the periods presented. EPS is not annualised for the quarter ended September 30, 2026, and September 30, 2025.

The quarterly results are available on the Company's website at www.royalsundaram.in The same could be accessed by scanning the QR code herein.

For and on behalf of the Board
Vedanarayanan Seshadri
Managing Director
DIN:08864477

Place: Chennai
Date: October 30, 2026

Disclosure

1. This public disclosure is made in accordance with the disclosure framework prescribed by Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) vide circular No. IRDAI/F&A/CIR/MISC/256/09/2021 dated September 30, 2021.
2. The above financial results have been reviewed by Joint Statutory Auditors of the Company and recommended by the Audit committee and subsequently approved by the Board of Directors at their meetings held on October 30, 2026.
3. Previous period figures have been regrouped/reclassified wherever necessary .
4. Due date for payment of interest on non-convertible debentures is March 15, 2027.

Place: Chennai
Date: October 30, 2026

ANALYTICAL RATIOS FOR NON-LIFE COMPANIES

(FORM NL-20)

S. No	Particulars	For the half year ended September 30, 2026	For the half year ended September 30, 2025
1	Gross direct premium growth rate	19.3%	14.1%
2	Gross direct premium to net worth ratio (No. of times)	1.41	1.20
3	Growth rate of net worth	1.8%	5.0%
4	Net retention ratio	84.6%	73.0%
5	Net commission ratio	21.1%	24.6%
6	Expense of management to gross direct premium ratio	29.7%	31.3%
7	Expense of management to net written premium ratio	31.3%	36.9%
8	Net incurred claims to net earned premium	86.4%	80.6%
9	Claims paid to claims provisions	17.8%	13.8%
10	Combined ratio	117.6%	117.5%
11	Investment income ratio	4.9%	4.7%
12	Technical reserves to net premium ratio (No. of times)	3.84	4.60
13	underwriting balance ratio (No. of times)	-0.23	-0.18
14	Operating profit ratio	-1.7%	3.5%
15	Liquid assets to liabilities ratio (No. of times)	0.33	0.19
16	Net earning ratio	1.4%	5.8%
17	Return on net worth ratio	1.7%	5.5%
18	Available solvency margin to required solvency margin ratio (No. of times)	1.89	2.18
19	NPA ratio		
	- Gross NPA ratio	0.05%	0.03%
	- Net NPA ratio	0.01%	0.01%
20	Debt equity ratio (No. of times)	0.03	0.07
21	Debt service coverage ratio (No. of times)	9.85	27.83
22	Interest service coverage ratio (No. of times)	9.85	27.83
23	Earnings per share - (in ₹)	0.23	0.74
24	Book value per share - (in ₹)	13.79	13.55

For and on behalf of the Board
Vedanarayanan Seshadri
Managing Director
DIN:08864477

We Insure

Motor | Travel | Health | Home | Accident | Marine | Establishment | Industry | Rural

Reach us

Call:
1860 258 0000
1860 425 0000

Email:
care@royalsundaram.in

Log on to:
www.royalsundaram.in

Visit:
any of our 139 offices

Follow us on:
Facebook / X / Instagram

Scan this to secure your health and wealth with Royal Sundaram.

‘वोट चोरी’ पर दिल्ली में चढ़ा सियासी पारा

रविवार को ‘इंडिया’ गठबंधन के नेताओं ने रामलीला मैदान में एकजुटता दिखाई

अर्चिस मोहन

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तापमान भले ही नीचे सरक गया है मगर सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। कथित ‘वोट चोरी’ के मुद्दे पर रविवार को दिल्ली के ही रामलीला मैदान में विपक्षी दलों ने एक बड़ी रैली आयोजित की। माना जा रहा है कि हाल के वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी में विपक्ष द्वारा आयोजित यह सबसे बड़ी रैलियों में एक थी। रविवार को कांग्रेस के नेतृत्व वाले ‘इंडिया’ गठबंधन के नेताओं ने एकजुटता दिखाने की पुरजोर कोशिश की। उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे मतदाता पत्रों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के तहत ‘वोट चोरी’ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी दलों का आरोप है कि ‘वोट चोरी’ से देश का संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में हैं और लोगों के मताधिकार छीनने की साजिश के तहत इसे (‘वोट चोरी’) को अंजाम दिया जा रहा है।



‘इंडिया’ गठबंधन के नेताओं के साथ रामलीला मैदान पहुंचे राहुल गांधी

गत 11 अक्टूबर को केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली के जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शन के लिए निर्धारित जगहों की सूची से हटाने के बाद ‘इंडिया’ गठबंधन के सामने चुनौती केवल यह नहीं थी कि संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत तक ‘वोट चोरी’ के खिलाफ अपने विरोध प्रदर्शन की रफ्तार कैसे बनाई रखी जाए बल्कि रामलीला मैदान भरने के लिए पर्याप्त लोग जुटाना भी उनके लिए बड़ी परीक्षा थी। जंतर-मंतर पर 3,000 लोगों के इकट्ठा होने से ही वह जगह पूरी तरह भर जाती है जबकि रामलीला मैदान भरने के लिए 50,000 लोगों की जरूरत होती है।

इस आयोजन में ‘इंडिया’ गठबंधन के नेताओं की गाड़ियां कनॉट प्लेस के पास मिंटो रोड से रामलीला मैदान की ओर बढ़ीं। उनके साथ हजारों समर्थक भी चल रहे थे। विरोध स्थल तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में उन्हें दो घंटे से अधिक का समय लग गया। अगर 12 अक्टूबर को कनॉट प्लेस से उच्चतम न्यायालय तक ‘इंडिया’ गठबंधन का मार्च एक प्रयोग था तो रविवार की रैली का मुजाहिरा उन्होंने अपनी ताकत सरकार को दिखाने के लिए किया।

रविवार को राजनीतिक गलियारों में इसी बात पर चर्चा गर्म रही कि रैली में कितने लोग आए (या कितने नहीं आए) और क्या ‘इंडिया’ गठबंधन वास्तव में एकजुट है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता संबित पात्र ने दावा किया कि कांग्रेस नेतृत्व ने 10 लाख लोगों के शामिल होने की बात कही थी मगर असल में बहुत कम लोग ही पहुंचे। भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का हिस्सा जनता दल (यूनाइटेड) ने कहा कि ‘इंडिया’ गठबंधन के दल रैलियों और बैठकों के लिए तो एक साथ आ जाते हैं मगर चुनाव एक-दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। जदयू (यू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि नेतृत्व साझा एजेंडे और मुद्दों पर आम सहमति के बिना किसी गठबंधन के बने रहने का कोई औचित्य नहीं है।

‘इंडिया’ गठबंधन की रैली के जवाब में भाजपा ने ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ मार्च निकाला। हरियाणा के रोहतक में भाजपा के राष्ट्रीय नेता नितिन नवीन ने ऐसे ही एक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। नवीन ने लोक सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वे विदेशी ताकतों के इशारे पर देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। भाजपा नेता ने कहा कि वर्ष 1984 के सिख-विरोधी दंगों के लिए प्रायश्चित करने और माफी मांगने के बजाय कांग्रेस दिल्ली में हुई उन हत्याओं की बरसी पर विरोध प्रदर्शन करने निकल पड़ी है। उन्होंने कहा, ‘मोदी जी कहीं नहीं जाएंगे, 2029 में वह फिर से लाल किले के प्राचीर से दिखाई देंगे।’ विपक्ष के इस आरोप पर कि मतदाता सूची से 13 करोड़ मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं, नवीन ने कहा कि इनमें 2.5 करोड़ लोग ऐसे थे जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, 6 करोड़ लोग एक जगह से दूसरी जगह चले गए थे और 3 करोड़ ‘घुसपैठिए’ थे। हालांकि, पिछले सप्ताह छपी ‘हिंदुस्तान टाइम्स’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन छह राज्यों में मतदाता सूची का सत्यापन किया गया वहां लगभग 1,600 लोगों की पहचान विदेशी नागरिकों के रूप में हुई। सत्ताधारी भाजपा ने असम के मोरीगांव और हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी रैलियां निकालीं। विपक्षी दलों द्वारा लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में फैलाए जा रहे कथित ‘गुमराह करने वाले प्रचार’ का मुकाबला करने के लिए भाजपा ने देशव्यापी अभियान चलाया है। इसी अभियान के समापन के तौर पर 5 नवंबर को नागपुर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ मार्च का नेतृत्व करेंगे।

‘इंडिया’ गठबंधन की रैली में कांग्रेस, वामपंथी दलों और समाजवादी पार्टी की ओर से भारी भीड़ जुटी। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने इस रैली के प्रति अपना समर्थन तो जताया मगर इसके नेता रैली में शामिल नहीं हुए। सीजेपी की गैर-मौजूदगी से यह साफ हो गया कि विपक्षी गुट को अभी भी अपनी रैलियों में शहरी शिक्षित युवाओं और मध्यम वर्ग को जोड़ने में संघर्ष करना पड़ रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन की नेता नेहा बोरा समेत कई वक्ताओं ने दावा किया कि युवा मतदाताओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। वहीं, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इकलौती ऐसी नेता रहीं जिन्होंने सीजेपी का नाम लिया और इसके नेतृत्व को बधाई दी। बनर्जी ने शनिवार शाम राष्ट्रीय राजधानी में सीजेपी नेता अभिजित दीपके से मुलाकात की। गांधी ने कहा कि 13 करोड़ से अधिक वोट हटा दिए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष और वर्ष 2024 का चुनाव जीतने वालों के बीच का अंतर केवल 3 प्रतिशत था यानी इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग स्वयं यह मान रहा है कि वर्ष 2024 का लोक सभा चुनाव ‘अवैध’ था।

गांधी ने कहा, ‘आप इन मतदाताओं के वोट हटाकर यह दावा नहीं कर सकते कि वर्ष 2024 का चुनाव वैध था।’ उन्होंने रामलीला मैदान में दिए अपने भाषण में भी इन आरोपों को दोहराया। गांधी ने कहा कि भविष्य में सीईसी कुमार को उनके पद से हटाया जाएगा और ‘देशद्रोह’ के आरोप में जेल भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी ‘कानूनी कार्रवाई’ का सामना करना पड़ेगा और उन्हें कानून से बचने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, ‘देश को न्याय मिलेगा। वोट चोरी करने और देश को अदाणी को बेचने के लिए हम न्याय मांगेंगे।’ वहां जुटी भारी भीड़ का जिक्र करते हुए गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री शाह और सीईसी तक एक संदेश पहुंच गया है।

शीर्ष प्राथमिकता में तेजस: दीक्षित

भास्वर कुमार



एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित

भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के नए प्रमुख एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कहा कि स्वदेश में निर्मित तेजस मार्क-1ए (एमके 1ए) एवं एमके 2 लड़ाकू विमान और एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एएमसीए) वायु सेना की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। दीक्षित ने यह भी कहा कि भारतीय सेंसर और हथियार भी वायु सेना के लिए शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल हैं। भारतीय वायु सेना के 29वें प्रमुख का कार्यभार संभालने के एक दिन बाद दीक्षित ने रविवार को नई दिल्ली में ये बातें कहीं।

दीक्षित ने कहा, ‘हम भारतीय रक्षा साजो-सामान एवं उपकरणों के साथ किसी भी चुनौती का सामना करेंगे।’ उन्होंने कहा कि वायु सेना के पास ये प्रणालियां इतनी बड़ी संख्या में होंगी कि लंबे समय तक चलने वाले अभियानों की जरूरतें बिना किसी चुनौती के पूरी हो सकें। उन्होंने कहा कि वायु सेना की ताकत वापस उसके स्वीकृत स्तर तक पहुंचाना उनका ‘सबसे प्रमुख कार्य’ होगा।

उन्होंने कहा, ‘हमारी जिम्मेदारी लड़ना और जीतना है मगर सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य अपनी मजबूत वायु शक्ति के जरिये किसी भी बाहरी चुनौती को दूर रखना है।’

सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को फरवरी 2024 में 180 तेजस एमके 1 ए विमानों के पहले खेप की आपूर्ति करनी थी। मगर अमेरिकी निर्मित इंजनों की आपूर्ति में देरी के कारण अब तक एक भी विमान नहीं सौंपा गया है। फिलहाल भारतीय वायु सेना के पास 42 स्वीकृत स्क्वाड्रन (विमानों का दस्ता) के मुकाबले केवल 29 सक्रिय लड़ाकू स्क्वाड्रन हैं जो पिछले 60 वर्षों में सबसे कम संख्या है।

शनिवार को एयर चीफ मार्शल एपी सिंह (सेवानिवृत्त) का स्थान लेने वाले दीक्षित ने अपनी प्राथमिकताओं को एक शब्द ‘वायु’ के जरिये समझाया। अंग्रेजी में लिखे इस शब्द के हर अक्षर का एक खास अर्थ है यानी ‘वी’ से सतर्कता एवं तैयारी ‘ए’ से आत्मनिर्भरता, ‘वाई’ से युक्ति (नवाचार/सूझबूझ) और ‘यू’ से एकजुट प्रयास।

वायु सेना की तैयारी पर उन्होंने कहा, ‘हर स्क्वाड्रन, हर रडार, हर वायु रक्षा इकाई और वायु सेना के हर एक जवान को किसी भी पल कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए।’

दीक्षित ने ‘युक्ति’ के तहत सिद्धांत, कार्य प्रणाली और तकनीक में नवाचार शामिल किए हैं। इसमें तंत्र से जुड़े और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) पर आधारित आदेश एवं नियंत्रण कई स्तरों वाली ड्रोन-रोधी सुरक्षा, जरूरत के हिसाब से रखरखाव, सेना की सुरक्षा और मजबूती और भारतीय वायु सेना के लिए पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी हिस्से का एक संचालन क्षेत्र के रूप में इस्तेमाल शामिल होगा। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों की लगातार निगरानी की जाएगी और इनमें आगे कदम बढ़ाए जाएंगे। प्रयासों में एकजुटता पर दीक्षित ने कहा कि भारतीय वायु सेना थल सेना, नौसेना और राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर योजना बनाएगी और लड़ेगी। यह ‘जेएआई’ (संयुक्तता, आत्मनिर्भरता और नवाचार) के दृष्टिकोण के अनुरूप होगा। उन्होंने कहा, ‘जब शुरुआती योजना से ही सभी को एक साथ जोड़ लिया जाए तो वायु शक्ति सबसे बेहतर परिणाम देती है।’

पिछले कुछ महीनों में सशस्त्र बलों ने सरकार को एक प्रस्ताव और खाका भेजा है जिसका उद्देश्य उन्हें थिएटर कमांड में एकीकृत करना है। अब इसे सुरक्षा पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की समिति से मंजूरी का इंतजार है।

दीक्षित ने कहा कि सुरक्षा के मोर्चे पर चुनौतियां बनी हुई हैं। उन्होंने ड्रोन, लंबी दूरी के सटीक हथियार, अंतरिक्ष, साइबर, एआई और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जिक्र किया और कहा कि नई तकनीक युद्ध के स्वरूप को बदल रही हैं। उन्होंने कहा कि वायु सेना को स्वयं को इस तरह तैयार करना होगा कि वह अगले दशक में भारत की रक्षा जरूरत पूरी कर सके और साथ ही हमेशा लड़ने और जीतने के लिए तैयार रहे।

दूरसंचार कंपनियों ने की आईटीसी बढ़ाने की मांग

पृष्ठ 1 का शेष

दूरसंचार कंपनियों का कहना है कि नियामक की तत्काल हस्तक्षेप से अधिक समान व्यवस्था बनेगी। ट्राई ने अभी व्यापक टर्मिनेशन शुल्क व्यवस्था पर अपनी सिफारिशें जारी नहीं की हैं। उसने 2020 में आईटीसी शुल्क की समीक्षा करते हुए उसे 0.30 रुपये से बढ़ाकर 0.35 से 0.65 रुपये प्रति मिनट कर दिया था। मामले से अवगत लोगों ने बताया कि दूरसंचार कंपनियों ने हाल की बैठकों में भी यह मांग दोहराई है। पिछले कुछ महीनों के दौरान ट्राई को लिखित प्रस्ताव भी भेजे गए हैं। जून 2026 के एक पत्र में सीओएआई ने कहा था कि शुल्क बढ़ने से भारतीय दरें अंतरराष्ट्रीय मानकों के करीब आएंगी। इससे भारतीय दूरसंचार नेटवर्क के इस्तेमाल का उचित भुगतान भी मिलेगा। उद्योग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अपनी पहचान जाहिर न करने की शर्त पर कहा कि चीन, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया और वियतनाम ने पिछले पांच साल के दौरान अमेरिकी डॉलर में आईटीसी शुल्क को दो से तीन गुना बढ़ा दिया है।

सीओएआई ने अपने पत्र में कहा, ‘ट्राई अगले दो से तीन वर्षों में भारत के आईटीसी शुल्क को वैश्विक मानकों के अनुरूप लाने के लिए आगे की बढ़ोतरी का समयबद्ध कार्यक्रम भी तय कर सकता है।’ ट्राई को दिए गए प्रस्तावों के अनुसार निजी दूरसंचार कंपनियां और सरकारी कंपनी बीएसएनएल इस मांग पर एकमत हैं। सभी कंपनियां अधिकतम शुल्क को कम से कम 4 रुपये और बढ़ाकर 5 रुपये प्रति मिनट करने या वैश्विक स्तर के अनुरूप लाने की मांग कर रही हैं। कंपनियों ने कहा है कि आईटीसी शुल्क बढ़ने से भारतीय उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। विदेश से आने वाली कॉल प्राप्त करने वाले ग्राहक के लिए मुफ्त रहती हैं। इसका भुगतान विदेशी कॉल करने वाली कंपनी या उसके मध्यस्थ को करना होता है।

कंपनियों ने पहले भी कहा था कि कम आईटीसी शुल्क व्यवस्था के कारण बड़ी संख्या में फर्जी अंतरराष्ट्रीय कॉल भारतीय लोगों को निशाना बनाती हैं। इससे वित्तीय धोखाधड़ी का खतरा बढ़ता है और टेलीकॉम सेवाओं पर भरोसा कमजोर होता है। इसके अलावा भारतीय कंपनियों को राजस्व का नुकसान होता है। इससे सरकार की कमाई भी घटती है और दूसरे देशों के मुकाबले भारत को प्रतिस्पर्धा तथा आर्थिक मोर्चे पर नुकसान उठाना पड़ता है।

इस दीवाली घरेलू उड़ान कम

दीपक पटेल



भारतीय विमानन कंपनियां इस साल दीवाली के महीने में पिछले साल के त्योहारी महीने के मुकाबले हर सप्ताह 2.6 फीसदी कम घरेलू उड़ानों का संचालन करेंगी। हवाई किराया बढ़ने और यात्रियों की मांग में कमी के संकेत मिलने के कारण विमानन कंपनियां अपनी उड़ानों की संख्या घटा रही हैं।

विमानन कंपनियों ने नवंबर 2026 में हर सप्ताह 22,306 उड़ानें संचालित करने का कार्यक्रम बनाया है जबकि अक्टूबर 2025 में यह संख्या 22,912 थी। इस तरह हर सप्ताह 606 उड़ानों की कमी आई है। यह जानकारी विमानन आंकड़ों का विश्लेषण करने वाली कंपनी सिरियम के आंकड़ों से मिली है। उड़ानों की संख्या में यह कमी ईंधन की बढ़ती कीमतों और रुपये में नरमी के कारण आई है क्योंकि इनसे हवाई यात्रा महंगी हो गई है। विमानन कंपनियां अब यात्रियों की मांग के हिसाब से उड़ानों की संख्या में बदलाव कर रही हैं। एयर इंडिया ने सबसे ज्यादा कटौती की है। उसने पिछले साल अक्टूबर की 3,644 साप्ताहिक घरेलू उड़ानों की तुलना में इस नवंबर में 543 उड़ानें घटाकर 3,101 कर दी हैं। यह 14.9 फीसदी की कमी है। उसकी सहायक कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 78 उड़ानों की कटौती करते हुए कुल उड़ानों की संख्या को घटाकर 2,420 कर दी है। यह 3.1 फीसदी की कटौती है। स्पाइसजेट ने 37 उड़ानें यानी 5.2 फीसदी की कमी की है। अब उसकी साप्ताहिक उड़ानों की संख्या 679 है। देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो ने 375 उड़ानें घटाकर 13,697 कर दी हैं। यह 2.7 फीसदी की कमी है।

जिन मार्गों पर सबसे ज्यादा कटौती हुई है उनमें हैदराबाद-तिरुपति और दिल्ली-हैदराबाद शामिल हैं। इन दोनों मार्गों पर हर सप्ताह 86-86 उड़ानें कम हुई हैं। दिल्ली-लेह मार्ग पर 78 उड़ानें कम हुई हैं। इसके अलावा चेन्नई-मदुरै मार्ग पर 70, अहमदाबाद-गोवा मार्ग पर 68, हैदराबाद-चेन्नई मार्ग पर 58, दिल्ली-चेन्नई मार्ग पर 58, बेंगलूरु-गोवा मार्ग पर 48, हैदराबाद-पटना मार्ग पर 48 और जम्मू-श्रीनगर मार्ग पर 47 उड़ानें कम हुई हैं।

बिहार के हवाई अड्डों पर भी उड़ानों में कटौती हुई है। दीवाली के बाद छठ वहां का बड़ा त्योहार है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपने घर लौटते हैं। पटना हवाई अड्डे से इस नवंबर में हर सप्ताह 302 उड़ानें रवाना होंगी जबकि पिछले साल अक्टूबर में यह संख्या 377 थी। दरभंगा से साप्ताहिक उड़ानों की संख्या 67 से घटकर 55 रह गई है। यह करीब 18 फीसदी की कमी है। हैदराबाद-पटना मार्ग पर भी हर सप्ताह 48 उड़ानें कम हुई हैं। यहां उड़ानों की संख्या 90 से घटकर 42 रह गई है। इंडिगो के मुख्य कार्याधिकारी विली वॉल्श ने पिछले गुरुवार को कहा था कि दिसंबर तिमाही में कंपनी की उड़ानों की क्षमता में कटौती अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर होगी।

जयशंकर ने की यूक्रेन और पश्चिम एशिया पर चर्चा

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अमेरिका में रूस, पोलैंड और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रियों के साथ अलग-अलग बैठकें करके यूक्रेन संघर्ष, पश्चिम एशिया की स्थिति, द्विपक्षीय संबंधों और बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। ये बैठकें शनिवार को अटलांटा में जी-20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर हुईं। जयशंकर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ ‘यूक्रेन संघर्ष, खाड़ी क्षेत्र की स्थिति और बहुपक्षीय मुद्दों’ पर चर्चा की। **भाषा**



नाविक के साथ निजी अंतरिक्ष क्षमता पर ध्यान

शाइन जेकब

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने शुक्रवार रात श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने 2,250 किलोग्राम वजनी नेविगेशन उपग्रह एनवीएस-03 का सफल प्रक्षेपण किया। यह मिशन भारत की स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन (नाविक) के लिए एक नई शुरुआत है। यह प्रक्षेपण अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की बढ़ती भागीदारी को भी प्रदर्शित करता है।

इसरो के प्रमुख वी. नारायणन ने बताया कि प्रक्षेपण से संबंधित बजट का लगभग 80 फीसदी हिस्सा घरेलू निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को जाता है। इसमें 400 से 500 कंपनियों और स्टार्टअप का नेटवर्क शामिल है। दिलचस्प है कि एनवीएस-03 उपग्रह मिशन को लगातार दो जीएसएलवी मिशनों के बीच सबसे कम टर्नअराउंड समय यानी महज 56 दिनों में पूरा कर लिया गया है।

यह प्रक्षेपण काफी महत्त्वपूर्ण समय पर किया गया है क्योंकि नाविक संकट से जूझ रहा था। इसी साल मार्च में भारतीय रिजनल नेविगेशन सेटलाइट सिस्टम (आईआरएनएसएस)-1एफ की परमाणु घड़ी खराब हो गई थी जिससे नाविक का कामकाज लगभग ठप पर गया था। फिलहाल केवल आईआरएनएसएस-1बी, आईआरएनएसएस-1एल और एनवीएस-01 काम कर रहे हैं जबकि नाविक प्रणाली के ठीक से काम करने के लिए कम से कम चार ऐसे उपग्रहों की जरूरत है।



इन-स्पेस से 4 कंपनियों को मिलेंगे 67 करोड़ रुपये

इंडियन नैशनल स्पेस प्रमोशन ऐंड ऑथराइजेशन सेंटर (इन-स्पेस) ने अपने टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फंड (टीएएफ) के तहत वित्तीय सहायता के लिए महाराष्ट्र की मनस्तु स्पेस, आईमुंबई सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड और इंस्पेसिटी स्पेस लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड (मुंबईसेमी) तथा बेंगलूरु की एयरोडोम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (व्योमआईसी) का चयन किया है। इन कंपनियों को कुल 67.15 करोड़ रुपये की राशि मिलेगी जिसका उपयोग वे स्वदेशी तकनीक विकसित करने में करेंगी ताकि वे सैटेलाइट प्रोपल्शन, इन-ऑर्बिट सर्विसिंग, अंतरिक्ष और जमीनी उपयोग के लिए प्रिसिजन टाइमिंग सिस्टम और नाविक युक्त जीएनएसएस सिस्टम-ऑन-चिप (एसओसी) जैसी तकनीकें विकसित कर सकें।

इंडियन स्पेस एसोसिएशन (आईएसपीए) के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल (सेवा-निवृत्त) एके भट्ट ने कहा, 'भारत के अंतरिक्ष मिशनों में निजी क्षेत्र का महत्त्वपूर्ण योगदान देखना उत्साहजनक है। जैसा कि इसरो के चेयरमैन ने बताया है कि प्रक्षेपण यान के बजट का लगभग 80 फीसदी हिस्सा निजी क्षेत्र को जाता है जिससे हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी कंपनियों की बढ़ती भूमिका का पता चलता है। इसका और विस्तार होना चाहिए ताकि भारतीय कंपनियां उपग्रह विनिर्माण, नेविगेशन तकनीक, कलपुर्जे और डाउनस्ट्रीम ऐप्लिकेशन जैसे तमाम क्षेत्रों में अपना योगदान दे सकें।'

उन्होंने कहा, 'नवाचार को बढ़ावा देने और एक आत्मनिर्भर एवं वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय परिवेश तैयार करने में मजबूत सार्वजनिक निजी भागीदारी अहम भूमिका निभाएगी। हम अगले कुछ दिनों में एनवीएस-03 के अंतिम कक्षा में स्थापित होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।' नाविक भारत का अपना स्वतंत्र एवं एकल नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है। इसका उद्देश्य पूरे भारत और देश की सीमाओं से लगभग 1,500 किलोमीटर बाहर तक 'पोजीशन, नेविगेशन ऐंड टाइमिंग' (पीएनटी) सेवाएं उपलब्ध कराना है। निजी क्षेत्र की कंपनियों में हैदराबाद की अनंत टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (एटीएल) ने महत्त्वपूर्ण एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्पेसक्राफ्ट सब-सिस्टम की आपूर्ति करते हुए अहम भूमिका निभाई है। एएलटी ने जीएल-एलवी-एफ18 प्रक्षेपण यान के लिए 46 पैकेज उपलब्ध कराए। इनमें टेलीमेट्री, डेटा एक्विजिशन सिस्टम, नेविगेशन, गाइडेंस ऐंड कंट्रोल सिस्टम, पावर मैनेजमेंट, ट्रांसपोंडर एवं अन्य संबंधित एवियोनिक्स कार्य शामिल हैं। ये उड़ान हार्डवेयर पैकेज प्रक्षेपण यान के अलग-अलग चरणों में महत्त्वपूर्ण कार्यों में मदद करते हैं।

अनंत टेक्नॉलजीज के चेयरमैन सुब्बा राव पावुलुरी ने कहा, 'यह सफलता भारत की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और इसके अंतरिक्ष उद्योग की सामूहिक ताकत का प्रमाण है। हम आने वाले वर्षों में भारत की महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष यात्रा में योगदान देने के लिए उत्सुक हैं। हम भरोसेमंद, स्वदेशी तकनीकों के जरिये भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को मदद करने और उन्नत अंतरिक्ष प्रणाली क्षेत्र में भारत की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।' अंतरिक्ष यान के मामले में एटीएल ने एनवीएस-03 के लिए 9 सिस्टम में योगदान किया है। यह अगली पीढ़ी के नेविगेशन उपग्रह प्रणाली का तीसरा उपग्रह है जिसे आईआरएनएसएस श्रृंखला के लिए नेविगेशन सेवाओं को लगातार जारी रखने के उद्देश्य से बनाया गया है। इस उपग्रह में एक स्वदेशी परमाणु घड़ी भी लगी है। इसमें मौजूदा एल5/एस सिग्नल के अलावा एल1 सिग्नल भी शामिल है। इसका कवरेज पूरे भारत और भारतीय सीमाओं के चारों ओर 1,500 किलोमीटर के दायरे तक है।